हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 14 मार्च, 1995

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)20
कथित विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाना	(7)23
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–	
किसी व्यक्ति को सदन के समक्ष साक्षी देने के लिए बुलाने संबंधी	(7)30
प्रो० छत्रपाल सिंह के निलम्बन को रह करने संबंधी मामला उठाना	(7) 31
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग (पुनरारम्भ) तथा उस पर चर्चा	(7)34
ध्यानाकर्षण सूचनाएं/नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	(7)37
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7)40
सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र	(7)42

वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)43
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
चौधरी बंसी लाल द्वारा	(7)54
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)56
वर्ष का समय बढ़ाना	(7)75
वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)75
बैठक का समय बढ़ाना	(7)77
वर्ष 1995– 96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरा रम्भ)	(7)78

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 14 मार्च 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता को।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होगे।

***1020 Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the year in which the lining of Joshi Minor (Panipat) Hansi Branch Meter-Majra fall was done?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Lining of Joshi Minor was completed under modernisation of existing channels phase-I in the year 1982.

श्री कृष्ण लालः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हू कि क्या इस माइनर को पक्का करने के बाद इसमें पानी चला है या नही? यदि नही, तो कब तक पानी चला देंगे? पानी न मिलने के बावजूद भी किसा नो से आबियाना लिया जा रहा है। क्या उस आबियाने को वापिस किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक दिया जाएगा ? दूसरा आश्वासन मैं यह चाहता हूं कि इस माईनर में कब तक पानी चला दिया जाएगा ?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, इसमें शुरू मे कुछ दिक्कत आई थी। यह ठीक है कि इसमें कुछ दिन पानी चला और कुछ दिन नही चला, इसके कई रीजन थे। लेकिन जब पानी नहीं चला उसके लिए जो आबियाना उगाहा गया है, उसको वापिस करने का प्रावधान रूल्ज में नही है।

श्री कृष्ण लालः स्पीकर साहब, जैसे मैंने कहा है, में उसके वारे मे जानना चाहता हूं कि पानी न देने के रीजन क्या थे, जब पानी नही गया तो आबियाना क्यो नही वापिस किया जाएगा?

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि इसके कारण तो कई थे। एक तो हांसी ब्रांच से फाल का कारण था, दूसरा पानी की कमी का भी कारण था। डसके अलावा कुछ किसानों का आपस मे लिटिगेशन का कारण है। इस तरह के कई कारण थे जिस वजह से कुछ देर पानी चला और कुछ देर नहीं चना। जहां तक आबियाना वापिस करने की बात है, वह नही किया जा सकता। यदि आगे के लिए किसान को एक भी पानी न लगे तो उससे आबियाना न लिए जाने के बारे में सोचा जा सकता है। जैसे कनक को 6– 6 पानी लगते हैं, उसमें अगर एक पानी भी लग गया तो आबियाना देना पड़ेगा और अगर पानी बिलकुल ही न लगे तो उसके लित सोचा जा सकता है।

Remittance of Interest of Loan

***1025. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state the total amount of interest on loan of Cooperative Sector, if any, remitted by the Government during the years from 1-7-91 to 30-6-94 ?

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): माफ की गई राशि 5191, 33 लाख रुपये है।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम सै मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि रु 1 करोड़ 91 लाख 33 हजार रुपए इन्होंने जो माफ किए हें, इसमें इंस्टीच्यूट वाइज कितना–कितना पैसा है? यानी प्राइमरी लैड मार्गेज बैक का कितना है और दू सरे सैक्टर का कितना है 7 मन्त्री महोदया कृपया यह भी बताएं कि क्या इसमें ऐसा भी अमाउंट शामिल है जो डैड खाते में जा चुका है। तीसरा प्वाईट यह है कि ये जिलावाइज बताने की भी कृपा करें कि कितना –कितना पैसा माफ किया गया और यह भी बताएं कि प्राइमरी मार्गेज बैक का कितना हुआ और कोआप्रेटिव बैक का कितना हुआ ? क्या इन्होने अपने जिले रिवाड़ी मे ज्यादा ब्याज माफ तो नही किया, अगर हां, तो उसका क्या कारण है?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः स्पीकर साहब, इसमें ज्यादा और कम का प्रश्न नही उठता क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस जिले से लोन ले रखा है, वह नार्म्स के मुताबिक ही है। इसमें अलग अलग बैको की बात नही है, दोनों ही बैको की बात है। इक्ट्ठे ही पैसे का ब्याज माफ किया गया है। वह राशि मैंने आपको

बताई है कि 51 करोड़ 91 लाख 33 हजार रुपये है। सर्कलवाइज जितना ब्याज माफ हुआ है और जितने लोग लाभान्वित हुए हें, वह इस प्रकार है। अम्बाला में 2 करोड़ 43 लाख 66 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 17549 लाख आदमी लाभान्वित हुए। यमुनानगर मे 3 करोड़, 19 लाख 04 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 20 हजार 13 आदमी लाभान्वित हुए। नारायणगढ में 1 करोड़ 08 लाख 03 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उसमे 7506 लोग लाभान्वित हुए। कुरुक्षेत्र में 4 करोड़ 25 लाख 59 हजार रुपए व्याज माफ किया गया और उससे 28472 लोग लाभाग्वित हुए। कैथल में 2 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 16829 लोग लाभान्वित हुए। गुहला में 1 करोड़ 52 लाख 67 हजार रुपए व्याज माफ किया गया और उससे 8280 लोग लाभान्वित हुए। करनाल में 5 करोड़ 08 लाख 78 हजार रुपए व्याज माफ किया गया और उससे 27276 लोग लाभान्वित हुए। पानीपत में 3 करोड़ 77 लाख 57 हजार रुपए ब्याज माफ किय। गया और उससे 19197 लोग लाभान्वित हुए। गुड़गांव में 80 लाख 74 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 5347 लोग लाभान्वित हुए। नूह मे 61 लाख 60 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 4382 लोग लाभान्वित हुए। सोनीपत में 1 करोड़ 43 लाख 77 हजार रुपए का व्याज माफ किया गया और उससे 9 हजार 04 लोगों को फायदा हुआ। फिरोजपुर झिरका में 99 लाख 53 हजार रुपए का व्याज माफ किया गया और उससे 7688 लोगों को फायदा हुआ। रोहतक

में 1 करोड़ 29 लाख 05 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 7978 लोगो को फायदा हुआ। झज्जर मैं 96 लाख 37 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उसमे 6191 लोगों को फायदा हुआ। बहादुरगढ़ में 36 लाख 58 हजाररू रुपए ब्याज माफ किया गया और येससे 1956 लोगों को फायदा हुआ। गोहाना मे 1 करोड़ 11 काख 55 हजार रुपए का ०ब्याज माफ किया गया और उससे 6360 लोगो को फायदा हुआ। जीन्द मैं 1 करौड 08 लाख 80 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 7336 लोगों को फायदा हुआ। नरवाना में 1 करोड़ 25 लाख 40 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 7388 लोगों को फायदा हुआ। सफीदों में 68 लाख 08 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 4882 लोगों को फायदा हुआ। फरीदाबाद में 46 लाख 47 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 3601 लोगों को फायदा हुआ। पलवल मे 1 करोड़ 60 लाख 33 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 9684 लोगो को फायदा हुआ। भिवानी मे 1 करोड़ 42 लाख 23 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 12850 लोगो को फायदा हुआ। चरखी दादरी में 76 लाख 62 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 6395 लोगों को फायदा हुआ। लोहारू में 32 लाख 52 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 2744 लोगो को फायदा हुआ। महेन्द्रगढ़ में 55 लाख 42 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 4349 लोगों को. फायदा हुआ। नारनौल में 63 लाख 27 हजार रुपऐ का व्याज माफ किया गया और उससे 4213

लोगों को फायदा हुआ। हिसार में 3 करोड़ 91 लाख 16 हजार रुपए का काज माफ किया गया और उससे 26117 लोगों को फायदा हुआ। फतेहाबाद में 2 करोड़ 58 लाख 64 हजार रुपए का ब्याज मांफ किया गया और उससे 14202 लोगों को फायदा हुआ। हांसी मे 90 लाख 10 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 6864 लोगों को फायदा हुआ। सिरसा में 2 करोड़ 65 लाख 57 हजार रुपए का व्याज माफ किया गया और उससे 13239 लोगों को फायदा हुआ। रिवाड़ी में 96 लाख 46 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 8376 लोगों को फायदा हुआ। डबवाली मे 80 लाख 11 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 3822 लोगों को फायदा हुआ। इस तरह से 51 करोड़ 91 लाख 33 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 328989 लोगों को फायदा हुआ।

चौधरी सूरज भान काजलः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि लोनी जो शेयर मनी देता है जोकि 10– 15 साल तक बैक के पास रहती है और उस पर लोनी को कोई इंट्रस्ट भी नहीं दिया जाता है और न ही वह पैसा लोनी को वापिस दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः आप क्वैश्चन पूछे।

चौधरी सूरज भान काजलः स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसानों का जो डिविडैड होता है, वह 10– 10 और

20– 20 सालों तक बैको मे जमा पड़ा रहता है। उस पैसे को न तो सरकार वापस करती है और न ही उस पर किसानों को कोई व्याज आदि देती है उस पैसे का ब्याज किसानों को क्यों नहीं दिया जाता? दूसरी बात मैं इनके नोटिस मे लाना चाहूगा कि शूगर मिल्ज मे गन्ना किसानों का जो जाता है, उस की कीमत में से 50 पैसे प्रति क्विंटल किसानों का काटा जा रहा है, तो वह क्यों काटा जाता है?

श्री अध्यक्षः बस प्रश्न का इस मूल सवाल से कोई संबंध नहीं है, आप बैठ जाए।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य ने मूल सवाल पढ़ा नहीं है। इसमे यह पूछा गया है कि सहकारिता क्षेत्र में कुल कितना कर्जा माफ किया गया है।

श्री अध्यक्षः आप यह बता दो कि इनके समय में कितनों कर्जा माफ हुआ था ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः हमने इन के मुकाबले में बहुत अधिक कर्जा माफ किया है।

तारा कित प्रश्न संख्या 1005

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य को राम प्रकाश सदन में उपस्थित नहीं थे।

Releasing of amount for development works

***1051. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Finance Minister be pleased to state whether the amount of Rs. 28 lakh for the development schemes (through D.C. concerned) in each constituency during the year 1994-95 has been released by the Government, If not, the reasons thereof ?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): जी, श्रीमान जी।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्डी महोदय के नोटिस में लाते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो 20 लाख रुपये की राशि पिछले सैशन में विधायकों के क्षेत्रों में विकास के काम करने के लिए देने की घोषणा की गई थी, यह राशि अभी तक उनके पास नही पहुंची है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 11 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक यह 20 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा है? यदि अब जायेगी तो यह राशि यूटेलाईज नही हो पायेगी। मैं चाहता हूं कि जब तक यह खर्च न हो जाए, तब तक इसको लैप्स न किया जाये। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगने साल की राशि भी अप्रैल–मई–जून के नही ने तक जारी कर दी जाये ताकि समय पर विकास के कार्यों में इसको लगाया जा सके। तीसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार इस राशि से जो काम एम०एल०एज० करवाना चाहेंगे, वहां पर खर्च होगी या जो काम सरकार पहले ही कर रही है, उन्ही पर एम०एल०ए ० के अंगूठे लगवायेंगी?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जवा व में बताया कि पिछले बजट सैशन में मुख्य मन्त्री ने कहा था कि विधायको को अपने हल्के के काम करवाने के लिए 20– 20 लाख रुपये की राशि प्रत्येक क्षेत्र में दी जायेगी और यह राशि डी ०सी ० को भेज दी जाएगी। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस साल की यह राशि संबंधित जिलाधीश को भेजी जा चुकी है। विधायको को शायद कुछ कन्फ्यूजन हो कि यह राशि कैश मिलेगी या कैश लेकर काम करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यह राशि विधायको, की इच्छानुसार पब्लिक इन्ट्रैस्ट के जिन वर्क्स की लिस्ट वे तैयार करके देगे, उस पर खर्च होगी। यह स्कीम चाहे गली की हो, चाहे वाटर सप्लाई की हो या रोड्ज की हो, अगले साल की राशि ज्यों ही खर्च कर दी जायेगी, भेज दी जाएगी। यह पैसा जब तक खर्च नही होगा लैप्स नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः रामभजन जी ने पर्टिकुलरली अगले साल की राशि भेजने के बारे में पूछा है कि क्या यह राशि मई–जून के महीने तक भेज दी जायेगी?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि जो राशि भेजी गई से, जब यूटेलाईज हो जाएगी तो अगले साल की राशि भी भेज दी जाएगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगले साल भी हम इस स्कीम को चालू रखेंगे। मेरे सामने बैठे इन महानुभावों की

जनता के विकास कार्यों में तो कोई रुचि है नही। इन 16 विधायकों ने कोई स्कीम विकास की बना कर डी ०सीज० को नही भेजी कि इस विकास के काम पर पैसा खर्च होना चाहिए। हमने पैसा कलर्ड डी ०सीज० को भिजवा दिया है। स्पीकर साहब अगर इन्होंने कोई स्कीम बना कर भेजी हो तो ये बता दें। मैं इनके नाम पढ़ कर बता देता हूं। सर्वश्री जसविन्द्र सिंह पेहोवा से, अमर सिंह ढांडे गुहला से, कृष्ण लाल असन्ध से, सतबीर सिंह कादया न नौलथा से, बलवन्त सिंह हसनगढ से, दरयाव सिंह झज्जर से, जिले सिंह साल्हावास से, ओम प्रकाश चौटाला नरवाना सै, सूरजभान काजल जुलना से, सम्पत सिंह भट्टकला सै, मनीराम दड़बा कलां से। इन लोगों ने कोई स्कीम बना कर डी०सी ज० को नही भेजी।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्द्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि बजट मे वायदा किया गया था कि 20–20 लाख रुपये एम०एल०एज० को लोकल फण्ड ऐरिया से देंगे। डि– सैट्रेलार्ड्ज प्लान और लोकल फण्ड ऐरिया को मिला दिया गया है। मन्त्री जी बताए कि जो पैसा दिया जाना है, क्या वह लोकल फण्ड ऐरिया का है या डिसैट्रेलाईज स्कीम का है, ये दोनों स्की में अलग–अलग है या इनको मिला दिया गया है, अगर दोनो को. मिला दिया गया है तो फिर इस स्कीम का क्या फायदा है, यह

जनता के साथ धोखा है क्या यह पैसा डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया है?

चौधरी भजन लालः यह पैसा एम०एल०एज० के लिए रखा गया है कि वे अपने हल्के में जो भी विकास का काम चाहते है, वह उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनकी इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। हरियाणा में 90 विधायक हैं और 20– 20 जा रुपये के हिसाब से 18 करोड़ रुपये की राशि इस उद्देश्य के लिए रखी गई थी ताकि विधायक अपने हल्के के बारे में बताए कि फलां गांव में यह काम होना चाहिए परन्तु इन महानुभावो ने इस में कोई रुचि नही दिखाई। किसी भी जगह का नाम बताएं, किसी ने भी कोई स्कीम बना कर भेजी हो तो बता दें। इन्होंने अगर कोई स्कीम किसी डी०सी ० को भेजी हो तो बता दें कि इस पैसे को मेरे हल्के में इस काम पर खर्च किया जाए।

चौधरी धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वित्त मन्त्री के पक्ष में आते हुए जवाब दिया कि इस राशि को खर्च करने के लिए विधायको ने कोई स्कीम बना कर प्रस्तुत नहीं की। अध्यक्ष महोदय, दू सरे साथी भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि फरवरी–मार्च तक तो किसी भी जिले में कोई भी पैसा जा री नही किया गया तो फिर इस प्रकार की स्कीम बनाने का लाभ क्या है? मुख्य मन्त्री जी से मैं एक और जानकारी चाहूगा कि मुख्य मन्त्री साहब जी ने बादली हल्के के मातण गाव में बड़ी लम्बी–चौड़ा घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी की

घोषणा की कोई मर्यादा होती है। मुख्य मन्त्री अपनी पार्टी का नेता हो सकता है लेकिन जहां तक मुख्य मन्त्री का ताल्लुक है, वह पूरे प्रदेश का मुख्य मन्त्री होता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण सारे प्रदेश के लिए एक जैसा होना चाहिए क्योंकि मुख्य मन्त्री तो सारे प्रदेश का होता है और जो घोषणा उनके द्वारा की जाती है वह तर हाल में पूरी होनी चाहिए। मुख्य मन्त्री जी लम्बी चौड़ी घोषणा तो कर देते है, परन्तु उसको पूरा नहीं करते। जहां तक विकास की स्कीम का संबंध है, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मच्छी जी जो घोषणाएं. करते हैं क्या उनको अमली जामा भी पहनाया जाता है या केवल थोथी और असत्य घोषणाएं करते हैं? (विघ्न) स्पीकर साहब, जनवरी और फरवरी में तो कोई पैसा इन स्कीमों के लिए जारी नही हुआ है तो हम किस प्रकार की कोई स्कीम बना कर भेजें, पहरने ये पैसा जारी करें, सदन में असन्य और थोथी घोषणाएं न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि उन्होने कुल मिला कर कितनी घोषणाएं की हैं और उनमें से कितनी घोषणाओं पर कार्यवाही हुई है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो भी घोषणा की जाती है, उसको पूरी तरह सै पहले एग्जामिन किया जाता है और बाद में घोषणा की जाती है। जो घोषणा की जाती है, उसको हम पूरा करते है।

चौधरी धीरपाल सिंहः जो घोषणा ये करते हैं उसमें कह देते हैं कि पैसे की उपलब्धता पर पूरा कर देंगे। जब पैसा ही नही तो फिर एग्जामिन क्या करते हैं? 20 लाख रुपये की राशि का जहां तक ताल्लुक है, कोई पैसा नही दिया गया फिर स्कीम किस चीज के लिए भेजे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पैसा डी०सीज० के पास पहुच गया है और जब ये छुट्टियों मे अपने अपने हल्के में जाएं और पता करके आएं तथा हाउस में बताए कि पैसा पहुंचा या कि नही। (विघ्न)

Amonnt spent on desilting of J.S.B. Canal

***1088 Chaudhri Zile Singh Jakhar :** Will the Minister of Irrigation be pleased to state the amount spent on desilting of J.S.B. Canal and its minors during the period from March, 1994 to-date ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : No work of desilting was carried out on Jhajjar Sub Branch from 3/94 to date. However, the desilting work on its 13. off-taking channels/minors was carried out during 3/94 to date and a sum of Rs. 8.39 lacs has been incurred for the purpose.

चौधरी जिले सिंह जाखड़ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो मेन नहर है वह 47532 आर०डी० से लेकर टेल तक गाद से भरी पड़ी है। उससे आगे 13 नहरें है जिन पर 8 लाख 39 हजार रुपया खर्च किया

गया है और जो इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है तो क्या ये वहां से गाद निकलवा कर पानी लाने की व्यवस्था करेगे? दूसरे मदनपुर और एक और गांव हैं वहां पर पम्प हाऊस लगे हुए है। तो क्या वहां परं भी पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी?

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए इनको बताना चाहुंगा कि ये जो 13 माईनर्ज और सब माईनर्ज हैं, इनकी डी–सिल्टिग की गई है और उसमें फायदा भी हुआ है। (विघ्न) आप सुनें तो सही। यह बात ठीक है कि सिल्टिंग की वजह से वहां पर पानी की कैपसिटी कम हुई है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी कहा था। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं ओमप्रकाश बेरी के साथ नहर देख कर आया हूं। (विघ्न) लेकिन मैंने पिछले साल एक सवाल के जवाब मे कहा था कि हम इसमें डी–सिल्टिंग करवाएने। इस पर 16 करोड़ रुपए के करीब खर्चा होगा, इसमें 2– 3 साल लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, 1995– 96 में भी इसकी डी–सिल्टिग करवाने का प्रावधान है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, पम्प हाऊस के बारे में इन्होंने नही बताया है। उनमे पानी नहीं आ रहा है। वहा पर मोटरे है, बिजली है और सब कुछ है लेकिन पानी नही है।

चौधरी जगदीश नेहरा: आप कौन से पम्प हाऊस के बारे में कह रहे है?

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं तो लिफ्ट इरीगेशन वाले के बारे मे कह रहा था।

चौधरी जगदीश नेहरा: ठीक है हम उनको ठीक करवा देंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, वे खराब नही हैं। वहां पर सब कुछ है लेकिन पानी नही हैं। तो क्या ये वहां पानी लाने की कृपा करेंगे?

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, हम वहां पर डी–सिल्टिग करवा कर पानी लाने की व्यवस्था करेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड: अध्यक्ष महोदय यह पानी कब तक वहां पर पहुंचाएंगे?

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, हम यह काम अप्रैल महीने से शुरू करवाएंगे और लगातार चलेगा। इसको कम्पलीट होने में दो महीने भी लग सकते **चौधरी जिले सिंह जाखड़:** ठीक है जी।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि क्या दूसरी नहरों से भी गाद निकलवाने की इनकी कोई स्कीम है क्योकि नहरों से गाद न निकलने की वजह से पीने का पानी

भी नही पहुंच पा रहा है। मेरे गांव मीठी मे तो दस अक्तूबर को ही पानी गया था और उसके बाद से आज तक भी वहां पानी नहीं गया। यह पानी वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि नहरें गाद से भरी हुई हैं। बजट में तो इन्होंने नहरों में गाद निकालने के लिए कोई पैसा रखा नहीं है तो क्या मंत्री जी की नहरों से गाद निकालने की कोई स्कीम है ?

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, ऐसी बात नही है कि बजट में प्रावधान नही है बजट में तो इस काम के लिए प्रावधान है। प्लान और नान प्लान का बजट होता है और नान प्लान में इस तरह के काम होते हैं। इनको जहां जहां भी दिक्कत है, वहां हम गाद निकलवाकर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री ओमप्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि हम डी–सिल्टिंग कराएंगे। क्या यह बात इनके नालेज में है कि भाखड़ा बाकरा हैड से डाउन स्ट्रीम जे०एस०बी० प्रैक्टिकल रूप मे बन्द हो चुकी है और जितने गांवों में इससे पानी आता था, उनमें पानी देने का कोई इन्तजाम नही किया जा रहा है। स्पीकर सर, मैं मन्त्री जी के साथ गया था और हमने जे०एस०बी० का इन्सपैक्शन भी किया था। सर, वहां नहर के बीच में कीकर के बड़े–बड़े पेड़ू खड़े हुए है इसलिए आगे पानी जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जे०एस०बी०, जे०एल०एन० के साथ–साथ जाती है। तों स्पीकर मर, मैं मन्त्री जी में जानना चाहूंगा कि ये कब तक जे०एस०बी० की डी–सिल्टिग और

लाईनिग करायेंगे स्पीकर सर, उनमें पानी नही छोड़ा जाता। जो जे०एस०बी० से इफैक्टिड गांव है, क्या सरकार उन गांवों को पानी देने के लिए जे०एल०एन० से पानी का प्रावधान कराएगी? इसके अलावा, दूसरा मेरा सवाल यह है कि किसानों को पानी तो मिल नहीं रहा है और सरकार उन से आबियाना कर–बार वसूल कर रही है तो, क्या मन्त्री जी इस बारे में कोई जाव कराएंगे? स्पीकर सर, मैं चौलेंज करसे है कि इसके लिए हाऊस की एक कमेटी बनायी जाए और वह कमेटी वहां पर जाकर इस बात को देख ले कि प्रैक्टिकल रूप से इन गांवों को पानी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? सरकार जानबूझ कर इन इलाको के साथ भेदभाव कर रही है, ज्यादती कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहे तो इस बारेमें बेशक हाउस की एक कमेटी बना दे।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, जब ये मेरे साथ वहां पर इसका इसपैक्शन करने के लिए गए थे तो उस समय झज्जर सब ब्रांच में पानी चल रहा था, ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं चल रहा था। हम इसीलिए ही वहां पर गए थे कि उसका मौके पर जाकर इन्सपैक्शन किया जाए। इसलिए ही उसमें डी–सिल्टिंग करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इंस्पैक्शन के बाद मैंनै स्वीकार किया कि वहां पर दिक्कत है।

श्री ओम प्रकाश बेरीः स्पीकर सर, मन्त्री जी यह बात बता दें कि आज उसमें पानी बन्द है या नहीं। और अगर मेरी बात

झुठ है तो में इस विधान सभा से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं (विघ्न) यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं कि पानी लोगों को मिलता है।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, ये इतना कठोर कदम न उठाएं कि इस प्वायंट पर रिजाइन करें। इसके लिए तो और मौके आएंगे। लेकिन अब मैं नही कह सकता कि वहां पर पानी चल रहा है या नही क्योंकि वहां पानी रोटेशन से चलता है। आज पानी है या नहीं मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसमें पानी टर्न के हिसाब से चल रहा है। इन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां पर पानी नहीं चलता है तो वहां पर जे०एल०एन० से पानी दिया जाना चाहिए। स्पीकर सर, इनको भी पता है कि उसमें क्या प्राब्लम है, एक तरफ तो वहां जे ०एल०एन० जा रही है और लैफ्ट साईड में उनके जे० एस० बी ० है और जे० एल० एन० के बीच मे से भी जे ० एस० बी ० से इधर मोगे हैं मौर जे० एल० एन० सभी जे ० एस० बी ० के साईड में भोगे हैं। जहां–जहां भी पानी की दिक्कत आयी वहां पर लगातार पानी के मोगे जे०एल०एन० से ही दिए गए। लेकिन इनको जहां–जहां भी पानी की दिक्कत है, वहां –वहां हम उसको हल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखडः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा कि जे ०एल०एन० में मोगे दे दिए गए हैं लेकिन सर, कोई भी मोगा नही दिया गया। जहां तक आबियाना का सवाल है तो मातनहेल, मुनसा मादल, अकेड़ी मदनपुर के लोगों का सीपेज की

वजह से काफी आबियाना आता है। पटवारी उनकी फसल को देखकर ही गिरदावरी करके चला जाता है और उन पर आबियाना लगा देता है।

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर एक भी पानी किसानों ने लगा लिया तो सरकार आबियाना लेने की हकदार हो गयी। तो हो सकता है कि इन गांवों में पानी न लगा हो, लेकिन यदि वहां बिल्कुल भी पानी नही लगा है तो उसके लिए सरकार एग्जामिन करवा कर रिलीफ देने की कोशिश करेगी।

Mr. Speaker : The Minister will visit the place and sort out the problem.

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, इसको हम मौके पर जाकर देखेंगे और अगर कोई दिक्कत है तो उसको हल करने की सरकार कोशिश करेगी।

Consolidation

***1098. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the villages of Bahadurgarh and Jhajjar Tehsils of District Rohtak in which consolidation of land holding has not been done so far, togetherwith the reasons thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): विभिन्न न्यायालयो में मुकदमेबाजी के कारण बहादुरगढ तहसील के छः गांवों नामत

छारा, माण्डोठी, बाढसा असोदा टोडरान बराही, कुलताना तथा झज्जर तहसील के चार गांव नामतः किलोई खेड़ी, होशदारपुर मोहम्मदपुर माजरा, डीघल, जिला रोहतक के चकबन्दी कार्य में देरी हुई है, मुकदमेबाजी की वजह से।

10.00 बजे

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानकारी चाहूगा कि जो दस गांव दर्शाए हैं, क्या इनमें से सभी गांवों के मामले कोर्ट मे गए हुए है या कितने ऐसे गांव हैं जिनके मामले कोर्ट में नहीं हैं, जिन गांवों के मामले कोर्ट में नही गए उन पर अगली कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जाएगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस समय इन दस गांवों में से किसी गांव का मामला कोर्ट मे नही है। 10 में से 8 पर चकबंदी इस्तेमाल का काम शुरू हो गया है बाकी दो गांव रहते हैं, कोशिश करेंगे कि साल सवा साल मे सभी गांवों में इस्तेमाल हो जाए।

Providing of more Stand-Posts

***1111 Shri Ram Kumar Katwal :**Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more stand posts to supply drinking water in Alewa ; and

(b) if so, the time by which aforesaid stand-posts are likely to be provided ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी)

(क) जी नहीं, स्वीकृत नार्मज 120 स्टैण्ड पोस्टों के विरुद्ध पहले ही 138 स्टैण्ड पोस्ट लगे हुए हैं।

(ख) उपरोक्त ''क' ' अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री राम कुमार कटवालः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि 1978 में चौधरी देवी लाल की सरकार ने (विध्न).....

श्री अध्यक्षः कटवाल साहब, आप क्वैशचन पूछिए।

श्री राम कुमार कटवालः स्पीकर कर सर, उस वक्त 120 स्टैण्ड पोस्ट लगे हूप, थे और अब 18 स्टैण्ड पोस्ट और बड़े हैं लेकिन उस वक्त अलेवा की आबादी 6,100 थी, अब यह गांव 21 हजार की आबादी वाला हो गया है।

श्री अध्यक्षः कटवाल साहब, 21 हजार तो किसी गांव की आबादी नहीं है।

श्रीमती शान्ति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, नार्म्ज के अनुसार 120 स्टैण्ड पोस्ट ठीक लगे थे, फिर भी सरकार ने 18 स्टैण्ड पोस्ट और लगाए और इनकी संख्या बढ़कर 138 हो गई।

नार्म्ज के अनुसार 100 की जनसंख्या पर एक स्टैण्ड पोस्ट लगता है। 18 ज्यादा है, यह बात आपने भी स्वीकारी है। जहां तक जनसंख्या का संबंध है, अलेवा में उस वक्त 11, 148 जनसंख्या थी और अब 12 हजार 40 है। यदि माननीय सदस्य का 1 –2 स्टैण्ड पोस्ट और लगाए जाने में इंट्रैस्ट है तो कोई बड़ी, बात नही है, हम लगवा देगे।

श्री राम कुमार कटवालः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है। इस बारे में हाउस की एक कमेटी गठित कराई जाए। 120 + 18 = 138 स्टैण्ड पोस्ट हैं, ये केबल आप ने पढकर सुनाया है मन्त्री महोदया, आबादी भी आज 21 हजार से कम नही है।

श्रीमती शान्ति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, मैं इनके बता देना चाहती हूं कि मैं जो आकड़े बता रही हूं, यह तथ्यों पर आधारित हैं। इन आकड़ों को ये चौलेन्ज नहीं कर सकते। ये जो आकड़े बता रहे हैं, ये अपने अनुमान से बता रहे है। इनकी पिछली सरकार के सारे कारनामों से जनता पूरी तरह से अवगत है लेकिन मैं उन कारनामों को यह पर रखना नहीं चाहती। मैं तो यह कहूंगी कि स्वच्छ पानी जनता को देने के लिये हमरि सरकार की पू री जिम्मेवारी है और हम दे रहे हैं। फिर भी मैं इनको यह क्लीयर करना चाहती हूं और जहां कहीं भी ये स्टैण्ड पोस्ट चाहते हैं, उनके नाम ये लिखकर हमें दे दें। जहां जहां ये अनुभव करते

हैं कि फलां फलां जगहों पर इनकी जरूरत है, वह हम लगवा देंगे।

Generation of Electricity in the State

***1147. Prof. Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government for the generation of electricity in the State with the collaboration of any company of Israel ; and

(b) if so, the details thereof ?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां श्रीमान् जी।

(ख) 700 मैगावाट यमुनानगर थर्मल परियोजना का निर्माण एक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे० बी ० सी ०) जिसमें हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड तथा इजराईल की आइजनवर्ग ग्रुप आफ कम्पनीज के युनाइटेड डिवैल्प– मैन्ट इंक्रोपोरेटिड शामिल हैं, के माध्यम से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये एक समझौते पर दोनों भागीदारों के मध्य 25 जनवरी, 1995 को हस्ताक्षर हुये हैं।

वित्तीय समाप्ति (क्लोजिंग) 6 मास कैं अन्दर–अन्दर होनी है।

प्रो० राम विलास शर्माः स्पीकर सर, इन्होंने इजराइल की एक कम्पनी आइजनवर्ग ग्रुप आफ कम्पनीज के साथ 25 जनवरी, 1995 को एक समझौंते पर हस्ताक्षर किये। पहली बात तो यह है कि इनको वह ऐग्रीमैंट सदन की पटल पर रखना चाहिये था कि कौन सी शर्तों पर वह् कम्पनी बिजली पैदा करेगी और वह बिजली हरियाणा के लोगों को किस भाव पड़ेगी, कौन सी शर्तो पर वे बिजली देंगे और क्या उसमें 700 मैगावाट का यमुनानगर का थर्मल प्लांट भी शामिल है या नही? क्या इस तरह का थर्मल प्लांट लगाने की सरकार की हिसार में भी कोई योजना विचाराधीन है? यह बात ठीक है कि बिजली के अकाल को देखते हुए हरियाणा सरकार चितित है। तो मैं इन से यह जानना चाहता हूं कि बिजली जन– रेशन के मामले में सरकार ने कोई विज्ञापन किया, किसी कम्पनी को इंवाइट किया? क्या ऐसी कोई कम्पनी ने इनको लिखित रूप में कोई आफर दी जोकि इनको सस्ते रेट्स पर बिजली जनरेट करके दे सकें, जरा पोजीशन क्लीयर कर दे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर,. इजराईल की कम्पनी को लेकर विपक्ष के भाई बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा हैं। आपको स्पीकर सर, यह पता है कि हरियाणा प्रान्त में ही नही बल्कि सारे देश ' में आज बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार के, हरियाणा प्रान्त के मैं चार–पांच अनुमान दूंगा। 1989–90 मे बिजली की जो खपत थी, वह आज 1994–95 में कहीं ज्यादा है। बिजली एक ऐसी

चीज है जोकि फोरी तौर पर पैदा नही का जा सकती। बढ़ी हुई लोगों की मांग को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि आज जो हरियाणा प्रांत इस माम् ले में नम्बर दो पर है, इसे इसी नम्बर पर ही कायम रखा जाए और हमरि'।. तो यह कोशिश होगी कि हरियाणा प्रांत को इस मामले में नम्बर वन पर लाया जाए। इसलिये सरकार का चिंतित होना जरूरी है कि इस प्रान्त में बिजली की खपत और बढ़ाई जाए और प्रान्त में बिजली की सप्लाई पूरी प्रदान की जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हुमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इजराईल की कम्पनी आइजनवर्ग ग्रुप से 1994 में एम० ओ० यू ० साईन किया जोकि बड़ी ही नामी–कामी कम्पनी है। उस एम० ओ० यू ० को अब आगे बढ़ावा दिया गया है और 25–1 –9 5 को एक एग्रीमैंट साइन किया गया, जसने अभी फाइनल शेप लेनी है। जो पावर परचेज एग्रीमैंट होगा, मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हू कि वह आपके सामने लाया जाएगा। जो गवर्नमैंट आफ इंडिया के गाइड लाइन्ज है, उससे रत्ती भर भी इधर–उधर नही जाएंगे। जहां तक अब तक की क्लाज पर सहमति की बात बताने का सवाल है, ऐसे कामों में एक क्लाज होता है जिसको कमर्शियल एंड कन्फीडैशियल क्लाज कहते हैं। उससे हम पाबन्द हैं, ज्यों ही पी० पी ० ए० साइन होगा, उसको हाउस के सामने लाया जाएगा। फिर भइ। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो नार्मज तय किए हैं, उससे एक इंच भी इधर उधर नही होगा। दूसरी बात इन्होंने हिसार में दूसरी जगह पर प्रोजैक्ट लगाने की पूछी कि उसके लए

कोई कम्पनी आगे आई है या नहीं। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि कम्पीटीटिव बिडिंग का एक डाकुमैंट तैयार हो रहा है। बहुत जल्द हम अखबारों के द्वारा गलोबल टैडर फलोट करेंगे और जो भी आफर आएगी उससे भी हाउस को अवगत कराया जाएगा।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आइजनवर्ग की इस कम्पनी से समझौता करने से पूर्व क्या गलोबल टैंडर इनवाइट किए गए थे अगर किए गए थे तो देश की किस–किम कम्पनी ने टसमें पार्टिसिपेट किया और विदेश की कौन कौन सी कम्पनियों ने पार्टिसिपेट किया? इसके अलावा, यह भी बनाए कि इसकी टोरल कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कम्पीटीटिव बिडिंग के लिए जो गर्वामैंट आफ इडिंया ने गाइड लाइन्ज तय की है, वे जनवरी, 1995 में की हैं। इसलिए उमसे पहले कम्पीटीटिव बिडिंग करने का कोई सवाल नही उठता। पहले केवल हरियाणा ने ही नही बल्कि हिन्दुस्तान के कई प्रदेशो जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान हैं, इन्होंने भी इस प्रकार के एम० ओ० यू ० साइन किए हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कादयान साहब के सवाल के जवाब में मन्त्री जी ने बताया कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने फारेन कम्पनियों को थर्मल कीं कंस्ट्रक्शान करने के लिए अभी

परमिशन दी है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फारेन कम्पनियों को इस वक्त इजाजत दी गई लेकिन हिन्दुस्तान में और भी कम्पनियां है, उनको आपने टेंडर जारी करने की इजाजत क्यों नही दी? ऐसा करने से हिन्दुस्तान की कम्पनियां भी इनके निर्माण में आ सकती थी ऐसा आपने क्यों नहीं किया? स्पीकर साहब, अब तो आपने इनका गलोबल टैडंर भरने की इजाजत दे दी है, लेकिन यह भी हो सकता है उनसे सस्ते रेट पर और कम्पनियां इसको बना सकती हों? तो क्या अब आप दूसरी कम्पनियो से गलोबल टैडर इनवाइट करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक यमुनानगर का सवाल है उसका एग्रीमैट तो आइजनवर्ग कम्पनी के साथ फाइनल है। उसके वारे में बातें चल रहा है और करीब करीब वहीं पर फाइनल हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि हिसार के लिए हम ओपन बिडिग करेंगे। उसके लिए सभी कम्पनियों को टैंडर देने की इजाजत होगी। जहां तक सम्पत सिंह जी ने यह कहा कि इंडियन कम्पनीज को भी इनवाइट करे तो इसमें इंडियन कम्पनीज का सवाल नहीं है और न उनको कोई परमिशन देने की बात है। मैने यह कहा है कि ओपन बिडिंग के लिए भारत सरकर ने अब गाइडलाइन्ज दी हैं कि आप गलोबल टैडंर कर सकते है।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि जिन कम्पनी के साथ इन्होंने समझौता किया है और वह कम्पनी 700 मैगावाट बिजली पैदा

करेगी। वह इमे किस भाव में देगी ? इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहना हूं कि जैसे बम्बई मैं टाटा कम्पनी सस्ती बिजली जनरेट करती है, उसी तरह की हिन्दुस्तान की किसी एक कम्पनी ने क्या आपको बिजली जनरेट करने की औफर दी थी? वह कम्पनी आपको टाटा कम्पनी से भी सस्ती बिजली जनरेट करके दे सकती है। इस बारे में मैं मंत्री जी से कैटेगोरीकली जानना चाहता हूं ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बड़ी तफसील के साथ सारी बातें बताई हैं। अगर इनको कोई काम बिगाड़ना हो तो चाहे ये कुछ भी कह दें। अध्यक्ष महोदय, उस कम्पनी के साथ भारत सरकार की एन० टी ० पी ० सी ० की 5–6 मीटिंगें हो चुकी थीं। उस कम्पनी के साथ हमने जो एम० ओ० यू० साइन किया उस कम्पनी ने एन० टी ० पी० सी ० को कहा था आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा ओर हम इतना पैसा लगाएंगे यानि 76 परसैटं पैसा हम लगाएंगे और 25 परसैट पैसा आप लगाएंगे। लेकिन उन्होंने यानी एम० टी ० पी ० सी ० ने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वह बहुत अच्छी कम्पनी है। उसने चाइना मे 3 हजार मेगावाट के प्रोजैक्ट लगाये हैं। वह कम्पनी और कंट्रीज में भी प्राजैक्ट लगाने जा रही है। वह कम्पनी हमारे यहां प्रोजैक्ट लगाने के लिए तैयार है। हम उस कम्पनी को यहां पर प्रोजैक्ट लगाने के लिए बड़ी मुश्किल से लाये हैं। हम इस काम के

पीछे तीन साल से लगे हुए हैं। हमने उस कम्पनी के साथ जो एम० ओ० यू ० साइन किया है वह यह किया है कि अगर 68.5 परसैंट लोड फैक्टर होगा तो बिजली का रेट होगा फी–यूनिट 1 रुपया 92 पैसे। अगर लोड फैक्टर 75 परसैट होगा तो बिजली का रेट होगा 1 रुपया 80 पैसे। अगर लोड फैक्टर 85 परसैंट होगा तो बिजली का रेट होगा 1 रुपया 60 पैसे और अगर लोड फैक्टर 90 या 95 परसैंट हो जाएगा तो बिजली का रेट 1 रुपया 50 या 55 पैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, हमने 68.5 परसैटं लोड फैक्टर पर 1 रुपया 92 पैसे बिजली के रेट पर एग्रीमैट साइन किया है। अब तक किसी भी जगह पर इससे कम रेट में कोई एग्री मैट साइन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश, उडीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान कहीं पर भी इससे कम रेट पर कोई एम० ओ० यू० साइन नही किया गया है। हमने यह सब कुछ भारत सरकार की इजाजत से किया है। अभी एग्रीमेंट हुआ है और अमी बात हमारे हाथ में है अगर किसी बात में कोई मतभेद हुआ तो हम उनसे कहेंगे कि नहीं आप इस रेट पर हमें बिजली दे। हम यह चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे यहां बिजली का प्रोजैक्ट लग जाए। मेरे सामने बैठे भाईयों की सरकार ने अपने चार साल के समय में एक भी प्रोजैक्ट नही लगाया। इनकी मेहरबानो से हमारे प्रदेश में बिजली का बहुत बुरा हाल हो गया। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से यह मामला बिगड़ जाए और यह प्रोजैक्ट हरियाणा में न लगे। इम बारे में जो भी एग्रीमैंट होगा वह सदन के सामने रखेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को क्या पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है ? हरियाणा के अन्दर 85 से कम पावर फैक्टर आता ही नहीं, जो ये कह रहे है कि 1.60 रुपये बिजली पड़ेगी, यह सरासर .... बोल रहे हैं। इतनी बिजली सस्ती हरियाणा में आ नही सकती, ये सदन को गुमराह कर रहे है।

श्री अध्यक्षः इस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने माना है कि 26 जनवरी, 1995 को दो भागीदारों के एक एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर हुए है। मैं जानना चाहता कि इनका यह जो एग्रीमैंट हुआ है, क्या उसको सदन की पटल पर रखेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि एम० ओ० यू० का टाईम एक्सपायर हो रहा था, इसलिए उसको बांधे रखने के लिए वह एग्रीमेट किया गया है। मेन एग्रीमेंट तो अभी होना है और जो एग्रीमैंट हुआ है, वह भी इस होने वाले मेन एग्रीमेंट का एक पार्ट होगा। ज्यों ही मो एग्री मैट हो जायेगा, उसको हाउस में रख दिया जायेगा।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जब एक एम० ओ० यू ० पर दो पार्टियों के हस्ताक्षर हो गए तो वह पब्लिक डाकूमैट बन जाता है। इसलिए. मैं चाहता हु किं उसको सदन की टेबल पर आना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने हाउस में बताया है कि एक एम ० ओ० यू ० पर जो दस्तखत हुए हैं, वह अभी काफिडेंशियल हुँ क्योंकि यह एक कमर्शियल एग्रीमैट है। हम कुछ बातों को जनता को बताने के लिए पाबंद है। यह सभी क पता है कि कमर्शियल डील में कुछ ऐसा पाबदिया होती है जो इस स्टेज पर नही बताई जा सकती। हां, मै सदन को यह आश्वासन देता हूं कि ज्यो ही हमारा फाईनल एग्रीमैट हो जायेगा, तो वह एग्रो मैट सदन की पटल पर रख दिया जायेगा। मैं यह भी बताना चाहता हू कि हमारा यह एग्री मैट, भारत सरकार की जो गाइडलाईपंज– है, उन्ही पर आधारित होगा। इसमें प्रात को किसी' प्रकार का कोई नुक्सान नही होने दिया जायेगा और हरियाणा के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे।

श्री बंसी लालः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस एम० ओ० यू० पर इनके दस्तखत हुए है, उसको सदन की पटल की पर रख से क्या हरियाणा के हित सुरक्षित नही रहेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह हरियाणा के हित तो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हम इस पर पाबंद हैं कि जब तक फाईनल एग्रीमैंट नही हो जाता, तब तक किसी तरफ से ऐसी बात न हो जाये जो एक दूसरे के हित के खिलाफ हो। जैसा मैंने बताया है कि यह मामला फाईनल स्टेज पर है, इसलिए उस एम० ओ० यू ० को इन समय पब्लिक डाकूमेंट के आधार पर हाउस में रखना उचित नहीं होगा।

Repair of Roads of Gulila Sub-Division

***1114. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads of Guhla Sub-Division of district Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the roads as referred to in part (a) above are likely to be repaired ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह):

(क) गुहला उपमण्डल की सड्कों की (मरम्मत) पैच कार्य दारा कर दी गई है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रश्न ही नही उठता।

श्री अमर सिंह ढांडे: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुहला उपमण्डल की सड्कों पर कुल कितना पैसा खर्च हुआ, जो पैसा खर्च होना था, वह वहां खर्च न होकर कहां पर खर्च हुआ है, क्योंकि गुहला उपमण्डल में सड़को की रिपेयर बिल्कुल भी नही हुई?

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, गुहला उप–मण्डल में 328.29 किलोमीटर की रोड्ज है। इन सभी पर पैच वर्क पूरा हो चुका है जिस पर 6.79 लाख रुपये खर्च हुआ है। 30.6 कि ० मी

० पर रिनीबल कोट भी हो चुका है जिस पर 10 लाख 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं। जनवरी 1995 तक 17.15 लाख रुपया खर्च किया गया।

श्री अमर सिंह ढांडे: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई स्पैशल टीम बना कर इसकी जांच करवाएंगे जो जांच करे कि यह पैसा कहां पर खर्च हुआ तुं। क्योंकि गुहला सर्कल के बारे में मैं कहता हूं कि आन तक कोई कार्य नही हुआ है। .... है इसलिए स्पैशल टीम बना कर उनकी चौकिंग करवाएं, वहां पर तो आदमी पैदल भी सड़क पर नही चल सकता बै?

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि आनरेबल मैम्बर अपने हल्के में नही रहते हैं, गुहला में रिपेयर वर्क पर 47.88 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मैं आनरेबल मैम्बर की तसल्ली के लिए बताना चाहता हूं कि 1992—93 में 7. 64 लाख रुपये सिर्फ पैच वर्क पर खर्च किए गए थे और 1993—94 जनवरी 1995 तक 6.79 लाख रुपये रिपेयर पर खर्च हुआ है। 3005 किलोमीटर लम्बी रोड पर 10.3 रु लाख खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा में लगभग 3,135 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 1,587 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्ज, और लिंक रोडज या एप्रोच रोडज 16,857 किलोमीटर हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि हरियाणा मे पैच अभियान चलाया गया है और

इसके तहत सारी रोडज की पैच वर्क (मुरम्मत) की गई है। पिछले साल 3,131 किलोमीटर रोडज टूटी थी। आनरेबल मैम्बर इस बात को मानेगे कि हर साल फल्ड आता है। गुहला घग्गर नदी के किनारे पर पड़ता है, घग्गर में फल्ड आने से काफी नुकसान होता है और रोडज भी टूटती हैं। हर फल्ड के बाद रोडज की मुरम्मत की जाती है और पैच वर्क भी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में रोडज का पैच वर्क करवा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह बात बार–वार आती रही है कि सड़क पर कोई टाकी नही लगी। हमने टाकी भी लगवा दी है ओर ओवर कोट भी बहुत सारी जगह पहना दिये हैं। (हंसी)

Shortage of Medicines in Government Hospitals in the State

***1107. Sathi Lehri Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is an acute shortage of medicines and also non availability of certain life saving drugs in Government Hospitals/Dispensaries in the State at present ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to provide adequate stock of essential medicines in Government Hospitals/ Dispensaries ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (बहिन करतार देवी):

(क) और (ख) जीवन रक्षक दवाईयां पर्याप्त माता में उपलब्ध है। फिर भी उपलब्ध धन राशि से दवाईयों की कुल मांग को पूरा किया जाना कठिन है।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हर साल मी ० एच० साईज० और पी ० एच० सीज० के लिए वर्ष के आधार पर या मन्थ वाईज दवाईयों का कोई नार्म निर्धारित है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई स्पैशल और सरपराईज चौकिंग कही पर की गई है कि वहा पर दवाईया है या नही है और जो दवाईया वहा दी जानी होती हैं, वे वहा पर पहुंचती है या नहीं पहुंचतीय अगर नही पहुंचती तो क्या कोई ऐसा मामला इनके नोटिस में आया है, यदि आया है तो उसके बारे मे इन्हेने क्या कार्यवाही की है?

बहिन करतार देवीः स्पीकर सर, जहा तक सब–सैटरज और प्राईमरी हैल्थ सैटरज मे दवाईयों के नार्म का ताल्लुक है, इनके लिए दवाईयों का महीने का तो नही लेकिन साल का बजट रखा जाता है। नार्म के मुताबिक सब–सैटर पर 2 हजार रुपये, प्राईमरी हैल्थ सैंटर में 10 हजार रुपये और सी ० एच० सी ० में 50 हजार रुपये की दवाईयों का नार्म है लेकिन होस्पीटल्ज के लिए कोई नार्म फिक्स नही है, वहां पर धन की उपलब्धता को देखते हुए दवाईयां प्रदान की जाती हैं। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, एक बार नही अनेकों बार हम जा–जा कर देखते हैं कि डांक्टरों का व्यवहार मरीजों के साथ ठीक है या नही जो दवाईयां उपलब्ध है

वे लोगो को मिल रही हैं या नही, बच्चों की देखभाल, जो उनको टीके लगाए जाते है और अनेक सुविधाएं जो उनको दी जाती' है, उनका अभाव तो नही है ? अगर कोई कमी हो तो हम उचित कार्य– चाही करते है।

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Ditch Drain

***1150. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for irrigation be pleased to refer to starred question No.530 which was replied on 5.3.93 and to state that the time by which the construction work of Ditch Drain along J. L. N. Feeder in Rohtak district is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : In reply to S.Q.No. 530 which was replied on 5.3.93, it was stated that the work will be completed on the availability of funds. Work will be started & it will be completed in phases.

High Schools

***1143 Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(c) the number of High Schools of tehsil Hathin, Taoru, Nuh and Ferozepur jhirka Sub-Divisions togetherwith their location ;and

(d) the number of schools out of those as referred to in part (a) above are without Headmasters at present ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(ए)

तहसील	उप–मण्डल	उच्च–वि० की संख्या		स्थिति
1	2	3		4
हथीन	पलवल	13	1	राजकीय उच्च विद्यालय कोडल
			2	रा० उ० वि० गहलब
			3	रा० उ० वि० गुरेकसर
			4	रा० उ० वि० मदनाक
			5	रा० उ० वि० अलीमेव
			6	रा० उ० वि० मानपुर

			7	रा० उ० वि० सेलवी
			8	रा० उ० वि० घरोट
			9	रा० उ० वि० अटावर
			10	रा० उ० वि० (क ०) बहीन
			11	रा० उ० वि० कलसाड़ा
			12	रा० उ० वि० छैसा
			13	रा० उ० वि० हुडीथल
नूह	नूह	12	1	रा० उ० वि० अकेड़ा
			2	रा० उ० वि० छपेरा
			3	रा० उ० वि० फिरोजपुर नमक
			4	रा० उ० वि० कुरथाला
			5	रा० उर० वि० खेड़ा

				खलीलपुर
			6	रा ० उ० वि० कैराका
			7	रा० उ० वि० मैलाब
			8	रा० उ० वि० उजीना
			9	रा० उ० वि० नूह
			10	रा० उ० वि० मेवली
			11	रा० उ० वि० घसेरा
			12	रा ० उ० वि० इन्द्री
तावडू	नूह	8	1	रा० उ० वि० मोहम्मदपुर अहीर
			2	रा० उ० वि० पादीनी.
			3	रा० उ० वि० राठीवास
			4	रा० उ० वि० सुंद
			5	रा० क०उ० वि० तावडू

			6	रा० उ० वि० कलवारी
			7	रा० उ० वि० बगांकी
			8	रा० उ० वि० जौरासी
फिरोजपुर झिरका	फिरोजपुर झिरका	29	1	रा० उ० वि० भादस
			2	रा० उ० वि० वजीदपुर
			3	रा ० उ० वि० बिच्चौर
			4	रा० उ० वि० बिवां
			5	रा० उ० वि० बटेर
			6	रा० उ० वि० बदरपुर
			7	रा० उ० वि० ढुढोली
			8	रा० उ० वि० डोहा
			9	रा० उ० वि० जेटाना
			10	रा० उ० वि० लोहिंगा

				कलां
			11	रा० उ० वि० मण्डीखेड़ी
			12	रा० उ० वि० माहू
			13	रा० उ० वि० नाई
			14	रा० उ० वि० नगीना
			15	रा० उ० वि० औथा
			16	रा० उ० वि० सिंगार
			17	रा० उ० वि० सिंगलहेडी
			18	रा० उ० वि० सरौसी
			19	रा० उ० वि० शिकरावा
			20	रा० उ० वि ० उमरा
			21	रा क ० उ० वि० फिरोजपुर झिरका
			22	रा० क०उ० वि०

				नगीना
			23	रा० उ० वि० गगवानी
			24	या० उ० वि० अगौन्ध
			25	रा० उ० वि० बिसर
			26	रा० उ० वि० जमालगढ़
			27	रा० उ० वि० रावली
			28	रा० उ० वि० साकरस
			29	रा० क० उ० वि० पिनगवा

(बी) उन स्कलों की संख्या निम्न अनुसार है, जहा मुख्याध्यापक नहीं हैं।

तहसील/ उपमंडल	बिना मुख्याध्यापकों के स्कूलो की संख्या
हथीन	10

नूह	10
तावडू	6
फिरोजपुर झिरका	23

कथित विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाना

Prof Sampat Singh : Mr. Speaker Sir, today morning we have given a notice of breach of privilege under Rule 261 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly against Shri Bhajan Lal, Chief Minister for making false and wrong statement on the floor of the House on the 10th March, 1995 that Mr. Om Parkash Chautala had demanded a bribe from Shri C.L. स्पीकर साहब, हुमने डाक्यूमैंटरी प्रूफ भी उसमें लगाया है। मिस्टर सी ० एल० वर्मा ने ट्रिब्यून के जरनलिस्ट को एक फैक्स मैसिज करवाया है। उसकी एक कापी हमने आपको भी सबमिट की है। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं बाहर गया हुआ था और बाहर से आने के बाद मैंने इंगलिश ट्रिब्यून में खबर पढ़ी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पांच करोड़ रुपए मेरी कम्पनी से उस काम को दोबारा से शुरू करने के लिए मांगे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऊपर उन्होंने लिखा है कि हाऊस के अन्दर बिना तथ्यों के दी हुई स्टेटमैंट विल्कुल असत्य है और ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे से कभी भी कोई पैसा नही मांगो है न ही मेरी कम्पनी से मांगा है और न ही मैंने उनको कोई पैसा दिया है। अध्यक्ष महोदय, उसने

यह भी लिखा है कि हाऊस में यह सब कहने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब मुख्यामंत्री जी गवर्नर ऐड्रस पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल असत्य हैं, फाल्स है और मिथ्या बात है। लेकिन मुख्यमत्री जी ने फिर भी बार–बार इस हाऊस की गरिमा को चोट मारने की कोशिश की और अपनी बात पर डटे रहे। इन्होंने हाऊस को उस दिन फाल्स स्टेटमैंट देकर मिस–लीड किया है। यह मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रिवलेज मोशन का केस है। इससे हाऊस के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। चाहे कोई भी मैम्बर बोले, उसको सत्य बोलना चाहिए। किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए, पोलिटिकल फायदा उठाने के लिए हाऊस के अन्दर असत्य बोले तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप रिपीट न करे।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सबमिशन है कि आप हमारे प्रिवलेज मोशन के नोटिस को एडमिट करे ताकि यह केस प्रिवलेज कमेटी को जाए जिससे तथ्य सामने आएंगे'। उस' वक्त मिस्टर सी ० एल० वर्मा को बुलाया जाए, डाक्यूमेंटरी प्रूफ भी आएं, उनकी भी जांच कर लें। उसके बाद कमेटी अपने रूल्ज के हिसाब से उस पर गौर करे और हाऊस में बताएं। मेरी आप से दोबारा पुरजोर अपील है कि यह जो इन्होंने ढंग अपनाया था, वह गलत था और हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अब मुझे भी कहना पड़ेगा। मैं एक फाईल के थोड़े से सारांश पढ़ देता हूं। उससे सारा हाऊस, गैलरी में बैठे हु महानुभाव और प्रैस के महानुभाव भो महसूस करेंगे कि इस तरह का वातावरण क्यो बना?

अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमैंट 23 मार्च, 1987 दूंको हुआ। उससे पहले मैं मुख्यमंत्री था फिर श्री बसी लाल जी डग गए थे। तो इनके साथ एग्रीमैट कान्टीनैटल कंस्ट्रक्शन वी ० टी ० लिमेटिंड, यू ० के० के ज्वायंट बैन्चर के साथ हुआ था जिसके अनुसार 31– 10– 90 तक यह काम पूरा होना था। काम यह था कि फोर–लैनिग वाली सड़क करनाल तक बनकर तैयार होनी थी। मार्च 1987 में एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर होने के पश्चात, 1988 के अन्त तक कोई कार्य नही हुआ। इस कार्य के न होने की वजह से और रुकावट की वजह से अंसतुष्ट होकर बालफर–बैटी ने जनवरी 1989 में कहा कि हम इस प्रोजैक्ट से ज्वाइंट वैचर विद ड्रा करना चाहते हैं क्योंकि काम तो करने नहीं देते और जो मांगते हैं, वह हम दे नहीं सकते। (विध्न)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, ये फिरै हाउस को मिसलीड कर रहे है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह मैं नही बोलता यह तो फाईल बोलती है। मैं फाईल को स्पीकर साहब के चौम्बर में भेज देता हूं आप खुद देख लें। तो अध्यक्ष महोदय, वे कहने

लगे कि हम इसमें से निकलना चाहते हैं। इसके उपरान्त कोटीनेटल कंस्ट्रक्शन लिमिटिड ने 4– 2– 89 को कहा कि वालफर–बैटी के समक्ष कंस्ट्रक्शन की स्पैसिफिकेशन के रेट के मुताबिक पूरा करेंगे और इस तथ्य के बारे में उनको अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी अनुमति दे –दो क्योंकि वह तो बेचारा दुखी होकर जा रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम करेगे। कटीनेटल कंस्ट्रक्शन लिमिटड ने 18– 3– 89 को इसके बारे में दोबारा पत्र लिखा और बाकी काम समय पर करने के लिए अनुमति मांगी। लेकिन कम्पनी. की इस प्रार्थना को 6–4–89 को पत्र द्वारा सरकार ने अस्वीकार कर दिया, उसको परेशान करने के लिए। स्पीकर साहब, वहा एक बैक की गारटी दैना होती है। इसी दौरान मोबलाइजेशन एडवास की बैक गारंटी को कैश करवाने का प्रयत्न किया गया जिसके खिलाफ कोंटीनेटल कंस्ट्रक्शन लिमिटड ने दिल्ली उच्च न्यायालय से 7– 3– 90 को स्टे प्राप्त किया। उस कम्पनी ने अलग से प्रस्ताव करके काम करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना की लेकिन उसको भी इन्होंने नामंजूर करके धारा 47 के तहतलिक्वीडेशन और डैमैजिज का नोटिस दे दिया गया। इन कारणों की वजह से वह कम्पनी आगे की कार्यवाही नहीं चला पायी, परिणामस्वरूप आगे कोई काम होने का सवाल ही नही था। इसके बाद आज की सरकार आ गयी। इस सरकार ने अगस्त मे उस कम्पनी के साथ पूरक अनुबन्ध करके हस्ताक्षर किए और उनसे काम शुरू करवाया जो आज करनाल तक बनकर तैयार हो गया है। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं इन पर

एक ऐलीगेशन और लगाना चाहता है कि सोनीपत जिले मे जो बी ० एस० टी ० गन्नौर में फैक्ट्री है, वह रौनक सिंह की एक बहुत बड़ी कम्पनी पं, जिसमें पांच हजार वर्कर काम कर र हे थे। उससे इन्होंने आठ करोड रुपये मांगे। उनका मेरे पास टेलीफोन आया और उन्होने मुझसे कहा कि आपने सी ० एल० वर्मा के बारे मे ही क्यो कहा, हमारे बारे में भी कह देते। स्पीकर सर, ये उन दोनो बाप–बेटे के लफ्ज है। मैं ओन ओथ कहता हूं कि उन्होंने कहा कि आठ करोड़ रुपये मेरे से मांगे। आप चाहे तो इसके लिए एक हाउस की कमेटी बना दें और उस कमेटी मे मुझे बुला लें, तब फिर मैं बताऊगा कि इन्होने क्या किया है। इन्होने उससे आठ करोड़ रुपये मांगे लेकिन उसने कहा कि इतने मैं नही दे सकता, दस या बीस लाख की बात होती तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि नही आठ करोड़ रुपये ही चाहिए। पहले तो ये दस करोड़ रुपये मांग रहे थे लेकिन फिर आठ करोड़ पर आ गत। जब उसने रुपये देने से इन्कार कर दिया तो वह फैक्ट्री बन्द कर दी। पांच साल से वह फैक्ट्री बन्द है और पांच हजार लेबर इनकी मेहरबानी से आज भीख माग रही है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस बी ० एस० टी ० में पांच साल से कर्मचारी बेकार बैने है इसलिये अब तो आप उसको चालू करवा दी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की. है और उन्होने वायदा भी किया है कि मार्च के महीने में यानि इसी महीने में इसको चालू कर देंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अभी मुख्य मन्त्री जी ने फाईल का हवाला दिया, सर, आपको भी मालूम है कि अगर कोई एग्रीमैंट के रूल्ज को वायलेट करता है तो काम रुक जाता है। खुद सी ० एल० वर्मा ने जो लिखा है, उसके बारे मेँ मैं आपको कम्पनी वाला पैरा पढ़कर सुनाता हूं। मुख्यमंत्री जी बार–बार डील की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आपकी फाईल मेरे पास आ गयी है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, लेकिन मैं भी इसको ओन रिकार्ड लाना चाहता हूं। सर, इसमें साफ लिखा है। The work on the fourlaning project between Sambalkha and Karnal (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : It is already with me, इसके अलावा कोई और बात बोलनी है तो बोलो, परन्तु इस पर नही।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, श्री सी ० एल० वर्मा की तो क्लीयर हो गई इसलिये ये अपनी पुरानी बात से भागना चाहते हैं, अपनी कही हुई बात से आज गवर्नमैंट भागना चाहती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आपने दूसरे ऐलीगेशन पर बोलना है तो बोलें, इस पर न बोले।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जैसे बी ० एस० टी ० के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है उसके लिए कम्पनी लैण्ड लेता है। चेंज आफ लैण्ड की भी सैक्शन होती है जैसै एक हजार एकड़, दो हजार एकड़ या पांच सौ एकड़ चाहिए, उसने लैण्ड ली लेकिन उसका इस्तेमाल गलत किया। उसको बाकायदा इस बात का नोटिस दिया गया था कि आपने जो लैण्ड ली है, उस लैण्ड को उस परपज के लिए इस्तेमाल नही किया जिस परपज के लिए आपने ली थी। वह चेंज आफ लैण्ड का फायदा उठाकर उससे दूसरे कामर्शियल गेन करना चाहता था, that is why Government gave notice, Sir. अगर सरकार कह रही है कि चार साल हो गए, प्लान्ट ने काम करना बद कर दिया .... (श्री लहरी सिंह की तरफ से विध्न)

Mr. Speaker : Lehri Singh Ji, no interruptions please. पहली बात तो यह है कि ऐलीगेशन आप पर नही लगाया, ओम प्रकाश चौटाला जी पर लगाया है। यह पार्टी पर नहीं लगाया है, पर्सनल लगाया है।

प्रो० सम्पत सिंहः एक मैम्बर पर लगाया (Interruptions & Noise)

Mr. Speaker : Lehri Singh ji, please do not interrupt. Please take your seat.

Prof. Sampat Singh : Sir, I am the Leader of the Opposition Party. Shri Chautala is my member, that is why I am speaking, Sin

Mr. Speaker : He should reply rather than you, please. He is already present in the House.

Prof. Sampat Singh : Sir, after me he will say something. I had also been in his Cabinet.

Mr. Speaker : May be, you were a Minister in that Cabinet but you cannot speak.

Prof. Sampat Singh : You have permitted me, Sir.

श्री अध्यक्षः अच्छा, अपनी बात आप पांच मिनट में कह दें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, दुनिया देख रही है इस तरह से रूलिंग पार्टी की क्या पोजीशन होती है। I am not saying about the ruling party, Sir.स्पीकर सर, अभी जो बी ० एस० टी ० का जिक्र आया था, एक फैक्ट्री का जिक्र कर रहे हैं उसको जिस परपज के लिए लैण्ड दी गई थी, उस लैण्ड को उस परपज के लिए इस्तेमाल नही किया गया, अदर दैन दैट परपज किया था, इसलिये गवर्नमैंट ने उनको नोटिस दिया कि जिस परपज के लिये आपको लैण्ड मिली थी उस परपज के लिये आप लैण्ड का यूटीलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे है ,वह नोटिस था। ऐसा हमेशा होता रहा है कि अगर सरकार किसी सरकारी लैण्ड को या प्राईवेट लैण्ड को किसी स्पैशल परपज के लिये अलाट करती है और यदि

कोई व्यक्ति लैण्ड यूज चेन्ज करवा लेता है तो सरकार उसको नोटिस देती है। वह नोटिस उनको दिया गया था, अदर– वाईज भी उनकी कोई अपनी लेबर प्रोब्लम थी। (शोर) आज फिर यह भी कह देंगे कि बे। ० एस० टी ० से पैसा मांगा था जिस तरह से सी ० एल० वर्मा की बात इन्होंने यहां पर कही। वह बिल्कुल असत्य निकली। (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): असत्य नही निकली, वह बिल्कुल सत्य है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, यह सब कुछ आफटर बाट है। (शोर) यह वैलप्लैप्ड है। (शोर) यह एक कास्पीरेन्सी है सर। (शोर) इस लिये इन्होंने ऐसा किया है कि इस मामले में कुछ है ही नही और वह मामला बिल्कुल खत्म हो गया है (शोर) इसीलिये इन्होंने दूसरा मामला यहां पर लाने की कोशिश की है। (शोर) यह बिल्कुल असत्य और तथ्यों से परे है, निराधार है। (शोर) इन की सरकार को बने लगभग चार साल हो गये है और हमारी सरकार भी लगभग पौने चार साल रही। उन वक्त ऐसो कोई बात नहीं होती थी। (शोर) लेकिन ये हर बात को यहां पर गोल मोल करना चाहते है। (शोर) केवल यही कह देना कि हमने फैक्टरी खुलवाने की. बहुत कोशिश की है, कोशिश कर रहें है, हम कोशिश करेंगे, इन बातों से कुछ नही बनने वाला। (शोर) इसका मतलब तो यह है कि इन लोगों में खुद में इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं अगर इनमे अपने मे यह कमियां है तो ये

उन सै डील करना चाहते होगे। यह बिल्कुल असत्य है। असलियत में यह केस प्रिवलेज का ही बनता है। (शोर) इस तरह से ये हाउस को मिस लीड कर रहे हैं। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहूगा। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मैटर है, यह कोई साधारण मैटर नही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस में खडे होकर इनकी प्रिवलेज मोशन के ऐलीगेशन को चौलेन्ज किया हे। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मसले पर कुछ बोलना चाहता हू। मेरे भी कुछ अधिकार है यहां बोलने के? (शोर)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बैठिये। (शोर) क्योंकि मैं मुख्य मंत्री महोदय को बोलने के लिये कह चुका हू। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बैठिये, कादयान साहब जो मूँ छ कह रहे है यह रिकार्ड न किया जाएं। (शोर) सी ० एम ० साहब, अगर आप बोलना चाहते है तो बोल लें, वरना मैं अपना फैसला इस पर सुनाता हू। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह इनका कोई बोलने का तरीका है? (शोर)

श्री सतबीर सिह कादयानः स्पीकर साहब, ... (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, यह क्या तरीका है हाउस चलाने का? यह क्या तरीका अपनाया जा रहा है कि प्रिबलेज मोशन पर जिन लोगों के हस्ताक्षर है, उनको आप बोलने नही दे रह हैं, ताकि वे अपनी–अपनी बाते यहां हाउस में न कह सकें। (विष्य)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, मैंने पहले ही आपको बोलने के लिये कहा था (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, आप हमे इस तरह से सनब कर रहे हो और हमारे उन मैम्बर्ज को जिन्होंने प्रिवलेज मोशन पर हस्ताक्षर किये हैं, बोलने नही दिया जा रहा है। (शोर)

श्री अध्यक्षः इन्होने मुझ से कभी बोलने की मन्जूरी नही ली है। बिना आज्ञा के वे कैसे बोल सकते है? (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, हम प्रिवलेज मोशन लाए है, उस पर तो हम बोलेंगे ही। (शोर) स्पीकर साहब, इन लोगों ने साथ में हमारे बारे में यह भी कहा कि हम भागेगे।

मैं इनको बताना चाहता हू कि हम भागेंगे नही, हम तो फेस करेंगे। (शोर) जिन लोगों ने प्रिवलेज मोशन पर साईन कर रखे है, उनको बुलवाने की जिम्मेवारी आप की ही है। (शोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, सतबीर सिह कादयान पहले अपनी बात कहेंगे। आप उन्हें बोलने क्यों नही देते? (शोर)

(इस समय श्री कादयान सहित बहुत सारे मैम्बर बोलने के लिये खडे हुए)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बैठ जाएं। (शोर) आप सब बैठ जाएं। कादयान साहब मैं आपको बोलने की आज्ञा नही देता। आप कृपया बैठ जाएं। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, मै फिर यही कहना चाहता हू कि जिन लोगों के प्रिवलेज मोशन पर दस्तखत हैं, वे कैसे नहीं बोल सकेंगे? (शोर) आप उनको बोलने से कैसे रोक सकते हैं? जिन मैम्बर्ज ने साईन किये हैं, वे तो जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे ही (शोर) उनका बोलने का पूरा राईट है। यह सरकार प्रिवलेज मोशन को फेस नही– करना चाहती। सब से पहले कादयान साहब इस पर बोलना चाहेंगे, उनके उस प्रिवलेज मोशन पर हस्ताक्षर हैं, सर।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, मुझे तकलीफ हुई है इसलिये मैं कुछ बोलना चाहूंगा, सर। (शोर)

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब आप बैठें। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, आप मुझे यह बताएं कि और कोन सा प्लेटफार्म है जहां हम अपनी बात कह सकते हैं? (शोर) मैं कहना चाहता हु कि .... (शोर) ....

श्री अध्यक्ष: जो कुछ कादयान साहब कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी धीरपाल सिंह: यह क्या बात है स्पीकर सर, कि हमें अपने प्रिवलेज मोशन पर बोलने ही नहीं दिया जा रहा। (शोर) यह क्या तरीका है कि जिस तरह से हाउस के नेता चाहें, वही कुछ बोला जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप सब साहेबान बैठ जाएं। पहले मुझे इस बारे में कुछ बतलाने दो। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, पहले आप हमारी बात सुनिये, तब हम आपकी बात सुनेंगे। (शोर) हमने प्रिवलेज मोशन दिया है उस पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, वे अवश्य ही बोलेगे। (शोर) यह कोई इनका हाउस चलाने का तरीका है क्या कि हम अपनी बात भी न कह सके? (शोर) हम

सब अपनी बात अवश्य कहेंगे। (शोर) हम प्रिवलेज मोशन के सिवाये कोई बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं। (शोर)

Mr Speaker : Hon'ble Member, Shri Om Parkash Chautala and other M.L. As have given a notice of breach of privilege. They had given it at 9.37 A.M. today (Interruptions). They had given it when the House had commenced. Here is my ruling on this. Rule 262 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly says:—

Notice of question of privilege	"262. A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the

चूंकि यह नोटिस 9. 37 पर आया था और कमेंसमैट आफ दि हाउस 9. 30 बजे हो चुकी थी। यह अंडर एग्जामिनेशन है इसलिए इस पर अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं अपनी बात तो कह लूं।

श्री अध्यक्ष: नही। आप बैठ जाइए।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–

किसी व्यक्ति को सदन के समक्ष साक्षी देने के लिए बुलाने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, on 10th March, 1995, while the Hon'ble Chief Minister was replying to the debate on the Motion of Thanks to the Governor's Address, a point of order was raised as to whether a person can be summoned before the House as a witness with a view to give,an evidence. On this issue, I have carefully gone through the proceedings of the House dated 10th March, 1995 and I have also gone through the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assessmbly as well as the Book on Parliamentry Practice and Procedure. Neither a person has ever been summoned as a witness before the House in the Haryana Legislative Assembly nor I could lay my hands on a precedent anywhere in Parliament/State Legislatures where a witness was summoned before the House to give an evidence.

On the basis of the above, I hold that a person cannot be summoned as a witness before the House in order to give an evidence. So far as the question of enquiry into the allegation that Shri Om Parkash Chautala, M L.A. demanded a sum of Rs. 5 crores from Shri C.L. Verma, owner of Continental Constructions Limited which was entrusted with the construction of four-laning road is concerned, I place this matter for consideration of this august House in order to enable me to decide as to in what manner the enquiry of the aforesaid subject may be conducted. I, therefore, feel that further appropriate action in the matter will be taken up after a decision on this issue is taken by this august House so that an appropriate procedure is evolved in such like cases.

प्रो ० छतर पाल सिह के निलंबन को रद्द करने संबंधी मामला उठाना

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चौधरी छत्तर पाल सिंह की सस्पैन्शन पर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कई दिन हो गए हैं इसलिए अब तो उनको वापिस ले लेना चाहिए। हमारे रूल 104 में लिखा हुआ है –

"(1) The Speaker shall preserve order and have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions on all points of order.

(2) He may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the Assembly and any member, so ordered, to with draw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. If any member is ordered to withdraw a second time in the session, the Speaker may direct the member to absent himself from the meetings of the Assembly for any period not longer than the remainder of the session and the member so directed shall absent himself accordingly. Such member shall be deemed to be absent from the meetings of the Assembly for purposes of section 3(2) (a) of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975, but shall not be deemed to be absent for the purposes of Article 190(4) of the Constitution." अध्यक्ष महोदय, प्रो० छतरपाल सिंह को आपने नेम नहीं किया। यह सरकार आपके राईटस को वेव करके सीधे रूल 121 के तहत मोशन ले आई जबकि आप द्वारा उनको नेम किए बगैर इनको वह मोशन नहीं

लाना चाहिए था। इसके बावजूद मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप अपने आर्डरज को रिवोक करें और उनको हाउस में आने की इजाजत दें। मैं लीडर औफ दि हाउस से भी कहूंगा कि उनको हाउस में आने की इजाजत मिलनी. चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने कहा, उससे मैं सहमत हूं। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि प्रो० छतर पाल सिंह, जिन को हाउस से बाहर रहते हुए एक हफ्ता हो गया है, वुला लिया जाए। गवर्नर ऐड्रैस पर भी बहस खत्म हो ली और कल बजट भी पेश हो गया। आज बजट पर डिस्कशन शुरू होनी है। याद आप उनको हाउस मे आने की इजाजत दे देंगे तो वे भी बजट पर बोल सकेने और अपने हल्के की समस्याएं यहां पर रख सकेंगे। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपन आर्डर्ज को रिव्यू करें और उनको यहां हाउस मे आने की इजाजत दे दें ताकि वे अपने हल्के और स्टेट के ईशूज को यहां पर उठा सकें। (शोर)

श्री अध्यक्षः बेरी साहब, क्या प्रो० छतरपाल सिंह आपकी पार्टी के हैं।

Ch. Jagdish Nehra : Speaker Sir, he is a leader of unattached party and Prof. Chhattar Pal Singh is a member of his party.

श्री ओम प्रकाश बेरीः स्पीकर साहब, दरअसल बात यह है कि बजट सैशन चल रहा है और यहां हाउस में हर एम ० एल०

ए ० को अपनी. अपनी बातें कहने का अधिकार है। प्रो० छतरपाल सिंह को हाउस से निष्कासित करने के कारण उनकी कांस्टीच्यूऐसी अन–रिप्रेजैटिड रह गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने फैसले को री–कसिडर करे और उनको हाउस में आने को इजाजत दें ताकि वह डिबेट में हिस्सा ले सके ताकि वह अपनी कांस्टीच्यूएंसी का बात यहां पर कह सके। आज उनको निष्कासित किए हुए 6 दिन हो गए हैं। यह उनके लिए काफी सजा है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार उनके विरद्ध जो मोशन ले कर आई थी, उस पर आप पूनः विचार करे और उनको सदन मे आने की इजाजत दें ताकि डिबेट इफैक्टिव तरीके से चले और माननीय सदस्य अपने हल्के की बात कह सकें।

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, अब तो आपका भी मन कर रहा है कि उनको हाउस में आने की इजाजत दे देनी चाहिए। आप बडे उदार है। सदन के नेता से चौधरी बंसी लाल जी ने भी आग्रह किया है और हम सब आग्रह कर रहे हैं कि उनको सदन में आने की इजाजत मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, आप तो इस सदन के कस्टोडियन है। स्पीकर साहब, इस बारे में हमने कल भी आपसे रिक्वैस्ट की थी। चौधरी भजन लाल जी, आप इसको इतना प्रैस्टीज ईशू न बनाए। आप नेहरा जी की सारी बातों को न माना करें। चौधरी बंसी लाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने भी आपसे रिक्वैस्ट की है। आप हमारी बात को मानें और

प्रो0 छतरपाल सिह को सदन में आने कीं इजाजत दे ताकि वह अपने हल्के की बात यहां पर कह सके। He is feeling sorry. तो आपसे गुजारिश है कि चौधरी भजन लाल जी, आप इस बात को प्रैस्टीज ईशू न बनाएं और अपने प्रस्ताव को वापिस लें।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, अगर वह हाउस मे फिर कोई गडबड करेंगे तो आपको यह अधिकार है कि आप फिर उसको बाहर निकाल दें। मैं यह भी कहूंगा कि नेहरा साहब की बजाय चौधरी भजन लाल जी आप खुद बोले क्योंकि नेहरा साहब को पढ़ना नही आता। ये थोडे पढे लिखे हैं इसलिए ये उल्टा पढ़ेगे। (हंसी)

11.00 बजे

श्री जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी बुजुर्ग हैं। मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं। मैं इनको यह भी बता सकता हूं कि ये खुद कितने पढ़े लिखे हैं और मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। स्पीकर साहब, इन्होंने दो–तीन बार कह दिया कि मुझे पढ़ना नही आता। अब मैं इन से बुजुर्ग होने के नाते कुछ कहना नहीं चाहता। अगर मैं ऐसे। कुछ बात कह दूंगा तो फिर चौधरी बंसी लाल जी कभी नही कहेंगे कि मुझे पढ़ना नही आता। अध्यक्ष महोदय प्रो० छत्तर पाल सिह का व्यवहार बड़ा खराब रहा था। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नही हुई थी जिस कारण उसे स्पीकर साहब की बात भी न माननी

पड़े। स्पीकर साहब के खड़े होने के बावजूद भी वे आपत्तिजनक ढंग से खडे रहे। हमारी सवकी जिम्मेवारी है कि जब अध्यक्ष महोदय, खड़े हों तो उनके सम्मान में हम सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। लेकिन वे दो–दो घण्टे तक बैठे नहीं और दो तीन दिन लगातार वे ऐसा ही करते रहे। स्पीकर साहब ने उनको बैठने के लिए एक दो बार नहीं, वीसियो बार कहा लेकिन वे नहीं माने। दूसरे उन्होंने कई बाते डैरोगेटरी कही और स्पीकर साहब बारे में भी उनका अशोभनीय व्यवहार रहा। (विघ्न) उनके शब्द मुझे सुनाई दिए यहा पर, तो ये फिर कैसे हो सकता है कि उन्होंने नहीं कहे। उन्होने ऐसे डैरोगेटरी शब्द पहले दिन भी कहे, दूसरे दिन भी कहे। उन्होंने हाउस की कोई डिगनटी नही रखी और न ही उनकी हाउस की डिबेट में कोई कन्ट्रीव्यूशन रही। उनका काम सिर्फ एलीनेशन लगाना ही रहा। जैसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब उन्हेंने महसूस कर लिया है, ऐसी बात नही है क्योंकि खुद चौधरी बंसी लाल जी भी कह रहे है कि यदि दुबारा वह ऐसी गलती करेंगे तो फिर निकाल सकते है। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी खुद संतुष्ट नही है कि उनका व्यव्हार आगे ठीक ही रहेगा या नही। इनको खुद पूरी तरह से कान्फींडैस नही है।

श्री बंसी लालः मैंने तो यह कहा है कि यंदि आप समझे कि उसका व्यवहार ठीक न लगे तो फिर दोबारा निकाल सकते है।

श्री जगदीश नेहराः उनका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। यह भी अच्छा नही लगता कि उनको बार बार निकाला आये। अब उनको पुन. हाउस में लेने की बात ठीक नहीं है।

Mr. Speaker : I have already quoted here Rule 121, which says—

"Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the Assembly and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being."

and the motion was moved and it was adopted by the House.

श्री बंसी लालः मेरी सबमिशन यह है कि रूल 121 बाद में आता है। पहले चेयर की तरफ से उसे नेम करना पड़ता है। यदि फिर भी न माने तो पुनरू नेम करना पड़ता है, यदि फिर भी न माने तो फिर चेयर की अवहेलना करने के कारण यह रूल लाने के लिये चेयर सरकार को कहती है और फिर सरकार मोशन मूव करती है, तब जाकर रूल सस्पेंड होता है, आर्डनरी प्रोसीजर तो यही है, बाकी आपकी मर्जी है।

Mr. Speaker : I had already warned him and consented for moving the motion.

श्री बंसी लालः क्या आपने उनको रोका, वार्निंग दी?

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग (पुनरारम्भ) तथा उस पर चर्चा

Mr. Speaker : Now the matter ends. So far as the question of inquiry into the allegation that Shri Om Parkash Chautala, MLA demanded a sum of Rs. 5 crores from Shri C.L. Verma. owner of Continental Constructions company, which was entrusted with the construction of fourlaniog road is concerned, I place this matter for consideration of this august House in order to enable me to decide as to in what manner the inquiry of the aforesaid subject may be conducted I, therefore, feel that further appropriate action in the matter will be taken up after a decision on this issue is taken by this august House so that an appropriate procedure is evolved in such like cases.

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मेरे दिमाग में एक सुझाव आ रहा है। वैसे तो उस दिन मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा था कि यह मामला स्पीकर साहब पर छोड़ दिया जाए और आपने यहा पर हाउस में फरमाया है कि कोई ऐसा प्रैसिडैट नही है कि विटनैस को सदन में बुलाया जा सकता है। आपकी यह रूलिंग आ गई है। इसमे एक तो यह हो सकता है कि इस मामले को आप पर छोड़ दिया जाए, जिस तरीके से भी आप तसल्ली करना चाहे, कर सकते हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि हाउस की एक कमेटी कान्स्टीच्यूट कर दी जाए। वह कमेटी अपनी तसल्ली कर लेगी। बेशक दोनो मेटर इसी कमेटी को दे दीजिए। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, इस बारे में मेरी सबमिशन है कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने स्पीकर साहब का भी हवाला दे कर सुझाव दिया है। स्पीकर सर, हमें चेयर में पूरी

आस्था है और हम चेयर की कद्र करते हैं। स्पीकर सर, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहना चाहता हूं कि इस मैटर को इस हाउस की जो प्रिवलेज कमेटी है, उसको दे दिया जाए। प्रिवलेज कमेटी एक बड़ी कमेटी है। स्पीकर सर, यह कमेटी या तो डयूली इलैक्टिड है या आपके दारा नोमिनेटिड है, यह मामला इस प्रिवलेज कमेटी को दे दिया जाये। हमने जो प्रिवलेज मोशन दिया हुआ है, वह अपने आप क्लीयर हो जाएगा और प्रिवलेज कमेटी इसको डिसाईड कर देगी। स्पीकर सर, जैसा कि आपने कहा है कि ऐसा कोई प्रैसिडैट नहीं पा है जिस के तहत विटनैस के लिए हाउस में किसी को बुलाया जाए न ही ऐसी कोई कन्वेन्शन ही रही है। इस बारे में स्पीकर साहब, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्वैशन या प्रैसिडैट जो बनती हैं, वह कही न कही तो बनती ही हैं। अगर पहले कोई प्रसिडैन्ट या कन्वैशन नही है तो उसको अब बना सकते हैं क्योंकि जब बाकायदा साईन्ड एण्ड वैरिफाईड स्टेटमैंट हमने आपको दे दी है तो उस बेस पर आप प्रैसिडैन्ट बना सकते हैं क्योंकि आईन्दा आने वाले वक्त में भी कोई भी सत्तासीन आदमी सत्ता से मदहोश हो कर किसी पर भी कोई भौं लान्छन लगा सकता है। स्पीकर सर, इसलिये मैं कह रहा हूं कि आईन्दा के लिये एक हैल्दी प्रैसिडैन्ट हैल्दी कन्वैन्शन बन जाएगी। स्पीकर सर, आप बेहतर जानते हैं कि इंग्लैड का कान्दटीच्यूशन, टोटली प्रैसिडैशियल एण्ड कन्वैन्शन्ज पर आधारित हैं। वही से हम्ने अपना संविधान लिया है। एक अच्छी बात की कन्वैन्शन तो हमें डालनी चाहिये। बुरी बात की चाहे कन्वैन्शन भी

रहीं हो, तो भी हम लोगों को उसे ड्रौप कर देना चाहिये। स्पीकर सर, इसलिये मैं तो यही अपील करूंगा तथा सुजैस्ट करूंगा कि जैसे हमने रैजोल्यूशन दिया है कि इस मैटर को हाउस की ब्रीच आफ प्रिविलेज, आप एडमिट करें और प्रिविलेज कमेटी को इसको दे दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। स्पीकर सर, हमे यही मान्य होगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः पहले मिनिस्टर साहब खड़े हैं, ये अपना सुजैशन दे दे फिर आप डौल लेना।

श्री ए ० सी ० चौधरीः स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रिविलेज कमेटी को मैटर तब जाता है जहां हाउस इस बात को मान ले कि कहीं बीच हुआ है तो वह मामला डायरैक्ट रैफर होता है। इस केस में यह अलैज कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है लेकिन हाउस ने इसको एसैप्ट नही किया। स्पीकर सर, इसके लिये तो एकमात्र रास्ता है कि हाउस की एक कमेटी बन जाए, वह इस बात को एग्जामिन करे कि दोनों बातें जो कही गई हैं, वे टैटामाउंट करती हैं या बीच आफ प्रिविलेज के लिये फरदर इन्वैस्टिनेशन मांगती है। इन्वैस्टिगेशन ही एक मात रास्ता है। हाउस की कमेटी बना दी जाए जो कि कन्कलूड कर दे कि आया कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है, अगर हुआ है तो उसके बाद जो प्रोसैस है वह हो सकता है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि चौटाला साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया और मुख्यमंत्री जी ने उसका हवाला दिया और आपने भी अपनी रूलिंग रिजर्व रखी तथा आज भी सदन के ऊपर छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर कोई भी पार्लियामैंटरी कन्वैन्शन नही है कि हाउस की कमेटी बनाई जाए या प्रिविलेज कमेटी को मामला सौंप दिया जाए। मुझे भी पार्लियामैंट तथा इस हाउस मे बैठते हुए 30– 35 साल हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय होता तो यह है कि एक मैम्बर ने दूसरे मैम्बर के ऊपर एलिगेशन लगा दिया और उसने मना कर दिया तो वह बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर आप आज कमेटी बना देते हैं तो भविष्य में यह एक प्रैसीडैन्ट बन जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि यह मामला यही पर बन्द कर दें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं आपके जरिए सदन के नेता से भी कहूंगा कि यह मामला यही पर बन्द कर दें।

चौधरी भजन लाल अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि बी०एस०टी० ने पूरी जमीन इस्तेमाल नही की जिसके लिये इन्होने ली हुई है। यह जमीन आज की नही है, यह फैक्टरी आज की नही है. यह ज्वायंट पंजाब के समय की लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा बिना सिर–पांव की बात कहतें है। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप हाउस की कमेटी बना दे और ये दोनो मामले उस कमेटी को सौंप दें या फिर चौधरी बंसी लाल जी की अध्यक्षता मे एक कमेटी बना दें और वे दोनो से पूछ कर हाउस क्ये बता दें।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये तैयार नहीं हू। मैं तो आपके जरिए यह कहूंगा कि ऐसी कन्वैशन न डाले और यह मामला यही पर बन्द कर दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बंसी लाल जी की बात से सहमत हू।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बसी लाल जी ने ठीक कहा है। आज भ्रष्टाचार के इतने मामले है, आप कहा कहां पर कमेटियां बनाते रहेगे? हाउस पर छोड़ने का मतलब है कि टोटल हाउस की कन्सैट हो। अगर हाउस की कन्सैट ही न हो तो कैसे हो सकता है? आप ऐसा करे कि यह मामला जनता पर ही छोड़ दें और एक साल बाद सब पता चल जाएगा।

Mr. Speaker : As it is the consensus of the House that the matter should be closed, the matter is closed.

No more discussion or. this subject will be allowed now

ध्यानाकर्षण सूचनाएं /नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुझे कालिंग अटैन्शन मोशन पर बोलना है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the calling attention motion No. 11, given notice of by Smt. Chandravati, M.L.A. regarding repairing of lift irrigation water courses in district Bhiwani has been admitted for 20th March, 1995.

The calling attention motion No. 5 given notice of by Shri Karan Singh Dalal M.L.A. regarding pollution being at the extreme in whole of district Faridabad has been admitted for 21st March, 1995.

The calling attention motion No. 25, given notice of by Shri Ram Bilas Sharma, M.L.A. regtrding non-availability of kerosene oil and wheat on ration stops and black marketing in Haryana State has been admitted for 15th March, 1995.

The calling attention motion No. 27, given notice of by Shri Satbir Singh Kadian M.L.A. regarding pollution due to waste ash and water of Thermal Power Plant, Panipat and spreading of disease in the nearby villages has been sent to the Government for comments.

The calling attention motion No. 30 given notice of by Shri Amar Singh Dhanday and two other M.L.As. regarding atrocities on Harijans of Village Keorak, Distt. Kaithal has been sent to the Government for comments.

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और मोशन राजधानी क्षेत्र के बारे में था जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की सारी जमीन का इस्तेमाल किया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपकी सेवा में अपना एक मोशन फरीदाबाद में बिगड़ा कानुन और व्यवस्था के बारे में दिया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस संरक्षण में वहां अपराध हो रहे हैं लेकिन आपने उस पर अपनी रूलिंग देते हुए उसको डिसअलाउ कर दिया। अध्यक्ष

महोदय, कोई बात नहीं मैं इस बारे में अपनी बात बजट स्पीच में कह लूगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक बात और कहनी है कि जिला फरीदाबाद में जमुना के साथ लगते हुए जो हरियाणा के गांव हैं वहां पुलिस ने उत्तर प्रदेश के किसानों से पैसा लेकर हमारे लोगों को थानों में बिठा रखा है। यह सब पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। (विघ्न)

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष: आप अभी बैठिए। (विघ्न)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी तो इसको टालने की बात कर रहे हैं हरियाणा के हित को देखते हुए इनको इसका जवाब देना चाहिये।

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी समय दें।

श्री अध्यक्ष: आप अभी बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे पलवल तहसील के यमुना के साथ लगते हुए धोडी और चांट गांव है, उनके मुख्य– मुख्य आदमियों को पलवल के सदर था ने में पुलिस

ने बैठा रखा है। ये किसान अपने अपने खेतों की फसल काटने गए हुए थे लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरियाणा की पुलिस को पैसा देकर उनको बंद करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के किसान उनकी फसल काटकर यू ०पी ० में ले जाते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, इनके तो गांव यमुना के किनारे लगते ही नही हैं बल्कि जमुना के किनारे तो हमारे इलाके के गाव लगते हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कर्ण सिंह जी ने कहा कि पलवल के था ने में किसान बैठा रखे है। आप जानते हैं कि यमुना के किनारे पर खेत है। जब यमुना अपना बहाव बदलती है तो उस हिसाब से लोग खेती करने की कोशिश करते हैं। कई बार यमुना जब यू० पी० की साईड में चलीं जाती है तो हरिंयाणा के लोग उस जमीन में काश्त कर लेते है जबकि जमीन की मलकियात उनकी है और कई बारे जब यमुना का बहाव इधर की ओर आ जाता है तो यू ० पी ० वाले उस जमीन पर काश्त कर लेते हैं और फसल काटते समय उनमें झगड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसको हम दिखवा लेंगे और जो ठीक बात होगी वह कर लेंगे।

श्री ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे दो मोशन नियम 84 के अधीन थे। एक तो मेरा मोशन एस ०वाई ०एल ० की कम्पलीशन के बारे में था और दूसरा यमुना के ऐग्रीमैन्ट के बारे'

में था जिसमें हरियाणा के हितों को बेच दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एस ०वाई ०एल ० का मामला तो हरियाणा प्रदेश के हित की बात है इसलिये आप मेरे इन दोनो मोशज पर दो घन्टे की बहस करा दे ताकि सारी चीजें ठीक से हाउस मे आ सकें।

श्री अध्यक्षः बेरी साहब, आपके मोशन अभी अडर कंसीड्रेशन हैं।

डा० राम प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैंनें 9 मार्च को ध्यानकर्षण प्रस्ताव दिंके था कि 7 मार्च 1995 को कुरुक्षेत्र जिले में देवीदासपुरा, रतगेल, उमरी और पलवल गांवों की जमीन हुडा ने ऐक्यायर की है, इस 215.83 एकड जमीन के अतिरिक्त इन गांवों और सुन्दरपुर की 255, 43 एकड़ भूमि और ऐक्वायर होने लगी है। इन गांवो के किसानों को जो रेट दिया जा रहा है, वह 1991–92 के मार्किट रेट से भी कम है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कुंडली जिला सोनीपत में घोषणा की थी कि बडी जल्दी यह फैसला करेंगे कि जहां किसान की जमीन ऐक्वायर की जाती है, उसके लिये पिछले पांच साल का औसत न लेकर, मार्किट रेट पर मुआवजा दिया जाए। कुरुझेत्र के इन लोगो में इस बात को लेकर काफी चिंता और घबराहट है। 7 मार्च को जमीन ऐक्वायर हुई है और 20 तारीख को पेमैन्ट करनी है, इस नाते मैं चाहूंगा कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को एडमिट करें ताकि इस के बारे में चर्चा की जा सके।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डा० राम प्रकाश जी ने ठीक बात कही है कि मैंने कुंडली मे यह बात कही है। मैंने ऐलान किया है और आज फिर सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी किसानों की जमीन ऐक्वायर होगी, उनको मार्किट रेट का पैसा दिया जाएगा। पिछले पांच साल के ऐवरेज के हिसाब से नही दिया जाएगा, मेरी बात पर आप विश्वास रखें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हमारी तरफ से एक काल अटैशन मोशन, स्टोन क्रशर के बारे मे है। ये स्टोन क्रशर तोशाम के पास खानक गांव में लगे है। स्टोन क्रशर से होने वाले पौल्यूशन की वजह से वहां के लोग तपेदिक की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इस बात को लेकर लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट के फैसले भी लोगों के हक में आए है। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि उन क्रशर्ज को क्रशर जोन बनाकर शिफ्ट किया जाए ताकि वहा पौल्यूशन न हो।

Mr. Speaker : It is disallowed as the matter is sub-judice and pending in the Hon'ble Supreme Court.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि खानक में जो क्रशर लगे हुए हैं, वे आन रोड हैं। वहां वाकई लोगों को बड़ी तकलीफ है। हमने फैसला किया है कि क्रशर वहा से उठ जायें। उनको थोड़ा समय दिया गया है। हमने उनको अलग जगह भी बता दी है, वहां क्रशर जाएंगे। उसमें छह महीने

लग सकते हैं। हमारी कोशिश है कि छह महीने के बाद वहां कोई क्रशर न रहे।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर सर, अभी चौटाला साहब के केस में जो गहमागहमी हो रही' थी, तो हमारे भाई दरियाव सिह जी ने बैठे बैठे एक बात कही कि मैंने .... स्पीकर सर, इनको यह फोबिया हो गया है। स्पीकर सर, मैंने तो शुरु से ही जब से अपनी जिन्दगी संभाली आठ आने की मजदूरी की, एक रुपये की मजदूरीं की है। मजदूरी करके रोटी खाता हूं। ....

श्री अध्यक्षः न इनकी बात रिकार्ड पर आई है और न आपकी बात रिकार्ड पर आयेगी, इसलिये आप बैठिए।

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various Business.

"The Committee met at 4.00 P.M. on Monday, the. 13th March 1995 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

The Committee also recommends that on Tuesday, the 28th March, 1995, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business from 14th March, 1995 to 15th March, 1995, 20th March, 1995 to 24th March, 1995 and from 27th March, 1995 to 28th March, 1995 be transacted by tine Sabha as under

Tuesday, the 14th March, 1993	1.	Questions Hour.
(9.30 a. m.)	2.	Presentation and adoption of Second Report of the Business Advisory Commi-ttee.
	3.	Papers to be laid on the Table of the House.
	4.	General discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.
Wednesday, the 15th March, 1995	1,	Questions Hour.
(9.30 a.m.)	2.	Resumption of discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.

Thursday, the 16th March, 1995		Off Day
Friday, the 17th March, 1995		Holiday
Saturday, The 18th March, 1995		Off Day
Sunday, the 19th March, 1995		Holiday
iMonday, The 20th March, 1995	1.	Questions Hour
(2.00 p.m.)	2.	Resumption of general discussion on the Budget
		Estimates for the year 1995-96.
Tuesday, the 21st March, 1995	1.	Questions hour.
(9.30 a.m.)	2.	Resumption of general discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.
Wednesday, the 22nd March, 1995	1.	Questions Hour.
(9.30 a.m.)	2.	Resumption of general discussion on the Budget

		Estimates for the year - 1995-96 and reply by the Finance Minister. -
Thursday, the 23rd March, 1995	1	. Questions hour.
(9.30 a.m.)		. Non-official Business..
Friday, the 24th March, 1995.	1.	Questions hour-
(9.30 a.m.)	2.	Presentation of Assembly Committee Reports.
	3.	Discussions and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for year 1995-96.
Saturday,the 25th March 1995		Off day
Sunday, the 26th March, 1995		Holiday
Monday, the 27ih March, 1995	1.	Questions Hour.
(2.00 p.m .)	2.	Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1994-95.
	3.	Appropriation Bill in respect

		of Budget Estimates for the year 1995-96.
	4.	Legislative Business.
	5.	Official Resolutions.
Tuesday, the 28th March, 1995	1.	Questions hour.
(9.30 a.m.)	2.	Motion under Rule 15 regarding, non-stop sitting.
	3.	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.
	4.	Presentation of Assembly Committee Reports.
	5.	Legislative Business.
	6.	Any other Business.”

Mr Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contai nedin the second Report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion is carried.

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

Mr Speaker : Now a Minister will lay papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir I beg to lay on the Table —

(a) The Memorandum of Action taken on the Annual Report of National Human Rights Commission for the year 1993-94 as required under section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

(b) The Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1992-93 as required under section 75(i) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(c) The Statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1995 as required under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr Speaker : Hon. Members, now general discussion on the Budget for the year 1995-96 will take place.

बिजनैस एडवाजरी कमेटी में यह तय हुआ है कि आर०एस०जे ०पी० के दो मैम्बर आधा आधा घंटा बोलेंगे और विकास पार्टी का एक सदस्य आधे घंटे के लिये बोलेगा, बाकी सब को 5– 5 मिनट का टाईम देंगे। अपने हल्के की कोई भी बात कहने का सभी मैम्बर्ज को हक है, इस साइड से भी और ट्रेजरी बैंचिज से भी।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री श्री मांगे राम जी ने बजट पेश करते वक्त बहुत बुलन्द दावे किए। इन दिनों में सामान्य तौर पर बजट आते ही हैं। व्यापारी भी अपना बस्ता तैयार करता है और किसान भी साल का अपना लेखा जोखा देखता है। प्रादेशिक सरकारें भी देखती है कि क्या योजना है, क्या खोया और क्या पाया। सरकारे इस बात पर विचार विमर्श करती हैं। इससे राजनीतिक नफे नुक्सान को भी आका जा सकता है। इस सरकार की गलत इकनोमिक पालिसी और गलत नीति की वजह से अभी रीसैटली हुए चुनावो में इनको लोगो ने खूब सबक सिखा दिया। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम डस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपकी पालिसी को लोगों ने पसन्द नहीं किया। इन्हें भी अपना ध्यान नही है इसलिये इसी आधार पर इन्होंने झूठे आकड़े दे कर

बजट पेश किया है। इससे इनकी भी सोच बन गई है। ये सोचते है कि तुमने अब जाना है। इन्होंने जिस तरीके का बजट पेश किया है, उससे सरकार की आमदनी नही बढ़ी बल्कि कर्जा बढ़ाया गया है। इससे जाहिर है कि कर्जा तो आने वाली सरकार देगी इन्होंने तो मौज लूटने का काम किया है। इनके अपने आकड़ों के आधार पर मैं आपके दारा हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आपको आधा घटा दिया गया है, टाईम का ध्यान रखना।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, आप तो बड़े फराख दिल हैं लेकिन जब मैं खड़ा होता हूं तो पता नही आपको तकलीफ क्यों हो जाती है। मैं जो बात कहूंगा अगर वह इनको अच्छा लगे तो मान लेना और अगर अच्छी न लगे तो वह आपको काटने का अधिकार पहले ही है। तो मैं राजस्व घाटे की बात के बारे में कहना चाहता था। हरियाणा के राजस्व की आमदनी खर्चे से पहले हमेशा ज्यादा थी। इसलिये यह प्रदेश इस दृष्टिकोण से सरप्लस माना जाता था। अब जो आकड़े आए हैं इनसे पता चलता है कि पहली बार 1994–96 में इस सरकार ने स्थिति को बदल कर हरियाणा सरकार को रैवेन्यू डैफिसिट स्टेट बना दिया है। इसके लिये सरकार बधाई की पाल है। मेरे ख्याल में यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने काम ही इस किस्म के किए हैं। सरकार ने 1996–96 के बजट में भी इस स्वस्थ परम्परा को कायम रखने की कोशिश की है। वर्ष 1995–96 के

राजस्व की आमदन पांच हजार चार करोड़ रुपए दिखाई गई है और खर्चा पांच हजार 48 करोड़ रुपए दिखाया है। तो राजस्व का घाटा 44 करोड़ रुपए है। इससे जाहिर होता है कि सरकार फिजूल खर्ची में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इसीलिए पब्लिक का कर्जा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से 1994–95 के अन्त मे प्रदेश 5015 करोड़ रुपए का कर्जदार हो जाएगा जो कि पिछले साल से 438 करोड़ रुपए ज्यादा है। डस बजट के मुताबिक 537 करोड़ रुपए का कर्जा और बढ़ जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि कर्जे की हर साल परसैटेज बढ़ती जा रही है। यह सरकार कर्जे से ही हकूमत चला रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इनकी यह सोच है, इन्होने जाना है इसलिये कर्जा वापिस देने के लिये आगे आने वाली सरकार अपने आप निपटती रहेगी। इन्होने तो फिजूल खर्ची करनी है। इस सरकार की वित्तीय साधन ठीक इस्तेमाल करने की पालिसी ठीक नही है। इस सरकार के लोन एंड एडवासिज बढ़ रहे हैं, उनकी रिकवरी की तरफ इनका कोई ध्यान नही है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993–94 में 290 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया और उसमें से वसूली सिर्फ 32 करोड़ रुपए की हुई। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995–96 के बजट में 463 करोड़ रुपए का कर्जा देने का प्रावधान किया गया है यानि कर्जे की 173 करोड़ रुपए की राशि और ज्यादा दी जाएगा और इनका वसूली का लक्ष्य 33.40 करोड़ रुपए का है। इससे ऐसा लगता है कि

कर्जा बोगस आदमियों को और बोगस कम्पनियों को दिया जा रहा है और इस तरह से भ्रष्टाचार करवा रहे है। सरकारी कोष में से पैसे को खुर्दबुर्द किया गया है, ये उस पैसे की वसूली की कोई जरूरत नही समझते और इनसे यह उम्मीद भी नही है कि ये यह पैसा भी वसूल कर लेने। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने खर्चा दिखाने की कोशिश की है, इस बारे मे क्वैश्चन आवर में यह जिक्र आया थी कि भाखड़ा मेन लाइन को रैस्टोर करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुखदायी बात और क्या हो सकती है कि इस सरकार ने भाखड़ा मेन लाइन को रैस्टोर करनें के लिये केवल 15 लाख रुपए रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1990 में हमारी सरकार थी, उस समय भाखड़ा नहर के लिये 8 करोड़ रुपए रखे गए थे क्योंकि पंजाब के एरिया में उसके। मुरम्मत करने, गाद निकालने और बैक्स को मजबूत करने के लिये पैसा खर्च होता है। वह पैसा हरियाणा सरकार वहन करती है और पंजाब सरकार को दिया जाता है। हमारी सरकार ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए एक किश्त के, पंजाब सरकार को दी थी। हमारी सरकार के जाने के बाद इन्होंने अपने तीन साल के अर्से मे उस नहर पर कोई काम नही किया। इस सरकार ने तो उस नहर के लिये इस साल केवल 15 लाख रुपए रखे हैं और इस पैसे से ये उसकी मुरम्मत करना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नालायकी की वजह से हमें भाखड़ा नहर से जो 12000 क्यूसिक्स पानी मिलता था, वह घट कर शव केवल 6 हजार क्यूसिक्स रह गया है। हमारे हरियाणा प्रदेश में कोई नैचुरल वाटर

फलों नहीं है और नही कोई दरिया है और जो दरिया हैं, जैसे घग्गर है, टांगरी है और मारकण्डा है, ये दरिया बरसात के दिन। में हरियाणा प्रदेश के अन्दर तबाही मचा देते हैं। उनकी बाढ़ से लोग तबाह हो जाते है। उन नदियों के पानी से सिंचाई नहीं होता है। जो पानी के साधन हैं, उनके बारे में इस सरकार की कोई तवज्जो नही है। अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा मेन लाइन को रैस्टोर न करने की वजह से हमारे हिस्से का पानी यह सरकार पंजाब से नहीं ला पाती। यह तो इनको ही मालूम होगा कि इस 15 लाख रुपए में यह सरकार क्या करने जा रही है? इसी तरीके से इन्होने फल्ड कंट्रोल के लिये 10 करोड़ रुपए रखे हैं। इस 10 करोड़ रुपए मे तो एस्टेब्लिशमैट का खर्चा ही पूरा नहीं होगा। यह पैसा तो स्टाफ की तनखा हो पर ही खर्च हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस सरकार को प्रकृति के प्रकोप का ज्ञान ही नही है, इसलिये यह सरकार फल्ड की पेशबन्दी क्या करेगा? अध्यक्ष महोदय, पिछले से पिछले साल हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो बाढ आई थी, जिसकी वजह से प्रदेश का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था, लोगो के मकान बर्बाद हो गए थे, फसले बर्बाद हो गई थी उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नही है। अगर उस प्रकार के फल्ड की तरफ कोई ध्यान नही दिया जाएगा और फल्ड कंट्रोल करने के लिये पैसे का ज्यादा प्रांवधान नही किया जाएगा तो फिर वैसा ही फल्ड आ गया तो यह प्रदेश पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। इस सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय जहा तक इकानोमिक रिफोर्मज की बात है। उन्होने कहा है कि मुल्य बुद्धि पर काबू पा लिया है। इन्हों नं जो आकड़े प्रस्तुत किए हैं उनके मुताबिक इन्होने मूल्य वृद्धि पर काबू पाया है इनके लिखे हुए के मुताबिक ही' मै आपको बताऊगा कि अप्रैल 1993 मे बजट का होलसेल मूल्य सूचकांक 232 था और वह फरवरी 1995 मे 285 हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि दो साल के अर्से में 25 परसेंट की मूल्य वृद्धि हु ई है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये हमारी यह तसल्ली करवाना चाहते है कि इनकी 100 परसैंट मूल्य वृद्धि बढ़ाने की योजना होगी। कहते हैं कि मूल्यवृद्धि पर काबू पाया है, परन्तु मूल्य वृद्धि तो बढ़ती जा रही है। इस 25 परसेंट मूल्य वृद्धि से आप देख सकते है कि मूल्य वृद्धि हो रही है या नहीं। इनका जो इकानोमिक रिफार्मज है, उससे विदेशी कम्पनियों को व वित्तीय संस्थाओं को फायदा हो रहा है। इससे आम आदमी को कोई फायदा नही है। इस नीति से विदेशी कम्पनियों को, वित्तीय संस्थाओ को यह सुविधा होगी कि वह यहां के पैसे को विदेशी बैकों में जमा करवा सकेंगे। मेरा कहना यह है कि इनकी इकानोमिक रिफार्मर्ज से आम आदमी को लाभ नही हो पाया है। चोरी का जो पैसा ये इधर उधर ले जा रहे थे, उसका कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामो से पता चलता है। जो हश्र उन राज्यों की सरकारों को भुगतना पड़ा है, उसी प्रकार को अपनीं कब ये यहां पर खोद रहे है। याहिया खा की तरह दफन होना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार मे मंत्री रह

चुके श्री अर्जुन सिह ने पीछे भोपाल में एक जन सभा मे बताया है कि 70 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्षः बीच में अर्जुन सिह का रै फेस कहां से आ गया?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः उसके बारे में तो ये अब कहेगे कि वह हमारी पार्टी में नहीं है। (विघ्न) स्पीकर साहब श्री सैफला जो कैबिनेट सैक्रेटरी और यहां हरियाणा के अन्दर भी हरियाणा के गवर्नर के एडवाईजर रह चुके हैं, ने कहा है कि चीनी के मामले में 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। ये उसी का अनु– सरण करते जा रहे है और यहां पर इनका भी वही हश्र होगा जैसे अभी हाल ही में चुनाव होंने वाले प्रदेशों की सरकारो का हुआ है। इनकी इकानामिक रिफार्मज की पालिसी के कारण शेयरों में भी 20 हजार करोड रुपये का घोटाला हुआ है। यह मौजूदा सरकार अपनी स्टेट की सम्पंत्ति के शेयर मिट्टी के भाव पर बेच रही है। यह सरकार पानीपत थर्मल प्लांट को 300 करोड़ रुपये मे बेचने के लिए एक विदेशी कम्पनी सै सौदा कर रही है और फिर उसी कम्पनी से दुबारा लीज पर लेने की सोच रही है। इस बारे मे कुछ बातें हवा में हो रहो है, बिजली मन्त्री महोदय, इस बारे में स्थिति स्पश्ट कर देंगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो बातें ये कह रहे हैं, इन बातो का इम मौजूदा बजट से कोई संबंध नही है। (विघ्न

) मैं पढ़ना जानता हू या नही लेकिन आपको और आपके पिता को पढ़ा ना अच्छी तरह जानता हू।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं, ये बीच में न बोलें, बाद में मेरी बातों का जवाब दे दें। इन्होंने कहा है कि प्रदेश की इकोनोमी में 4. 2 प्रतिशत की वुद्धि हुई है। इस बारे मे मैं यह कहना चाहता हु कि इसका सारा श्रेय किसानों को जाता है, जिन्होने प्रकृति की कृपा से और अपनी मेहनत से उपज को बढाया। सरकार की तरफ से न तो समय पर खाद सप्लाई हुआ और न हे बिजली और पानी किसानो को मिला। इसलिए इस बुद्धि में सरकार का कोई सहयोग नही है। वर्ष 1993– 94 में सशोधित अनु– मतो में टैक्सी से आमदनी 1, 784 करोड़ रुपये रखी गई है जब कि असल में 1,684 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। यहां पर गुमराह करने की बात की गई है। अनुमानित तो 1,784 और असल में 1, 684 है। मार्च मे साल खत्म होता है। इनके आकड़ों में तथा संशोधित अनुमानों मे 100 करोड़ रुपये का फर्क है जो कि माना जाना चाहिए कि जानबुझ कर खा ता गलत बनाया गया है। इस प्रकार के मामलों पर इस तरह के नकली खाते बड़ी होशियारी से गुप्ता जी हर बजट मे देते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बार आमदनी मे 115 करोड़ रुपये की कमी रही.। जो अन्दाजा लगाया जाता है, वह अन्दाजा फेल हो जाता है और जो कटौती होती. है वह किसान पर, शडयूल्ड कास्ट्स के लोगो पर, आकर सैक्शन्ज और बेकवर्ड

क्लासिज के लोगों पर होती है। योजना खर्च का अनुमान बढा–चढ़ा कर दिया जाता है जिससे आमदनी मे कमी होती है मौर खर्च ज्यादा हो जाता है। ग्रामीण विकास में 12 करोड़ रुपये की कमी हुई। अध्यक्ष महोदय, ये कागज पर खर्च दिखा देते हैं, वास्तव में कोई कार्य कहीं नही होता है। खर्च मैं जो कटौती होती है, वह ग्रामीण विकास में से हो जाती है। ये किसानों के विकास और भले की बात हांकते है, आखिर में जो कटौती होती है वह किसानों और गरीब लोगों पर पड़ती है। इस वर्ष की योजना से अगले वर्ष की योजना को बढ़ा कर दिखा या गया है, यह सब एक छलावा है। अध्यक्ष महोदय, 1994–95 मैं कैपिटल एक्सपैडिचर 252 था जब कि 1995–96 में कैपिटल एक्सपैंडिचर का संशोधित अनुमान 262 करोड रुपये हुए। खर्च में 11 परसैंट की बढ़ौतरी है लेकिन कमितों में जो बढ़ौतरी हुई है, वह पिछले साल के मुकाबले 15 परसैंट है। अध्यक्ष महोदय जो 4,349 करोड रुपये का खर्च अनुमानित है, उसमें से 30 करोड़ रुपये की राशि मानेसर जापानी ग्राम विकास सुविधा के नाम पर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का, या हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक क्हा पर जाने की नहीं सोच सकता, वह उनके स्वाधीनता और स्वावलम्बी के नारे पर चोट करता है। ये 30 करोड़ खर्च कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश या हिन्दुस्तान के लोगों को इससे कुछ भी लेना देना नही है, उल्टा उससे नुकसान ही होगा। सिंचाई के लिए 1,800 करोड़ रुपये का वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है, जिसमें से ज्यादातर स्टाफ की तनख्वाहों तथा अन्य खर्ची के लिए खर्च किया

जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चर्चा चलती है कि वर्ल्ड बैक से पैसा आ रहा है, खर्च का प्रावधान कहां से रखा गया है, वह पैसा आएगा वर्ल्ड बैंक से। अध्यक्ष महोदय, कोई भी पैसा किसानो के विकास के नाम पर किसी मद में खर्च मैं दिखाने की चेष्टा नहीं की गई है। 65 करोड़ रुपये यमुना नदी के किनारे पर बसे शहरों की सफाई और बेहतरी पर खर्च होगा और वह पैसा बाहर के मुल्कों से आएगा। इस काम के लिए जापान से 65 करोड रुपया आना है। यदि इनकी स्कीम इस तरीके से चलती रही तो प्रदेश का विकास कैसे होगा?

अध्यक्ष महोदय, बिजली का मामला बड़ा अहम् मामला है। 170 करोड रुपये के अतिरिक्त कर लोगो पर लगाये गये हैं। इस अतिरिक्त कर के बोझ से लोगों का लाद दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की उत्पादन लागत को कम करने की बजाय इसके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और बिजली बोर्ड का घाटा निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है जिमको पूरा करने के लिए जनता पर निरन्तर टैक्स लगाए जा रहे हैं। 110 करोड रुपये का रूरल इलैक्ट्रिकल सबसिडी का और 337 करोड़ रुपये महकमो का बकाया है। जैसा मैंने बताया है, इसके बावजूद पानीपत थर्मल प्लांट में 100 करोड़ रुपये की मशीनरी का प्रस्ताव किया है जबकि बोर्ड के पास पैसा ही नही है। जिन अधिकारियों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसे घपले किये है, सरकार को उन्हें सजा देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आइजनबर्ग कम्पनी का जिक्र भी किया गया और मुख्य मंत्री जी ने

कहा कि 1.92 रुपये प्रति यूनिट बिजली हमें उससे मिलेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यह बिजली पड़ेगी। (विघ्न) (इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट के इन्ट्रैस्ट को छगन में रखते हुए अगर कोई अधिकारी इन्हें कोई बात कह देता तो उसको ये खुड्डे लाईन लगा देते हैं और अगर कोई बेइमानी करता है तौ उसको इज्जत देते हैं। उसका परिणाम यह है कि आज कहीं पर भी बिजली नही मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कलकत्ते की एक पीयरलैस कम्पनी से 300 करोड़ रुपए साढ़े 16 प्रतिशत के हिसाब से लेने की सोच रहे हैं। अगर कोई अफसर इम बात के लिए आपत्ति करे तो उसको खुड्डे लाईन लगा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के ऐसे तो हालात है। उपाध्यक्ष महोदय, 1992– 93 के मुकाबले में इन्स्टालड कपैसिटी तो बढा है लेकिन बिजली का उत्पादन 40 करोड़ यूनिट कम हुआ है। यह तो आपकी मैनेजमैंट क्षमता है। अब इजराईल की कम्पनी के बारे में बताया गया था और बड़ी डीग मारी गई थी कि बड़ी ही अच्छी कम्पनी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कम्पनी वर्ल्ड व्यापार में ब्लैक लिस्टिड है, उस कम्पनी के साथ इन्होंने समझौता किया है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होने कहा है कि यह ब्लैक लिस्टिड कम्पनी है। इनको बात सोच समझ कर कहनी चाहिए। फिर नही तो इसी मामले के बारे में एक कमेटी बनाकर इन्कवायरी करवानी

पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो गलत ब्यानी। कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। क्या यह सरकार ऐसा काम करेगी, क्या हमारी सरकार किसी ब्लैक लिस्टिड कम्पनी के साथ बात करेगी? उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया की जो पांच बड़ा कम्पनियां है, यह कम्पनी उन में से एक है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः हम अपने अधिकारों से हाऊस में आए हैं, किसी के रहमोकर्म पर नही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने बहुत ढींग मारने की कोशिश कीर थी।

चौधरी भजन लालः यह तो आगे चलकर जनता बता देगी।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः आगे चल कर क्यों, तुम अभी आओ। मैं भी रिजाईन देता हूं और तुम भी रिजाईन दो और दोनों हल्कों में चुनाव करवा कर देख लो। हम तो सभी रिजाईन दे देते हैं, तुम अपनी बात करो। (शोर) तुम क्या बढ़चढ़ कर बात करते हो कि कमेटी बनाएंगे और यह करेंगे, वह करेंगे। जैसे किसी पर एहसान करते होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हें कंट्रोल करें। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप कुछ बोलते हैं तो सुनने की भी हिम्मत रखें।

श्री उपाध्यक्षः चौटाला जी, आप अपनी बात कीजिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इजराईल की कम्पनी के बारे में बात कर रहा हूं कि इस हाऊस

को गुमराह किया जा रहा है। हमने इनसे एम० ओ० यू० बार–बार मांगा, प्रैस के लोगो ने मांगा ओंर ये उसकी कापी भी नही दे पाएं? इसके बाद फिर प्रोमिजरी एग्रीमैंट हुआ और उसकी भी कापी ये नहा दे पाए और अभी भी हाऊस को गुमराह किया जा रहा है कि यह बात ही लाभप्रद समझौता है। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त आप भी बैठ हुए थे और मैंने इनसे पूछा था कि किस प्रकार से इसको लाभप्रद बनाने जा रहे हैं, जबकि बिजली के उत्पादन पर प्रति यूनिट साढ़े चार रुपए खर्च आएगा। मलेशिया की एक कम्पनी ने ने 2.4 करोड़ मैगावाट के हिसाब से दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मलेशिया में एक विदेशी फर्म ने इसी प्रकार का साढ़े सात सौ करोड़ का एक प्रोजैक्ट लगाया, है जो कि 2.4 करोड़ मैगावाट के हिसाब से हुआ है। जबकि हमारी यहां पर एक बहल कम्पनी है, जिसने इनको तीन करोड़ से कम की आफर दी हुई है जोकि हमारे देश की अपनी ही कम्पनी है, जिसका रिकार्ड बहुत ही अच्छा है, जिसके इंजीनियर भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये उसको कान्ट्रैक्ट दे देते तो देश का पैसा विदेश में न जाता बल्कि देश मे ही रहता। इतना पैसा मुल्क मैं रहना था लेकिन उससे सौदा करने के बजाए इस प्रकार की कम्पनी से सौदा कर लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हजारों करोड़ों रुपयों का घपला किया गया और इसी वजह से बोर्ड का घाटा 1, 800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आज प्रदेश की सम्पत्ति को लूटा जा रहा है और इसी कारण आज इस प्रकार की साजिशे रची जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल पावर प्लांट के बारें में इन्होंने

कहा किं सरकार ने अखबारों में टेंडर काल नही किए। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह बात इंजीनियर्ज की मीटिंग में कही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब टैंडर अखबारों मे आए हैं. तो फिर ये क्यों कह रहे है कि हमने टैंडर नही काल किए है?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): कहा टैंडर कॉल किए हैं, आप दिखाएं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: बता देंगे आपको दिखा देगे। (विंध्य) सर, अब ये कहते है कि वह कम्पनी बहुत अच्छी है, लगता है इस कम्पनी के साथ रनकी पूरानी पार्टनरशिप रही है लेकिन इनको ज्ञान नही है कि केन्द्र के उर्जा मंत्री से भी पूछा गया था कि आपका इस कम्पनी से क्या ताल्लुक है? पता नही सरकार के पास वह पत्र है या नही, सरकार के पास वह पल आया है या नही आया है। केन्द्रीय उर्जा मंत्री का भी सुझाव है कि आप बिजली के मामले में इस कम्पनी. से कोई सौदा न करें। उपाध्यक्ष महोदय, ये उस लैटर कों दिखाए। लेकिन ये तो हाउस को और हरियाणा को गुमराह कर रहे हैं। स्टेट का नुक्सान हो रहा है। हमें एम ० ओ० यू ० की और प्रोमोसरी ऐग्रीमैंट की कौपी नही दी गयी और न ही ग्लोबल टैडर काल किए जाते हैं, यह कह देने है कि जब मौका आएगा, दे देंगे और हम यह मुनाफे का सौदा करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह सें कृषि के वारे मे हैं। अगले वर्ष की योजना मे इस वर्ष के मुकाबत्ने मे कृषि पर खर्चा 6.4 परसैन्ट अधिक दिखाया गैया है हालांकि योजना की कुल

बढोत्तरी 21 परसैन्ट ही हैं। यह सरकार ऐंग्रीकल्चर के मारे में कुछ नहीं कर रही हैं। सरकार की जो मंशा है वह स्पष्ट दीख रही हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज के बारे में इनकी पालसी है। इन्डस्ट्रीज में सबसिडी की ये बात कहते हैं कि हम सबसिडी देने जा रहे हैं। मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अभी सबसिडी के कितने क्लेम बकाया हैं और किन किन जिलों में सबसिडी दी गयी है? सर, अपने आदमियों और अपने चहेते ओफिसर्ज को ही यह सबसिडी दी गयी हैं। आप बतायें यह सबसिडी कहां पर दी है और कहां पर नहीं दी है लेकिन यह कभी भी हाउस में नही बताया जाता है, केवल गुप्ता जी ने आकड़े दिखाने की कोशिश की है कि इतने रुपये हमने सबसिडी के लिए रखे हैं लेकिन सर, वह सबसिडी कहां जाती है इतना तो कम से कम हाउस के सामने आना चाहिए। इसी प्रकार से क्रेडिट और डिपोजिट के बारे में बात आती है। यदि सरकार सौ रुपये जमा करती है तो केवल इनको 51 रुपये का ही केडिट मिलता है। आज हमारी यही क्रेडेबिलिटी रह गई बै कि अगर सरकार की तरफ से सी रुपये बैक में जमा होते हैं तो उसे केवल 61 रुपये ही मिलते हैं यानी हमारी स्टेट का प्रोफिट दूसरे स्टेट्स, जैसे अधि प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र उठा रहे हैं, इनके मुकाबले में कम है। (घंटी) सर, अभी तो मुझे बोलते हुए केवल दस मिनट भी नहीं हुए हैं। इसी तरह से परसों मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने एम० एल० एज० के लिए बीस लाख रुपये दे दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से हाउस को गुमराह किया जा रहा है? यह तो वह पैसा है जो डिस्ट्रिक्ट

प्लानिंग बोर्ड पर पहले खर्च होता था लेकिन यहां पर हमें बहकावा दिया जा रहा है कि हम एम ० एल० एज० को पैसा दे रहे हैं। मैंम्बर जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि यह पैसा खर्च क्यों नही किया जा रहा है तो एम० एल० एज० क्या जबाव देंगे, क्योंकि एम० एल० ए० के काम की लिस्ट के मुताबिक अधिकारी इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में छलावा किया जा रहा है।

12.00 बजे

इसी तरह से आज प्रदेश में ऐजुकेशन की हालत हो गई है क्योंकि 1994 का स्कूल में पास होने वाले लड़कों का प्रतिशत केवल पांच प्रतिशत ही रहा है जबकि सरकार ने कहा कि नकल रोकने पर हमने बहुत पाबंदी लगायी है। लेकिन जिस सुशीला कुमारी टीचर ने नकल रोकने की कोशिश की थी, उसका क्या हश्र हुआ है, यह बात ये स्पष्ट नही कर पाए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के आदेश का पालन करते हुए अगर अध्यापक नकल रोकने की कोशिश करें तो उनको मार दिया जाता है। उनको मारने वाले लोग सरकारी संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं लेकिन उनके खिलाफ सरकार कोई भी ऐक्शन नहीं ने रही है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, रणबीर सिंह सुहाग का मामला है, वह भी अध्यापक हैं और वह अच्छा काम कर रहा था लेकिन उसका भी वहीं हश्र हुआ है। सरकार के इन कामो का ही परिणाम है कि रिजल्ट केवल पांच प्रतिशत ही बना रहा। इसी तरह सें उपाध्यक्ष

महोदय, ये सैनीटेशन की बात करते है। गुप्ता जी ने अपने भाषण मे इसका जिक्र किया है। गांव मे सैनीटेशन पर कोई भी पैसा खर्च नही किया गया है, क्या गुप्ता जी गांव की सफाई के लिए कोई प्रावधान करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आज गाव सड़ रहे है लेकिन इन्होने अपने बजट में कही भी यह दिखाने की कोशिश नही की कि हम रूरल एरियाज में कितना पैसा खच' करने जा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़ा दावा करते है हरिजनो के उत्था न का। कहते है कि 80 लाख रुपया केवल हरिजन बस्तियों पर खर्च करने की सरकार की योजना है। केवल माल 80 लाख रुपये में आज इस महगाई के युग में, किला गांव की गलियों का पक्का हो पाना भी मुश्किल है कहां यह हरिजनों की बस्तियों का उत्थान करने जा रहे हैं ? उनको लड़ाने की बात जरूर करते हैं, विकास के क्रोमों में रुचि नहीं है इसमें भी छलाबा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के उत्थान की. बात को लेकर इन्होंने 1994–95 में 68 हकार परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन दिसम्बर तक केवल 20,173 परिवारो को लाभ पहुंचाया है। कहां 68 हजार परिवार कहां 20 हजार परिवार। इसी प्रकार से इंदिरा आवास योजना के तहत 1, 707 मकान हरिजनो के लिए बनवाये थे लेकिन केवल 868 मकान ही बना पाए है जो 50 प्रतिशत है। यह हरिजनों के उद्धार की बात करने वाले हैं। जब उनके विकास करने का प्रशन आता है तो उनके साथ यह सलूक किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अप्रैल से लाटरी बद करने की बात कही है, अब पता नही यह बन्द कर रहे है या अप्रैल फूल बना रहे है। खैर हम मान लेते हैं कि बंद कर रहें है तो दूसरे प्रदेशो को लाटरी ये क्यो अला ऊ कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार को वढ़ावा देंगे। अपने मजूरेनजर लोगों को फा यदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन जो लोग लाटरी' से बर्बाद हो रहे हैं, जिन्होने स्युसाइड कर लिया उचका तो विनाश हो गया। क्राइम बढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने लॉटरी लेनी है, वे तो लेंगे ही, सरकार को भी इससे लाभ नहीं होने वाला है इसलिए इसे बन्द कर देना चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिऐ बता दू कि स्टेट की लॉटरी एक अप्रैल से बन्द कर दी है, बाहर की जो लॉटरी है, इसके लिए भारत सरकार का ऐक्ट है इसलिए हम किसी बाहर की लाटरी पर बैन नही लगा सकते, केवल स्टेट गवर्नमैंट टैक्स लगा सकती. है ताकि बाहर की लाटरी यहां आकर न बिके। टैक्स का रेट और बड़ा सकतै हैं। स्टेट गवर्नमैंट बैन नही लगा सकती इस रात का ज्ञान इनका होना चाहिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः बजट में रोड ट्रासपोर्ट की बात की लई है। ऐक्सप्रेस बस सर्विस के किराए 25 प्रतिशत बढ़ा दिए, इससे सरकार को नुकसान ही रहा है। बसें सडक पर वाली जा रही हैं, जनता को किसी किसी पर भी सस्ती सवारी उपलब्धा

नही है। उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडू की जो सेमी डीलक्स बसे है, उनका किराया 17 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से है और हमारे यहां का 37 पैसे पर किलो मीटर के हिसाब से है। लोगों को सवारी उपलब्ध नही है और ये भागते जा रहे है। इस प्रकार सरकार के खजाने में भी पैसा नही आ सकता। इकोनोमिक सर्वे के पृष्ठ 21 पर आप पढ़ ले। वर्ष 1990 मे 497 डिग्री होल्डर. इंजीनियर्ज हरियाणा प्रदेश मे अनइम्प्लायड थे। आज सै 8 महीने पहले 30–6– 94 को डिप्लोमा होल्डर्ज की सख्या 1123 थी और अब 4425 तक चली– गई और दूसरी अन–सक्लिड लेबर है इस बारे मे आप अन्दाजा लगाईये कि आई० टी ० आईज० ट्रेन्ड की संख्या पहले 260102 थी जो अब 28645 और बढ़ गई है। इस प्रकार से अन–इम्पलायडज की संख्या बढ़ रही है। मांगे राम जी की किताब के दिये हुए आकड़ों को ही मैं दर्शा रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हू। अभी यहा पर सड़कों का भी जिकर आया। इनके अपने किताब के आकडे हैं, वही मैं बता रहा हूं। हो सकता है गुप्ता जी ने ध्यान सै ये आकड़े पढ़े न हो। सड़कें बनाने की बजाये 181 किलोमीटर समथिग सड्कों को डिसमैंटल किया गया है। यह इनकी इकानामिक सर्वे रिपोर्ट पेज 17 कहती है। जितनी सड़को का जिकर किया गया है, उनकी मुरम्मत नहीं हुई है और नई कोई सड़क बनी भी नही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार का ध्यान सड़के बनाने मे कम रहा और डिसमैंटल करने मे ज्यादा रहा। डिसमैंटल करने में सरकार नें अपनी दिलचस्पी खूब दिखाई है। (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा पूरा समय हुआ ही नही है। अभी मैं अपने आगामी दो चार प्यायंटस पर आ रहा हू और जल्दी ही समाप्त. करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत ही उदार दिल है। मैंने तो आपको कई बार अध्यक्ष कहकर भी सम्बोधित किया है। आपकी तरक्की की योजना बना रहा था। (हंसी) इतनी सराहना के बावजूद थोड़ा बहुत रहम का खाना आपके पास होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात को कहकर समाप्त करता हू।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे मे भी जिक्र करना चाहूंगा। चौधरी बीरेन्द्र सिंह यहां पर बैठे हैं, जरा ध्यान देवें कि इन्होंने 1 रुपये 92 पैसे पर यूनिट बिजली का रेट बतलाया, बिलिंग चाजिंज का रेट बतलाया 1 रुपया 30 पैसे पर यूनिट, ट्रासमिशन का एक रुपया पर यूनिट, अनफोरसीन का 26 पैसे पर यूनिट। मै इनको बताना चाहता हूं कि ट्रासफारर्मज और कोयले के रेट्स के साथ बिजली का रेट्स भी बढ़ेगा ही। इस प्रकार यह 4 रुपये 47 पैसे पर यूनिट खर्चा बैठता है। यह सब इनके अपने बताए हुए आकडों केर अनुसार फिगर्ज बैठती है।

इसी प्रकार चुनावों की भी बड़ी ढींग मार रहे थे मुख्य मस्ती महोदय कि बड़े ही फेयर चुनाव करवाए गये। इसी प्रकार लोकल बाडीज और पंचायतों का जिकर भी यहां पर आया और इन्होंने कहा कि चुनाव फेयर और अच्छे हुए हैं लोगों ने इन चुनावों की बड़ी प्रशंसा की है। भजन लाल जी ने अपने आईडैन्टी,

कार्ड का भी जिक्र किया। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार घन्टी बजा रहे हैं। मैं बस जल्दी ही अपने एक दो प्वांयट कहकर समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा, आप स्वयं भी चुनावो से जुड़े रहे है। जिस प्रकार से वोटे बनी, वार्ड बने, वार्ड काटे, ऐसा करके सरकार ने लोगों के साथ कितना भद्दा मजा क किया है। पंचायत समितियों की तो सीकरेट वोटिग करवाई और जिला परिषद के चुनावो में हाथ ऊपर करके शो–अप तरीके से वोटिग करवाई। इसी तरह से मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि हमें म्युनिसिपल कमेटियों के चुनावों में 85 परसैन्ट वोट मिले, हैं। 25 म्युनिसिपल कमेटियां ऐसी हैं जिनमें एस०जे ०पी०के पदाधिकारी चेयरमैन है पाच में बी ० जे ० पी ० के है और 9 मे निर्दलीय है। इनके केवल 19 है और वे भी जोड़ तोड़ के हिसाब से हैं, कांग्रेसी वे लोग भी नही है। (शोर) युंही इस तरह की बाते कहकर हाउस को गुमराह कर रहे है। आखिर इस हाउस में कोई बात तौ साफ होना चाहिए। (शोर) इस तरह से आगे मैं बताना चाहता हूं ' कि एक पुराना ब्लाक ऐसा है जहां पर पंचायत समिति के चुनाव नही हुए है। इसी तरह से अम्बाला के चुनाव भी नही हो पाए है। यहां पर एक परम्परा बनती जा रही है कि इस हाउस में गल्त ब्यानी की जाए। यह प्रथा केवल ट्रेजरी बैचिज तक ही नही है बल्कि दूसरे बैचिज तक भी चली गई है। जैसे साहबी नदी के बांध का जिक्र आया था, तो चौधरी बंसी लाल ने कहा था कि 40 करोड़ रुपये बेकार में खर्च ही गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय जितना फ्लड से नुक्सान हुआ था, उसके दृष्टिगत यह

पैसा रखा गया था। बाद मे राजस्थान ने बांध बांध कर इधर पानी नही आने दिया। ये इस बात को भूल गए कि जब ये एस० वाई० एल० नहर को बनाने लगे थे तो पहले इनको नहर पंजाब मे बनाने की कोशिश करनी चाहिए इन्होने उस नहर को हरियाणा प्रदेश मे पहते बना कर सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा में फ्लड आता है तो प्रदेश बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा, जब राजवीर नाम के व्यक्ति के बारे मे बात आई तो ये उससे मुकर गए। कम से कम बंसी लाल जी आपने जो बात कहा थी उस पर तो आपको कायम रहना चाहिए। अगर राजनैतिक लोग अपनी विश्वसनियता खत्म कर लेंगे तो कल को प्रैस वाले कहगे कि लिख कर दो। फिर बंसी लाल जी कहते हैं कि एमरजैसी ठीक थी, बहिन भाई को नंगा करना ठीक था तो फिर राज वीर वाली बात को क्यों नहीं मानते? मैं चाहूंगा कि हाउस की कुछ परम्पराएं रहनी चाहिएं। अगर गुनती हो गई हो तो उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं पसर्नल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हू। यह बात बिल्कुल गलत है कि मैने उसको अपनी पार्टी मे एडमिट किया है। वह मेरे को कहने तो कुछ और आया था लेकिन वहां आ कर कहानी घड्ने लग गया।

प्रैस वालों ने खुद लिखा है कि मैंने उसको धमकाया था। फिर इन्होंने बहिन भाई को नंगा क्रने का जिक्र किया तथा एमरजैसी का जिक्र किया। मैं समझता हू कि वह एमरजैसी तो 19 मही ने रही लेकिन सनके राज मे तो फैन चार साल हरियाणा मे एमरजैसी रहा। (हंसी) अभी मेहम के लोग इनको भूले नही हैं। आपको गल्त फइक हो गई है, आप मदीना का रास्ता छोड़ कर बाया लाखन माजरा मेहम पहुचे थे। एक बात चौटाला साहब ने कही कि हरियाणा में बाढ़ आई थी इसलिये बांध बनाया गया था। अगर हरियाणा मे बाढ़ आर्ड थी तो ऐसी स्थिति नही आई थी कि मसानी बांध बनाना पड़े। वह तो दिल्ली को बचाने के लिए बनाया गया था और दिल्ली की सरकार के कहने से वह बनाया गया था। तो इनको वह रुपया दिल्ली की सरकार से बदल करना चाहिए था। वह बांध बनने के बाद हरियाणा में राजस्थान से एक बूंद पानी भी नही आया।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, जब भी' कोई काम शुरू किया जाता है तो हमेशा हैड से शु रू किया जाता है। लेकिन इन्होंने एस ० वाई० एल० को टेल से इसलिए बनाया था कि उसमें मे कमिशन मिलेगा। इन्होने पजांब मे, हैड से इसलिए काम शुरू नहीं करवाया क्योंकि पंजाब में जो कस्ट्रकशन होती है, उसका काम वही स्टेट करती है। हरियाणा मे इसलिये बनाया गया था कि यहां जो कस्ट्रकशन होती' है उसको अपनी स्टेट के लोग करते है। जनाब को कमिशन मिलना था, जिस

प्रकार पंजाब इलैक्ट्रिस्टी बोर्ड के रिजैक्ट हुए खम्बे लिए थे और उनमें इनको कमिशन मिला था, उसी प्रकार मे कमिशन खाने के लिए इन्होने उल्टे। गंगा बहाई थी।

श्री बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का यह कहना कि मैंने कमिशन खाया था और पंजाब से रिजैक्टिड पोल खरीद लिए। यह सवाल नही है। मैं कमिशन नही खाता मैं तो दो रोटी खा ता हूं। कमिशन खाने का काम चौटाला साहब का है, मेरा नही है, ऐसा काम ये करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह नहर हरियाणा प्रदेश के हिस्से में न बनती तो क्या हम पंजाब वालों सें पानी मांग सकते थे ?

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): उपाध्यक्ष महोदय, जहा तक मसानी बैराज बनाने की बात है। यह बैराज बना कर चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने मेरे हल्के के 14 गांवों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद कर किसानों को बर्बाद कर दिया वैसे तो यह लोग किसानों के हित की बात करते हैं परन्तु उस समय इन लोगों ने किसानो का अहित किया। उन गांवों के लोगों के साथ इन्होंने जितनी ज्यादती की है, उतनी और कोई नही कर सकता।

श्री धीरपाल सिंहः चौधरी भजन लाल जी आप भी 1978 में मंत्री है। उस समय ढांसा बांध बना कर बहादुरगढ़ और झज्जर

तहसील के लोगो को तबाह कर दिया। दिल्ली वालों ने बाढ़ का एक बूंद पानी भी दिल्ली में नही जाने दिया। इसलिए मसानी बांध बनाना जरूरी था। आज आप कहां कहा से लोगों को ला कर इधर उधर की बात करवा रहे हैं। (विध्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ): उपाध्यक्ष महोदय, सदन मे हमारे सक्ष्म विष्य मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने वर्ष 1995– 96 का प्रगतिशील बजट पेश किया है इसलिये वे बधाई के पात्र हैं। यह बजट इस सरकार की सामाजिक एव आर्थिक विकास के प्रति वचनबद्धता कौ दर्शाता है। उपाध्यक्ष महोदय, समस्त हरियाणा भली भांति जानता है कि वर्ष– 1991 में हमारे आदरणीय चौधरी भजन ताल जी के नेतृत्व मे हमारी इस लोकप्रिय सरकार का गम हुआ था। उस समय हमारी सरकार का यह नारा था और यह प्राथमिकता थी कि हम सारे प्रदेश के अन्दर सारे प्रदेश की जनता को साथ ले कर विकास के काम करना चाहते है और निष्ठा के साथ सारे प्रदेश में अमन और शांति के साथ प्रदेश के अन्दर चहुंमुखी विकास करेंगे। आज मैं कख के साथ हमारे आदरणीय मुख्य मैली जी को यह बधाई देना चाहता हुं कि जिस समय से हमारी सरकार बनी है उस समय से हरियाणा प्रदेश चहुंमुखी विकास की तरफ निरन्तर गति के साथ बढ़ रहा है उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पाव है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जनित है कि यह वर्ष हम राष्ट्र– पिता महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती का मना रहे है। समस्त हरियाणा प्रदेश के अन्दर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में अनेकों कार्यक्रम हरिजन से ले कर ऊपर की जाति तक के सभी समुदाय के लोगो के लिए, सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समस्त दुनिया में महात्मा के नाम से जाने जाते है। हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर फख्र है। उन्होंने न केवल भारतवासियो के पिछड़े हुए लोगों के लिए आवाज उठाई बल्कि उन्होंने समस्त दुनिया के पिछड़े हुए लोगों के लिए आवाज उठाई। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 12 रवी जयन्ती मनाकर हरियाणा ललकार ने एक बात ही सराहनीय कार्यक्रम शुरू किए है, इसके लिए हमरि। हरियाणा सरकार बधाई की ताऊ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हु कि संविधान के अन्दर जो 73 वां व 74 वां संशोधन किया गया था, वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावैज है। इस अमैंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, व इन्दिरा गांधी जी ने के सपने साकार हुए हैं। इस अमेंडमेंट के जरिए ऊपर के लैवल से लेकर नीचे ग्राम स्तर तक राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ है। उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए. यह संशोधन किया गया था और उसी संशोधन को कार्यान्वित हरियाणा सरकार ने किया है। अभी हाल ही में जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए हैं और जो शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ है, वह अपने आप में एक इतिहास है। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। पहले लोग सिर्फ विधायको तथा एम ० पीज० तक ही

शक्ति का केन्द्रीकरण मानते थे लेकिन अब इन चुनावों से लोग फख्र के साथ कह सकते है कि शक्ति में उनका भी हिस्सा है। ये चुनाव चाहे जिला परिषद के थे, चाहे म्युनिस्पिल कमेटी के थे, या ब्लाक समिति के थे, या ग्राम पचायतों के थे, इनसे सभी को अपनी अपनी शक्ति का पता चला है। इसलिये 73वां व 74वां संशोधन अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज हए। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इस काम मे सारे देश के लिए एक अच्छी उदाहरण हरियाणा प्रदेश बना है और इसका नाम सबसे ऊपर आया है यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। इस अधिनियम का दस्तावेज सबसे पहले लोक सभा में रखने का श्रय हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल जी को जाता है, ये केन्द्र में कृषि मंत्री थे तो उन्होंने यह दस्तावेज उस समय लोकसभा में पेश किया था, यी समस्त हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के कई नेताओं ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए और बजट पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि सदियों से, वैदिक काल से इतिहास उठा कर देख ले कि कानून व्यवस्था में कहीं न कही थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। लेकिन असल सवाल यह है कि जो मौजूदा सरकार है, वह कानून का उल्लंघन करने वाले के प्रति कैसा रवैया अख्तयार करती' है आया उसको

दण्डित करती है या नही? मैं अपनी हरियाणा प्रदेश की सरकार को बधाई देता हू कि हरियाणा में कानून व्यवस्था सारे देश से सबसे बढ़िया है। कानून व्यवस्था के बारे में हमारे विपक्ष के कई साथियों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए गल्त आरोप लगाए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे मे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भार सामान्यत हमारे कर्तव्यपरायण अधिकारियों के कन्धों पर आता है। ये व्यूराक्रेटस जो आई० ए० एस०, आई० पी ० एस०, एच० सी० एस० बनते है यह केवल डिग्री ले कर ही नही बन जाते, बाकायदा उनको 24 घण्टों में से 18– 18 घण्टे पढ़ना पडता है, तब, कही जा कर वे इस योग्य हो पाते हैं कि इन पदों पर आए। हमारे कई साथी जो यूनिवर्सिटी और कालेज में हमारे साथ पढ़ते रहे हैं उनमें से कुछ लीडर बने तो कुछ आई० ए० एस०, आई० पी ० एस०, आई० एफ ० एस० और टैक्नोक्रेट आदि बने है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि इतने मेहनती और ईमानदार व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर व्यूरोक्रेटस के रूप में आते हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्यांयट आफ आर्डर है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई ऐसी बात नही कही ये किस बात पर ये प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे

निवेदन करूंगा कि ये मुझे बोलने दे और बाप में इस प्रकार से मुझे मेहरबानी करके इन्ट्रप्ट न करे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः सम्पत सिह जी, आप का क्या प्यायट आफ आर्डर है?

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, मेरे काबिल दोस्त ने प्रशासनिक अधिकारियो के बारे मे कहा। इसमें कोई दो राय नही कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए बहुत मेहनत और काबलीयत की जरूरत होती है और हरियाणा के अधिकारी मेहनती और काबिल हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, हमारे काबिल 11 एच ० सी ० एस० अधिकारियों को आई० ए ० एस० की लिस्ट में डाला गया था और उनकी सिलैक्शन की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी सिलैक्शन हुए साल होने जा रहा है लेकिन उनको अब तक पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है ? एक साल के बाद तो वह लिस्ट लैप्स हो जाएगी। उनको आई० ए० एस० की लिस्ट में पोस्टिंग क्यों नही दी जा रही है?

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है, आप बैठे।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। हमारे माननीय श्री बिसला साहब जी अभी प्रदेश में कानून और व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे। ये पूरे राज्य के बारे में तो बात छोड़ दें, केवल फरीदाबाद जिले में ही इतने ज्यादा

रैपस, हत्याए और डकैतियां हो रही हैं कि जिसका कोई अन्त नहीं।

श्री उपाध्यक्षः दलाल साहब, यह कोई प्वायट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महॉदय, हमारे साथी. चौधरी कर्ण सिंह दलाल तथा प्रो० सम्पत सिंह जी ये एक तरीका बना रखा है कि जो बोले उसको इन्ट्रप्ट किया जाए, ये अनावश्यक रूप मे मुझे टोक रहे हैं और मुझे अपनी बात नही कहने दे रहे है, इसलिये आप इन्हें रैस्ट्रेन करने की मेहरबानी. करे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मै निवेदन कर ग्हा था कि सजपा और विकस पार्टी के लोगों का तरीका रहा है कि ब्युरोक्रेटस तथा प्रशासनिक अधिकारिया पर निराधार एलिगेशज जगा कर उनको डी–मोरेलोईज कियो जाए। ये एलिगेशन्ज उनकी वर्किग के कारण से नहीं लगाए जा. रहे बल्कि ये अधिकारियों को गलत काम करने के आदेश देते थे और जौ अधिकारी इनकी बात नहीं मानते थे, उन पर ये निराधार एलिमेशन्ज लगा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा अभियान चलाया जाना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए लेकिन जो लोग ईमानदारी और काबलियत से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, उनके बारे मे कभी भी गलत शब्द नही कहे जाने चाहिए। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय, एग्जाम्पल के रूप मे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मे व्यूरोक्रेटस डी–मोरेलाईज हो

जाते हैं, वहां पर हालात खराब होते हैं जिसकी वजह से आतंकवाद पनपता है। आज देश की एकता और अखण्डता के लिए आतंकवाद एक भारी खतरा बना हुआ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन डी–मोरेलाईज हो जाए तो कानून–व्यवस्था को बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी बसी. लाल जी., कर्ण सिंह दलाल, चौधरी सम्पत सिंह जी से निवेदन करता हू कि इस प्रकार की बाते करके प्रशासन को –तथा व्यूरोक्रेटस को डी–मोरेलाईज न करें। जिन अधिकारियों को ये पसन्द नहीं करते थे, उन अधिकारियों पर ये फाल्स ऐलिगेशन न लगाए क्योंकि वे अधिकारी यहां पर खुद को डिफैड नही कर सकते है। हमारे जिला के एस० पी ० श्री ० के० के० मिश्रा हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जिला फरीदाबाद के एक तरफ दिल्ली, एक तरफ राजस्थान और एक तरफ यू० पी ० है। वहां पर रातों रात क्रीमिनल आकर के घुसते है और वारदातें कर के चले जाते है। हमारे फरीदाबाद की जो सराऊंडिग है, उसको देखते हुए आज सारे हरियाणा में फरीदाबाद में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने एक एलिगेशन लगाया कि एस० पी ० फरीदाबाद ने लछमण दास डी ० जी ० पी ० साहब को उनके लड़के की शादी में कन्टैसा कार दी है। हमारे भी बच्चों की शादियां हुई हैं, बसी लाल जी के बच्चों की भी शादिया हुई है, पता नहीं उनको कितनी ही कन्टैसा कारे मिल गई होगा त् उपाध्यक्ष महोदय, ये हाऊस का मिसयूंज करके गलत एलिगेशज लगाते है। (विध्न) उपाध्यक्ष

महोदय, ऐसे एलि– गेशन इनको नही लगाने चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको बोलने की इजाजत दे दी है। (श्री कर्ण सिंह दलाल की तरफ से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कर्ण सिंह जी आप किम बात पर बोलना चाहते है?

श्री कर्ण सिंह दलीलः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना है। हमारे माननीय बिसला जी ने जो बात कही है कि ....

श्री उपाध्यक्ष कर्ण सिह जी. जो आदमी अपने आप को हाऊस मे डिफैण्ड नही कर सकता, आपको उसके बारे मे कोई बात नही कहना चाहिए। कर्ण सिह जी ने जिस अफसर की' बात कहीं है उस वर्शन को कार्यवाही से निकाल दें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद मेरा जिला है और बल्लभगढ़ मेरी कास्टीचुएसी है, उसके बारे में मैं कोई बात फक्र से कह सकता हू। उपाध्यक्ष महोदय, अपोजिशन का तो एक सूत्रीय प्रोग्राम है कि सदन की कार्यवाही में बाधाए डाले या किसी भी अफसर को कंडम करने का प्रोग्राम है। मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हू कि जिस प्रदेश के अन्दर ब्यूरोक्रेसी में श्री एच० डी ० बंसल जैसे चीफ सैक्रेटरी हो, वह प्रदेश तो तरक्की करेगा हीं। वे एक ईमानदार और उच्च कोटि के अधिकारी है और उनकी ईमानदारी को सभी जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि

आज सारे देश मे सबसे बढ़िया प्रशासन हरियाणा का है, सबसे अच्छी ला एण्ड आर्डर की स्थिति जो हमारे प्रदेश के अन्दर है, इसका श्रेय भी चौधरी भजन लाल जी को ही जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मागेराम गुप्ता जी ने जिस अच्छी चीज को अपने बजट के अन्दर रखा हैँ वह हे डाईवर्सीफिकेशन आफ ऐग्रीकल्चर।

प्रो ० सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। जैसा कि ब्यूरोक्रेसी की. बात आयी' है, हम यह नही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अच्छी नही है लेकिन मै यह कहना चाहता हू कि जो 11 एच० सी० एस० अफसर, आई० ए ० एस० के रूप मे सिलैक्ट किए है, उनको एक साल होने क्एख बाद भी कही पर पोसटिंग ओर्डर क्यो नई दिए गए है?

Mr. Deputy Speaker : This is not a point of order.

Prof. Sampat Singh : Sir, it is a valid point of order. If Government does not want to give reply तो यह गवर्नमैंट की मर्जी है। मैंने तो अपना प्वायंट रेज करना था, कर दिया है।

सिचाई मंत्री (चौ ० जगदीश नेहरा): डिप्टी स्पीकर साहब, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। इन्होने अपने दो बार प्वायंट उठाए हैं। अगर इसी तरह से सवाल किए जाएगे तो मैं आपसे जानना चाहूगा कि क्या यह क्वैश्चन आवर है?

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह हाउस चलाने का तरीका है। ये क्यों बार–बार इन्ट्रप्ट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गरिमामय सदन के जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, वे कई बार अपनी मर्यादा से बाहर चले जाते है। इस सदन की जो गरिमा है वह तो सभी सम्मानित सदस्यों की सांझी है। ऐसा करके ये लोग प्रैस को और हरियाणा की जनता को कोई अच्छी इम्प्रैशन नहीं दे रहे हैं। हमे अपनी मर्यादा के अन्दर रहकर ही अपने काम करने चाहिएं। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मै अपने समय के अन्दर ही अपनी बात खत्म कर लूंगा। सर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज बड़ी भारी बेरोजगारी है और ज्यादा नौकरियां सरकार लोगो को नहीं दे सकती। हमारी सरकार ने आज इतने अच्छे प्रोग्राम, इतने अच्छे कार्यक्रम बनाए हैं जिन के लिए सरकार बधाई की पात्र है। सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय लिया है कि डाईवर्सीफिकेशन आफ एग्रीकल्चर किया जाए। आप सभी जानते हैं कि आज थोड़ी थोड़ी जमीन पर दस या बारहरू लोग गुजारा करते हैं, लेकिन उनका गुजारा से नहीं होता। सरकार ने कृषि का डाईवर्सीफिकेशन करके एक बड़ा भारी निर्णय लिया है। आज इस निर्णय की बड़ी भारी चर्चा है और इसका बड़ा भारी श्रेय आज की सरकार को जाता है। अभी दिल्ली के अन्दर जो फूलों का मेला लगा हुआ है, उस मेले में मैं गया हुआ था, वहां पर साउथ से भी काफी लोग आए थे, उन्ह ओंरने भी सरकार, के इस निर्णय की. काफी सराहना की है। आज लोग

महसूस करते हैं कि कृषि का डाईवर्सीफिकेशन होना चाहिए। सरकार इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए छोटे छोटे लोन, कम इंट्रस्ट पर लोगों को दे रही है जिसके लिए सरकार बधाई की पाल है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सभी मानते हैं और सदन के नेता ने भी कहा है कि बिजली की समस्या है और बिजली जितना हरियाणा के लोगो को मिलनी चाहिए, उतनी बिजली हम आज नही दे पा रहे हैं। लेकिन मैं सम्पत सिंह से निवेदन करना चाहूगा कि वे जो अपनी रैलियों में, अपने भाषण में लोगों से यह कहते हैं कि सरकार के जो मीटर रीडर चौक करने आते हैं, या जो बिजली की चोरी करने से रोकने हैं, उनको आप मारों। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह अच्छी बात है? बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बिजली कें अन्दर पूरा सुधार हो। जिस तरह के हालात है, लोगों को ये गुमराह करते हैं, नारा देते हैं कि जो कर्मचारी बिजली की चोरी रोकते हैं उन अधिकारियो को मारो, मीटर चौक करने आते है तो उनका घेराव करो। यह तो अपोजीशन के पार्ट पर पुअर रिफलैक्शन है। मैं बिजली के बारे में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आदरणीय मुख्य मक्की जी ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। एक ओर बहुत अच्छी योजना जो हमारे आदरणीय मुख्यमन्त्री जी ने शुरू की है, वह है 'अपनी बेटी अपना धन'। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ –साथ महर्षि दयानन्द भी यही कहते थे कि हमारे समाज मे सबसे ज्यादा उपेक्षित महिला वर्ग है। हमारे समाज मे सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हुआ है, इस शोषण को रोकने का श्रेय

हमारी सरकार को जाता है। चौदहवी तक लड़कियों की शिक्षा और टैक्नीकल एजूकेशन के लिए गरीब हरिजन और बैकवर्ड परिवार की जो बेटियां हैं, उनको स्पैशल वजीफे दिये जाते हैं। यह बहुत अच्छी योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गर्व महसूस करते हैं और उन्होने यह ऐलान किया है कि 'अपनी बेटी अपना धन नामक योजना जो हरियाणा सरकार ने बनाई है, इस योजना को दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी बनाना चाहिए। यह हमारी सरकार की बइत बड़ी सफलता है। शिक्षा के स्तर के बारे में भाई सम्पत सिंह जी, ओम प्रकाश चौटाला और बंसी लाल जी ने बहुत नुक्ताचीनी को है। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और विशेषकर भसई मुलाना जी को बधाई देता हं कि जिन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बहुत ठोस नीतियां बनाई और निर्णय लिये है। नकल को रोकने के लिए भिवानी शिक्षा– बोर्ड ने बड़े अच्छे निर्णय लेकर मास स्केल पर जो नकल होती थी, उसको रोका है, गांव के लोग एग्जामिनेशन सैन्टर्ज पर लाठी लेकर पहुंचते थे। ला एण्ड आर्डर स्टेट में खराब लगता था। आज उस नकल को रोका है और बड़ा भारी सुधार करने में सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी सफल हुए हैं।

अभी यमुना जल समझौते के बारे में बड़ी भारी चर्चा इस सदन में हुई और हमारे विपक्ष के साथियों ने इस पर बड़ी नुक्ताचीनी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यमुना

जल समझौता अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। मैं पिछली बार पी ० ए ० सी ० का चौयरमैन था। भाई जिले सिंह और राम विलास जी मेरे साथ थे। ताजेवाला हैडवर्क्स और हथनीकुण्ड बैराज पर निरीक्षण के लिए हमारी. विधान सभा की कमेटी गई थी। ये जो अपोजीशन की बैच के सदस्य, थे, ये सभी इस विचार के थे कि ताजेवाला हैडवर्क्स का बाकायदा निर्माण होना चाहिए, हथनीकुण्ड का निर्माण होना चाहिये। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पांच स्टेटस के साथ इस ऐतिहासिक समझौते को करवाया है और वह भी तब, जब वहां हमारी पार्टी की सरकार न हो। ऐसा समझौता चौधरी भजन लाल ही करा सकते है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मै उम्मीद करता हूं कि हथनी कुण्ड बैराज का निर्माण शीघ्र होगा। 100 वर्ष से पुराना ताजेलावा हैडवर्क्स है यह कभी भी प्राकृतिक प्रकोप का शिकार बन सकता है इसलिए सरकार इसके बारे में भी ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार घण्टी मार रहे है और इशारा कर रहे है। आपको पता है कि हम कांग्रेस कितने अनुशासित होते हैं? आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने कल जो बजट इस हाउस मे प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हु। मैं इस बात के लिये

सरकार को बधाई देती हू कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं रखा है। हमारी सरकार ने 1250 करोड़ का अनुमानित बजट रखा है जबकि 222.29 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र की तरफ से है। सरकार ने आम आदमी के खाने की चीजों पर जैसै बाजरा है, ज्वार है, पर कोई टैक्स नही लगाया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो सूरजमुखी का तेल है, जिसको आम आदमी प्रयोग में लाता है, खासतौर पर बीमार आदमी इसका काफी प्रयोग करता है, दूसरी स्टेटों की तरह इस पर से सरकार, ने सेल्ज टैक्स हटा दिया है। यह बड़ी ही प्रशसनीय बात है लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहूंगी कि इस बजट के अन्दर खेती के लिये जो पैसा रखा गया है, वह पर्याप्त नही है, वह कुछ कम रखा गया है, पहले से ज्यादा रखना चाहिये था। इसकी निस्बत बिजली. के लिये, इरीगेशन के लिये सरकार ने काफ्ही पैसे का प्रावधान इस बजट में किया है लेकिन आज जो हमारे प्रान्त के अन्दर नहरे अटी पड़ी है उनके लिये मैं समझती हू कि सरकार को ज्यादा पैसा रखना चाहिये था। आज हमें पानी पंजाब की तरफ से क्यो नहीं आ रहा है, इस–लिये एक तो नरवाना के पास और कु छ उधर पंजाब साईड से नहरें अटा पडी है जिस कारण से पाने नही आ रहा है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। हम सब को व लंटैरिली एक आगेंनाईजेशन बनाकर इन नहरों की मिट्टी को हटाना चाहिये ताकि पानी आगे आ सके। नहरों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। मैं आपको बताती हूं कि एक मिट्टी गांव है वहां पर एक टंकी बनी हुई है। इसी सिलसिले में मैने एक सवाल भी दिया

था कि 10 अक्तूबर को पानी गया, उसके बाद 30 जनवरी तक पानी वहां पर नही गया। लेकिन प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने जानबूझ कर यह सवाल आने ही नही दिया इसीलिये मैं उस वक्त बचि मे बोल भी रही थी। जब सवाल पूछने की बात होती है तो दो तीन मिनट मे ही पूछा जाता है लेकिन इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो लैक्चर ही दे डाला, जिस के कारण उस वक्त मुझे बोलने का समय ही नही मिला। मैं यह बताना चाहता हू कि वहां पर साढ़े तनि या चार सालो में केवल 11 बार पानी आया और ज्यादा से ज्यादा पाच दिन या आठ दिन ही पानी आया। इसी गांव के नीचे छ सात गांव आते है जिनमें पानी नही जाता जिसका वजह से लोगो को काफी परेशानी हो रही है। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान देवे। हमारे वहां पर बोरिग वैलज हैं, उनके लिये सरकार ने अलग से कुछ नही किया है। कई जगहों पर मीठा पानी है और गहरा भी है। रिवाड़ी के अन्दर एक ऐक्सीजन है या एस० डी. ० ओ० है, वह तो कभी कुओं को देखने आता ही नही है, परिणामस्वरूप कुएं खराब हो जाते है। इस इलाके मे बोरिंग वैलज ज्यादा है, अगर एक अफसर की अलग से डयूटी भिवानी में भी लग जाए तो बेहतर रहेगा। एक तो टेलीफोन न मिलने की वजह से अफसर भी नही मिलता। इसी' तरह से झाजडा गांव है, वहां पर जो कुआ है, उसको वहां के कुछ बैकवर्ड क्लासिज के लोगों ने ईन्टों और पत्थर डाल कर बन्द कर रखा है, जिसके लिये कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को कहा जा चुका है। मैंने कई बार उसको कहा है लेकिन मैं समझती हू कि आज तक उसको ठीक से

चालू नही पिरो गया है। हवा और पानी तथा बिजली बहुत जरूरी हैं। पता नही ये बोरिग वैल एग ० आई० टी ० सो ० के अंडर है या पीने के पानी में हैं लेकिन उसका अलग से नाम नहीं लिया गया। अगर उसका नाम ले लेते तो आपको हम इम बात के लिए डबरा बधाई दे देते।

इसी तरह से शिक्षा की बात है। सरकार नैं जो साक्षरता अभियान चलाया है, यह बहुत अच्छा है। कहते हैं कि दूत कपूत सो का धन सचे, पूत सपूत खो का धन सीचे। अगर पूत सपूत हो गया तो कमा लेगा वरना खो देगा। तो शिक्षा की भी ऐसी ही बात है। इसी तरह से अपनी बेटी अपना धन की भी अच्छी स्कीम है। इस बारे मे बिसरा जी ने कह दिया था इसलिये मैं कुछ नही कहुगी। आपका आगंनवार्ड का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है लेकिन जो बच्चों के लिये न्यूट्रीशन की चीजे आती है, वे ऊपर ही बंट जाती है। मेरे पास मेरे हल्के का कोई आदमी आया, मैं उसका नाम नहीं लुंगा। कह कहने लगा कि हमारा झगडा हो गया और मेरी मार पिटाई की गई है। मेरे घर वालों ने उसमें पूछा कि क्या बात हो गई। पता चला कि यह झगड़ा इस सामान को बांटने की वजह मे हुआ। तो जो सी ० डी० पी ० ओज० हैं, वे इसको वही खत्म कर देते है। मै चाहती हू कि वह कम से कम बच्चों तक तो जाना चाहिये। यह बहुत अच्छी स्कीम है। इसके तहत मां और बच्चे के लिए न्य्ट्रीशन का प्रावधान है लेकिन कह वही खत्म हो जाता है। जो बात अभी मैंने आपको बताई है, वह हिसार का

वाक्या है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हू कि हमारे जो प्रोग्राम अच्छे तै, अगर वे लोगो तक पहुचते हैं तो लोग खुश होगे। अगर लोगों तक नही पहुंचते तो चाहे जितनी भी अच्छी स्कीम क्यों न बने, उसने लोगो को कोई फायदा नहो होगा। पंचायतों के बारे मे मुख्य मन्त्री जा ने कहा कि उनको स्कूलो का अधिकार देंगे। लेकिन क्या आपने पंचायतो के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है? मैंने तो इस बात को कही देखा नही। मैं चाहती हु कि आगे जे आप सप्लीमैंटरी डिमाडज लाए, उनकें द्वारा पचांयतो के लिए अलग से बजट मांगा जाए। आपने उनको जो अधिकार दिए है, वे तभी मिलेंगे जब आप उनको पैसा देंगे। इसके अलावा, आज कल जो बड़े गांव हैं, उनकी बुरी हालत है। जो गाव के लोग कस्बों मे बसते है, वे चाहे झज्जर हो या रोहतक है, वहां सैनटर का इन्तजाम नही है। इसके लिए मैंने कई वार सुजैशन दिया है। जब तक आप गन्दे पानी को ट्रीट नही करेंगे, तब तक बीमारियां होती रहेगी। मै तो लोगो को हमेशा सलाह देती है कि आपस मैं मिल कर इस काम को कर ले जैसे आपने बिजली के लिए सैल्फ फाइनैसिंग की स्कीम चलाई है, उसी तरह से सैनीटेशन के लिए भी कर दे ताकि बीमारिया खत्म हो जाए। हमारे हल्के मे एक नम्बरदार रूप चन्द है जो फ्रीडम फ्रिडम फाइटर रहे है। उनके दो जवान लड़कों को लकवा लग गया। तो इस तरीके मे ये बीमारिया फैल रही। है। हम यहा पर पैस्टीसाइड के बारे मे कहते हैं कि यह एक अच्छा चीज है लेकिन यह अच्छा नही है। इसका जो छिड़काव होता है उसके परिन्दे खाते है। इसका छिड़काव सब से ज्यादा

कपास के ऊपर होता है। जब कपास पर छिडकाव होगा तो बिनौला दूर कैसे जाएगा, बिनाने पर भी कीटनाशक दवाई का असर आता है। उसका भैस खाती है वह भी बीमार हो सकती है। हम भैसो का घी दूध खाते है, हम भी बीमार हो सकते है। मैने कभी दूसरा घी खाया नही मैने तो भैस का ही घी खाया है। डिप्टी स्पीकर साहब, श्री रामपत बिसलवास गांव के रहने वाले है और वे मेरे रिश्ते में चाचा लगते है। वे कहते है कि उन्होने अपनी फसल मे कभी भी कारखाने मे बनी हुई खाद नही डाली और कभी भी आज तक कपास से किसी कीटनाशक दवाई के छिडकाव की जरुरत नही पडी। उपाध्यक्ष महोदय, विदेशों से जो बजि मंगवाया जाता है उसके साथ कई किस्म कपास का बीज भी आ जाता है। जो पी ० एच० 48 बजि के साथ घास का बीज आया था, जिसको लोग कांग्रेसी घास कहते हैं, उस घास के बाज के आने से हमारे यहां पर वह घास बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होने लग गया शै। मैं यह कहना चाहती हूं कि विदेशों से जो बीज मंगवाया जाए उसके साथ किसी किस्म के घास के बीज नही आने चाहिएं। आपने रूरल डिवैल्पमैंट के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया है, इसकी मुझे खुशी है। जैसे आपने मेवात के विकास के लिए मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया, उसका जो लाभ लोगों को पहुंचना चाहिए वह सभी लोगों को पहुंच नही पा रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि लोहारू से ज्यादा बैकवर्ड एरिया और कोई नहीं है। लोहारू सबसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया है। झज्जर का सालाहावास भी बैकवर्ड एरिया है। बाढड़ा का सतनाली बैकवर्ड छुरिया है। उन एरियाज

की डिवैल्पमैंट के लिये आप चाहे डिवैल्पमैंट बोर्ड न बनाएं, बोर्ड बनाने पर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ज्यादा होगा लेकिन उन इलाकों की डिवैल्पमैंट के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिए, यह जरूरी है। सरकार ने यह बहुत अच्छी बात की है कि एक एम० एल० ए ० अपने हल्के में 20 लाख रुपए विकास के काम पर खर्च करवा सकेगा और एक एम ० पी ० एक करोड़ खर्च करवा सकेगा। यह बहुत अच्छी बात है। आपने एक एम ० एल० ए० को 20 लाख रुपए खर्च करवाने की जो बात की है, उसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देती हूं क्योंकि कुछ काम एम ० एल० ए ० की मर्जी से उनके हल्कों में हो जाएंगे। यह काम सबसे पहले गुजरात स्टेट ने किया था।

अब मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। हमारे यहां सड़कें अच्छी हैं लेकिन फिर भी कुछ सड़कें टूटी हुई हैं। उन सउको में बिचुमैन की हेराफेरी हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में अच्छी सड़कें बनाई गई है, और भी बन खी हैं। इसके अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि बसें इन्टीरियर के गावों तक नहीं जाती। बसें इन्टीरियर के गांवों तक जानी चाहिएं। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन बनाई है, उसका काम सैटिसफैक्टरी नही है। ए ० जी ० ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस कारपोरेशन में अनस्किल्ड लोग ज्यादा भर्ती कर लिए गए है। अगर उस कारपोरेशन में ज्यादा भर्ती करने की जरूरत है तो जो

स्किल्ड लोग मारे मारे फिर रहे है, जे ० ई० बगैरह उनको भर्ती किया जा सकता है। जो लोग इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट से ट्रेनिग ले कर आते है, उनको भर्ती किया जा सकता है मेरे हल्के लोहारू में एक इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है और न ही उसके लिए कोई बिल्डिग बनाई गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से इस बात का जरूर आश्वासन चाहूंगी कि वे कम से कम वहां पर उस स्कूल की बिल्डिग जरूर बनवा दें। वह हमारा बैकवर्ड एरिया है। व्हं पर जो प्रिंसीपल साहब गए, उन्होने यह लिख दिया कि वहां पर इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग स्कूल ही जरूरत ही नही है। एक वहां पर नकई डाक्टर आए, उन्होंने कह दिया कि वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की जरूरत नहीं है। यदि वे लोग इस तरह से लिखते है तो सरकार उनकी इस तरह की बातों को क्यों मानती है। सरकार को उनकी बातो को डी ग्रेड कर देना चाहिए। वह इस तरह की बात इसलिये लिखते हैं क्योकि वे लोग बैकवर्ड एरिया में जाना नही चाहते, इसीलिये तो हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर गए। वे सबसे ज्यादा साउथ को अच्छा मानते थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि गांवों के पढ़े लिखे लड़के भी वहां पर जाना नही चाहते। उनको सरकार को कोई इनसैटिव देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने काफी बच्चो को सर्विस दी है, मैं चाहती हूं कि काफी लोग बेरोजगार है इसलिए और अधिक सर्विस का प्रावधान करना चाहिए।

13.00 बजे

एक बात मैं कोआप्रेशन डिपार्टमेंट के बारे मे कहना चाहती हू। इस बारे में मेरा कहना है कि जो कोआप्रेटिव सोसायटीज है, उनमें किसानों के भी शेयर होते हैं। मैं चाहती हूं कि उनको भी उस शेयर का डिवीडेंड मिलना चाहिए। दूसरे मैं साथ ही साथ यह भी चाहती हू कि कही पर नैचुरल क्लैमिटी यानि ओले आदि पड़ने की स्थिति आती है तो किसानों को तुरन्त सहायता दी जानी चाहिए।

अब मैं पशुधन के बारे में भी कहना चाहती हू। लोग जर्सी गाय वगैरा तो लाते है लेकिन मैं चाहती हूं कि अपने यहां की गाय और भैंसो की नस्ल को सुधा रा जाये ताकि अधिक से अधिक दूध घी हो सके। अब पीछे कुरुक्षेत्र में किसी ने आर्टिफिशियल दूध तैयार किया था लेकिन बाद में वह व्यक्ति पकड़ा गया। मैं चाहती हूं कि जिस गति से आबादी बढ़ रही है उस गति सै दूध की पैदावार भी बढ़ायी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार राजधानी क्षेत्र के तहत कुण्डली में एक फलों की मण्डी बनाने जा रही है, इस बारे में मेरा कहना है कि सरकार को जब कोई ऐसा काम लार्ज स्केल पर करना हो तो उपजाऊ जमीन नही लेनी चाहिए। जो बजंर जमीन है, उसको यूज करना चाहिये। अगर उपजाऊ जमीन ने ली गई तो कल को जिनकी जमीन ली गई है, उनके धार बर्बाद हो जायेंगे। पैसे के चक्कर मे पड़ कर जो उन्हें मिलता है, एक साल तक तो वे गुलछर्रे उड़ाते रहते है, कभी मारूती कार ले लेते हैं या अपने

छोरे छोरी की शादी मे खर्च कर देते है लेकिन बाद मे उनको बहुत दिक्कत आती शै। इस बारे में मैं किसानों को कहतीं हु कि तुम अपनी जमीन मत बेचो, नही तो कप को तुम्हारी छोरियां इन कोठियों मै झाडू लगाएंगी। इस बारे मे मेरा कहना यह है कि यदि सरकार उनकी जमीन लेती है तो कम से कम उनकी जमीन लेने के बदले मैं नौकरी. अवश्य दे ताकि उनका गुजारा हो सके। मैं यह भो चाहती हू कि जो कारखाने बनाये जाते है, वे जी टी रोड पर न बनाकर दूसरी जगह पर बनाएं और उनको जी. टी. रोड. से वहा तक सड्क दे दो ताकि कोई दुर्घटना भी न हो। फ्रांस में ऐसी स्थिति हो गई कि जी. टी. रोड चन्द होते पर फौज की गाड़ियां भी नहीं जा पाई। यहां पर भी ऐसी हालत न हो जाये इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जी. टी. रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और कहीं पर भी पूरे हरियाणा में जीटी. रोड पर पशुओं का कोई क्रासिंग नहीं है। जी टी रोड पर कैटल एप्रोच पूरे हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है। करनाल हिसार बाई पास को कॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। यह बहुत जरूरी चीज है इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सड़क कें पास अगर किसी की कोई दुकान या मकान हो तो उसका मुंह भी जी. टी. रोड की तरफ नहीं करने देना चाहिए। (विध्न)

उपाध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई के लिए जौहड बहुत जरूरी हैं। जब तक इन जौहड़ों में बरसात का पानी इकट्ठा नही

करेंगे तब तक पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलेगा और पशुओं के लिये पीने के पानी की समस्या बनी रहेगी। मेरे हल्के के कुछ गांवों में पानी बिल्कुल नहीं है। मिट्ठी गांव है, मलिक सालंग साल्हेवास और न जाने कितने ही गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या रहती है। इस बारे में मैंने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को चिट्ठियां भी लिखी हैं। उन चिट्ठियों का जवाब भी मेरे पास आया है जिसमें उन्होंने माना है कि मिट्ठी गांव में 4 दिन तक पानी नही आया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके, माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि चाहे किसी भी तरह से हो, पीने का पानी जरूर पहुचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करती हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्षः अब श्री ओम प्रकाश बेरी बोलेंगे। बेरो साहब आपको एक बात मैं पहले ही क्लीयर कर दू कि आपका नाम चौधरी बंसी लाल जी ने रिकमेंड करके भेजा है, क्या आप उनकी पार्टी की तरफ से बोलेंगे ((विध्न)

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः उपाध्यक्ष महोदय, चाहे उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया है लेकिन मैं एक बान पहले ही बता देना चाहता हू कि मुझे कम से कम एक घंटे का समय मिलना चाहिए। मैं उनकी पार्टी की तरफ से नही बोल रहा।

श्री उपाध्यक्ष: आपको अपने हिसाब से आधे घंटे का समय दिया जा सकता है इसलिये आप अपने समय का ध्यान रखें और ज्यादा समय न लें।

श्री बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इनको भी आपोजीशन से ही समझ लें हमारी पार्टी के बाकी सदस्य 5– 5 या 7– 7 मिनट बोल लेंगे अगर ये कुछ ज्यादा वोले तो इनका टाईम हमारे टाईम में से काट ले। इनको हमारी पार्टी में हा मान लें।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): वे तो इस बात से इन्कार कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश बेरी (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कल वर्ष 1995– 96 के लिये जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और उस पर सदन में परिचर्चा चल रही है, मैं भी इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होने विभिन्न विभागो के लिये योजना खर्च दर्शाया णै, मैं उनके बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा और उनका थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। बिजली के लिये योजना खर्च 261.85 करोड़ रुपये रखे गये है जो बजट का 20.9 परसैंट बनता है, सामाजिक व सामुदायिक विकास की मद में 456.38 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो 36.5 परसैंट बनता है, इरोगेशन एण्ड फल्ड कन्ट्रोल के लिये 248. 36 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो 19.9 परसैंट बनती है। एग्रीकल्चर सम्बधी कार्य के लिये 79.64 करोड़ रुपये की राशि

रखी गई है जो कुल बजट का 7. 2 परसैंट बनती है, ट्रासपोर्ट के लिये 66.54 करोड़ दर्शाया गया है। इसी तरह से इण्डस्ट्रीज पर 56.29 करोड़ रुपये दिखाया गया है। इसमें डेफिसिट दिखा दिया 14.50 करोड़ रुपये जो साल के एण्ड तक बढ़ कर 69 करोड़ रुपये हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, वही धिसी पिटी बाते इस बजट में भी दोहरा दी गई है कि हमें 10 वें फाइनैन्स कमीशन की सिफारिश के आधार पर करों में ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा या कुछ ग्रान्टस मिल जाएंगे।, नान प्लान एक्सपैडिचर को कम किया जायेगा या जो घाटा है, उसको बचत करके पूरा कर त्रिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल वही धिसी पिटी बाते हैं और हर साल यही बातें कह दी जाती है। समझ मे नही आता कि ऐसा क्या करते है। हर साल बजट के बाद नये टैक्स लगा कर हरियाणा की जनता के साथ अन्याय किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय इस डैफिसिट को परा करने? के लिये मै सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि अपने 36 मन्त्रियों की जो फौज खड़ी कर रखी है, उसको कम कीजिए। बोर्डज और कारपोरेशन्न के चेयरमैन्ज को कोई पावर नही है, आई ० ए ० एस० जो एम०डी० है, उनको सारी पावर्ज दे रखी हैं। जो कि काम को ठीक प्रकार से चला सकते है। बोर्ड व निगमों के चेयरमैन नही बनाये जाने चाहिएं। डैफिसिट को पूरा करने के लिए वहीं धिसी पिटी बाते करने का कोई फायदा नही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब तो यह एक रिवाज सा हो गया है कि चाहे यूनियन बजट हो या स्टेट गवर्नमैंट का बजट हो, कहने को तो बजट कर मुक्त होता है लेकिन हर

सरकार बजट पास होने के बाद नये कर लगा देती है, कभीं किसी चीज पर तो कभी किसी चीज पर और इस मामले मे इन्हेंने एक्सैप्शनल बात नही की। इनमें कर लगाने की हिम्मत होनी चाहिए और इस बजट में कर लगाते। इन्होने तो एक तरीका इस्तेमाल कर रखा है कि या तो बजट से पहले या बजट के बाद कर लगा देते हैं। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हू कि विभिन्न विभागों की योजनाओं पर जो खर्चा दिखाया है और जो प्रस्ताव वित्त मन्त्री जी ने किया है, मैं उस बारे मे स्पाट रूप से सरकार के ऊपर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि पहले के वर्षो में भी और आने वाले वर्षों में भी मुझे आशंका है कि यह पैसा उन्ही इलाको में खर्च किया जा रहा है जो मुख्यमन्त्री जी के और इस सरकार के चहेते इलाके हैं। इस प्रकार से पैसा खर्च करने से इस प्रदेश के अन्दर क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है, रिजनल इम्बैलेन्स पैदा हो गया है। इसका उदाहरण मैं विभिन्न विभा गो की चर्चा करते हुए दूगा। सबसे पहले मैं सिचाई विभाग के बारे मे कहना चाहूंगा। मुख्यमन्त्री जी की सरकार जून 1991 में आई थी। उस वक्त ये कहने लगे थे कि उस आदमी का नाम या मुख्यमन्त्री का नाम भजन लाल होगा जो एस० वाई० एल० प्रोजैक्ट पूरा करवाएगा। इन्होंने एलान किया था कि जो एस० वाई० एल० का काम अधूरा पड़ा हुआ है, वह यह सरकार एक साल के अन्दर अन्दर पूरा करवा देगी। (विध्न) उसके बाद 6 महीने की बात कही गई। मैंने बार बार कहा कि मुख्यमन्त्री जी आप कम से कम यह बता दें कि वह साल कौन सी तारीख को शुरु और कौन सी

तारीख को खत्म होगा। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो प्रस्ताव मांगें राम गुप्ता जी ने रखा है, उसमे सरकार ने एस० वाई० एल० के बार में इतना ही कहा है कि हम केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार से एस० वाई० एल० नहर के पंजाब क्षेत्र में आने वाले भाग को शीघ्र पूरा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। इनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है और इन्होने जो खोखले दावे किए थे, वे कतई तौर पर निर्मल हो गए है ओर कतई तौर पर इनकी इसको बनाने की इच्छा शक्ति नही है। ये क्यो नही बनाना चाहते? हमारे जो इलाके है जैसे रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद जिले हैं, इनके साथ राजनैतिक आधार पर नहरी पानी के बटवारे के बारे में काफी अर्से से भेद भाव किया जा रहा है। हमारे पानी का हिस्सा 1977 से चौधरी भजन लाल के जिले मे जा रहा है। सिरसा जिले मे नरवाना सब डिवीजन में जा रहा है। हमारे खेत प्यासे पड़े हुए हैं और हमारे गले सूखे पड़े हैं। आज ये ऐसे हालात हमारे साथ कर रहे हैं। मैंने 12 मार्च 1993 को विधान सभा में एस्टीमेट कमेटी की 25वी रिपोर्ट पेश की थी।

चौधरी जगदीश नेहराः आन ए प्यायंट आफ आर्डर डिप्टी स्पीकर सर, यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं और यह जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वह रिपोर्ट यह है कि लिफ्ट इरीगेशन करके वहां पर पानी ले जाया जाए। एक नहर और बनाई जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यह क्लीयर करना चाहता हू कि

नरवाना लिंक चौनल से जितना हम पानी जमुना में भाखड़ा से ले जा सकते हैं उतना हम ले जा रहे है और इसके अलावा अभी पिछले दिनों नरवाना लिक चौनल की कैपेसिटी 2400 क्यूसिक रह गई थी। हमने उसको रिपेयर करके उसकी कैपेसिटी 3400 क्यूसिक की है और इस पर एक करोड रुपया खर्च किया है। इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी ही नही है। उपाध्यक्ष महोदय जितना पानी वहां सरकार ले जा सकती है और यह सरकार ही नही बल्कि कितनी भी सरकारें रही हैं, यह सिस्टम ऐसा ही है। यह तो ओम प्रकाश बेरी का सस्ती लोकप्रियता लेने का तरीका है कि दक्षिणी हरियाणा के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दक्षिणी हरियाणा मे जो भी 84– 85– 86 में नहरे निकली हैं, वह कांग्रेस ने ही निकाली है और जितना भाखडा का पानी नरवाना चौनल में ले जाया जा सकता है, उतना ही जा रहा है। ये इस तरह के ऐलीगेशन लगाकर सज को गुमराह कर रहे है।

श्री ओम प्रकाश बेरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जरा ध्यान से बात सुनते रहे और जिस ढंग से मैंने सुझाव दिए है, उनका बाद में जवाब दे दें। इस तरह से बीच बीच में इंट्रप्ट न करे। उपाध्यक्ष महोदय, 12 मार्च, 1993 को जो मैंने ऐस्टीमट कमेटी की 25वीं रिपोर्ट पेश की, आज तक सरकार ने उसको क्रियान्वित करने के लिये कोई कदम नही उठाया जब कि साफ तौर पर इस रिपोर्ट मे दर्शाया था की इन इलाकों को 18 लाख एकड़ फुट पानी सिरसा

हिसार तथा नरवाना को दिया जा रहा है और यह पानी राजनीतिक आधार पर उन इलाके को दिया जा रहा है जिनके 1977 से लेकर आज तक मुख्यमन्त्री रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा मे भी पंजाब मे भी और केन्द्र मे भी कांग्रेस की सरकार है इसलिये एस० वाई० एल० का बकाया 15 फीसदी काम आराम से हो सकता है लेकिन सरकार जानबुझकर एम० वाई० एल० के प्रोजैक्ट को नही बनवा रही है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर पानी की चोरी जारी नही रखी जा सकेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय ये डीसिल्टिग की बात करते हैं, नरवाना ब्रांच की कैपेसिटी की. बात करते हैं। सर, मैं इनको नरवाना बाच के बारे में बताना चाहता हू कि इस ब्रांच की सैक्शनड कैपेसिटी 42सौ क्यूसिक की है लेकिन इस ब्रांच मे इतनी सिल्ट जमा हो चुकी है कि आज इसकी कैपेसिटी घटकर ज्यादा से ज्यादा 2600 क्यूसिक ही रह चुकी है। मैं इस बारे में आपको एक सुझाव देना चाहता हू कि सरकार नरवाना ब्रांच की छटाई करवाए और 50 किलो मीटर की लम्बाई तक इसके किनारो को तीन तीन फुट ऊंचा करवा दे। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम कुछ ही करोंड रुपये खर्च करके दो या तनि महीने मे किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो आराम से हमारे इलाको मे भी पानी पहुंच जाएगा और झारे इलाको से पूरा इंसाफ भी हो जाएगा। जिस तरह से आज ये एक महीने मे 24 दिन पानी ले रहे है तो ऐसा करने से दो हफ्ते पानी ये ले सकेंगे और दो हफ्तों के लिये पानी हमारे इलाकों में जा सकेगा। लेकिन सरकार हमारे इलाकों के साथ भेदभाव कर रही है

जो सरकार को नही करना चाहिए। इन्होने सिर्फ डीसिल्टिग के लिये 15 लाख रुपये भाखड़ा मेन लाईन कैनाल के लिये रखे हैं। आज भाखडा मेन लाइन कैनाल की क्षमता 11500 क्यूसिक से घटकर करीब 6 हजार क्यूसिक ही रह गयी है। आज हालात इस तरह खराब हो गए हैं कि इसमें जो राबी न्यास का पानी लेकर आ रहे हैं, वह किस तरह से आएगा। यह पानी सरकार हरियाणा में लाना ही नही चाहती। इसके अलावा ये यमुना के ऐग्रीमेन्ट के बारे में बात करते है।

चौधरी जगदीश नेहराः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कह रहे है तो उसी का खुद कंट्राडिक्शन भी कर रहे है। एक तो ये कह रहे हैं कि सिरसा और हिसार जिलो में पानी ज्यादा जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये यह भी कह रहे है कि भाखड़ा मेन लाईन की कैपेसिटी घटकर 6 हजार क्यूसिक ही रह गयी है। तो यह किस तरह से ऐलीगेशन लगा रहे हैं कि हिसार और सिरसा जिलों में पानी ज्यादा जा रहा है। इनकी दोनों बातों में स्वयं ही कंट्राडिक्शन है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हिसार, सिरसा, कैथल और नरवाना में पानी ज्यादा जा रहा है जबकि दुसरी तरफ खूद ही कह रहे है कि उसकी कैपेसिटी कम हो गयी। ये दोनों ऐलीगेशन किस आधर पर लगा रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश बेरीः उपाध्यक्ष महोदय, ये समझने की कोशिश करे लेकिन डनकी समझ में तो कुछ आता नही है। मैं

कंट्राडिक्शन नही कर रहा हूं बल्कि ये खुद ही कंट्राडिक्शन कर रहे है। मैं तो हरियाणा के इंट्रस्ट मे कह रहा हूं कि आप भाखड़ा मेन लाइन कीं सफाई करवाएं। जब तक एस० वाई० एल० नही बन जाती तब तक भाखड़ा का पूरा पानी लाने के लिये इसका सफा ई करवानी जरूरी है। आपने 18 एम०ए० एफ० पानी के बारे में बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को नरवाना ब्रांच की सफाई करवाकर इसके किनारों को तीन तीन फुट ऊंचा करवाकर हमार इलाको में पानी भेजना चाहिए। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह से ये डीसिल्टिग के बारे में कह रहे हैं कि हम छंटाई करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जे. एस. बी के बारे में सवाल आया था तौ मन्त्री जी ने उस बारे मैं हाउस को गुमराह किया, मन्त्री जी को ज्ञान ही नही है। उपाध्यक्ष महोदय, या तो मन्त्री जी को इस बारे में ज्ञान नही है या फिर इनके ओफिसर इनको गुमराह कर रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैंने उस वक्त भी कहा था और अब भी. कहता हूं कि बांकरा हैड के बाद पिछले कई महीनों से जे० एस० बी ० में कतई तौर पर पानी नही डाला जा रहा है और बहुत से गांव पीने के पानी से और नहरी पानी से वचित किए जा रहे हैं जबकि उनसे आबियाना वसूला जा रहा पैं। उपाध्यक्ष महोदय, जे ० एस० वो ० नहर में बहुत बड़े बड़े कीकर के दरख्त खड़े हुए है और 6–7 फुट ऊंची सिल्ट उसमें जमा हो चुकी है। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस नहर की छंटाई करवाए, सफाई करवाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह इलाका भी इसी प्रदेश का इलाका

है, इसीलिये सरकार को इस इलाके के साथ भी इंसाफ करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक उन इलाकों के लिये पानी नहीं भेजा जाता जे ० एस० बी ० की सफाई नहीं हो जाती तब तक उन इलाको के गांव वालों से आबियाना नही लिया जाना चाहिए तथा जे० एल० एन ० कैनाल से आलटरनेटिव अरेजमैन्ठ करके सिंचाई और पीने का पानी मुहैया करवाया जाना चाहिए। सर, यह तो सरकार का दायित्व बनता है सरकार डीसिल्टिग के बारे में कागजों में आकड़े तो दे देती है कि हमने इतनी डीसिल्टिग करवायी लेकिन मौके पर जा कर देखो तो कतई तौर पर भी सफाई नही होती है। मैं मार्च 1993 के महीने में पूरे हरियाणा मे गया था। मैंने भिवानी जिले में, रिवाड़ी जिले में और महेन्द्रगढ़ जिले में नहरों की और पम्प हाउसिज की जो हालत देखी उसको देखकर मुझे रोना आता है कि हरियाणा की सरकार उन लोगों के साथ क्यो ऐसा बिहेव कर रही है क्यों ज्यादती कर रही है? 1986– 87 में जब चौधरी बस। लाल जी प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने थे तब इन्होंने हुक्म दिया था कि पावर हाउसिज को एनरजाइज कर दीजिए। 28 एनरजाइज कर दिए गए थे, बाकी 30– 35 पावर हाऊस की तरफ आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पम्प हाउसिंज में 7–7 फुट गाद जमा है, उन इलाको मे पीने के पानी की समस्या है, सरकार खोखले दावे करती है कि हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराया है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बोलते हुए 10 मिनट ही हुए है। मुझे तो अभी बहुत बोलना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सीपेज की प्रौबलम है, हमारे

इलाके के अन्दर जवाहर लाल नेहरु नहर और जे० एस० वी ० पैरेलल चलती है, वहां पर 15–20 साल से पानी के रिसाव की गंभीर समस्या है। लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1992 में सरकार ने मेरे हल्के के लिए एक स्कीम पेश की थी। यह स्कीम 73 लाख रुपये की थी लेकिन ऐसी स्कीम मंजूर करने से क्या फायदा जिसके लिए फड प्रोवाइड नही किया जाता। मंत्री जी का हल्का रोड़ा है, उस इलाके की सीपेज की समस्या को हल करने के लिए मुख्यमन्त्री जी ने शुभारम्भ कर दिया क्योंकि वह मन्त्री जी का हल्का था। पिछड़ इलाकों को तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, जानबूझकर उन इलाको के साथ ज्यादती की जा रहा है। सीपेज को प्राब्लम की वजह से 50 हजार किले भूमि 15 साल में बरबाद हो चुकी है, उन किसानों को राहत दी जानी चाहिए। सीपेज की प्रॉब्लम परमानैन्टली हल की जानी चाहिए। यमुना जल के बारे में भी चौधरी भजन लाल जी ने हाउस में आश्वासन दिया था कि यमुना के बारे मै जब कोई ऐग्रीमैंट होगा, उस एग्रीमैंट पर दस्तखत करने से पहले पूरे सदन को विश्वास में लिया जाएगा लेकिन हमें तो विश्वास में लेना दरकिनार अपने मन्त्रिमण्डल को भी विश्वास में नही तिया और यमुना जल समझौते पर दस्तखत कर दिए। जिससे मोटे तौर पर हरियाणा का 20 फीसदी पानी कम हो गया। दिल्ली, यू०पी ०, हिमाचल और राजस्थान को पानी दे दिया गया बै। मुख्य मन्त्री जी कहने है कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को पीने का पानी चाहिए। पीने का पानी मिलना चाहिए लेकिन यह अकेंले हरियाणा की

जिम्मेदारी नहीं है, पंजाब से भी लेना चाहिए, यू०पी ० औंर राजस्थान से भी लिया जाना चाहिए। अकेला हरियाणा क्यों दे? 1954 के समझौते के मुताबिक खरीफ की फसल में हरियाणा का 77 परसैंट, यू०पी० का 23 परसैंट, रबी के वक्त हरियाणा का 73 परसैंट और यू०पी ० का 27 परसैंट। अगर पानी ज्यादा पड जाए और 10900 क्यूसिक पानी आ जाए तो हरियाणा का 67 परसैटं और यू०पी ० का 33 परसैटं होता था। इस नये समझौते के आने की वजह से वह घटकर 47.8 परसैंट हो गया है, जो मैंने एम०ओ०यू० पढ़ा है उसके मुताबिक। गड़बड़ तो यह है कि सरकार उस एग्रीमैंट को हाउस में पेण नहीं करना चाहती। क्या हालात हैं जिससे इस समझौते को छिपाया जा रहा है। इस तरह से कोई काम चलने वाला नहीं है। कंपट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की 31 मार्च, 1992 की जो रिपोर्ट है, इसमे लिखा है कि वैस्ट यमुना सिस्टम में ज्यादा पानी चले, इसकी क्षमता बढ़े। पानी जो समुद्र में पहुंच जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, उस स्कीम पर न तो इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है और है न ही पहले किया गया था। वह क्या स्कीम थी, मै आपको पढ़कर सुनाता हूं:–

"The scheme envisaged bringing water from Tajewala to MunakHaad (Karnal District) through existing WJC system by adding one additional bay at Tajewala for raising its capacity by 1603 cusecs and remodelling of the Main Line Upper and Main Line Lower canals for increasing carrying capacity by 1600cusecs and 1350 cusecs respectively. No work

had, however, been carried out far increasing the carrying capacity. From Munak Head, water was to be carried though Deihi Parallel Branch from which supply was delivered to JLN Feeder off taking at RD 145-50. Delhi Parallel Branch was remodelled to a designed capacity of 5156 cusecs upto RD 145250 during 1969-70 to 1986-87 at the cost of Rs. 687 lakhs. The total required capacity at RD 145250 of Delhi Parallel Branch was 7076 cusecs for feeding off taking channels (Delhi Parallel Branch down stream RD 145250 : 1783 cusecs, Bhalaut Sub Branch : 2052 cusecs and JLN Feeder : 3241 cusecs) against the designe I capacity of 5156 cusecs. The quantity of water actually released in Delhi Parallel Branch during July to September each year from 1982 to 199.2 ranged between 301 and 4302 cusecs while the actual quantity of water released in JLN Feeder after meeting downstream requirement of Delhi Parallel Branch and Bhalaut Sub Branch rarged between 60 cusecs and 1200 cusecs. Thus, the failure to increase the carrying capacity of existing WJC system and insufficient capacity of Delhi Parallel Branch resulted in short delivery of water in JLN system"

इस स्कीम की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, इन हल्कों कैं साथ सरकार ने पूरा भेदभाव बरता है। फिर. सरकार कहती है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। कम से कम इस बजट में तो इसके लिये कोई प्रावधान किया जा सकता था।

डिप्टी स्पीकर साहब, दादूपुर नलवी की एक स्कीम जोकि 1984 से मन्जूरशुदा है। आज 1984 से 1995 आ गया है, इस स्कीम से कुरुक्षेत्र अम्बाला और यमुनानगर जिलों को फायदा

होना चाहिए था लेकिन सरकार ने न ही इस बजट में इस के लिए प्रावधान किया है और न ही पिछले बजट में प्रावधान किया था। उस इलाके के लोग पानी को तरस रहे है। यमुना इन इलाको के पास से गुजरती है लेकिन दादूपुर–नलवी स्कीम पर अमल न होने के कारण उन इलाकों के लोगों को पीने के पानी से व सिचाई से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है। अभी सरकार ने यमुना के बारे में अपर रिवर यमुना बोर्ड बनाना मन्जूर कर लिया है, बना भी दिया है। रावी–व्यास व भाखड़ा के मैनेजमैंट का जो बोर्ड बना था, उसमें जो स्टेट्स–बैनीफिशरीज होती थीं, वे सारी की सारी उसकी मैम्बर थी और सेन्टर का एक नुमाइंदा उसका अध्यक्ष होता था। प्रेक्टीकल रूप से आज पंजाब सरकार का बी ०एम ०बी ० पर पूरा कंट्रोल है लेकिन आगरा कैनाल की क्या स्थिति है 7 वह हरियाणा से गुजरती है लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल यू ०पी ० सरकार का है। इसका कंट्रोल लेने के लिए आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नही की कुए। इस बारे में, मैं यह कहूंगा कि सरकार पानी के मामले मै कोई खास चितित नही है क्योंकि जिस इलाके के मुख्यमन्त्री बनते रहे हैं, उन इलाको में पानी बाकायदा पहुच रहा है और वह भी शेष इलाकों को पानी देने के लिये तैयार नही है, यह कितनी गल्त परम्परा डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं स्प्रिंकलर सैट्स के बारे मे भी कुछ कहना चाहूंगा। यह स्कीम 1974 के बाद इट्रोड्यूस की गयी थी। जब चौधरी बंसीलाल जी डस प्रदेश के मुख्य मन्त्री हुआ करते थे तो इन्होंने ऐग्रीकलचर इम्पलीमैंट्स पर दरांती मे लेकर कम्बाईड

हारवैस्टर तक के ऊंपर मे सेल्ज टैक्स बिल्कुल माफ कर रखा था। एक तो इस सरकार ने हमारा पानी छीन लिया, दूसरे अगर किसी तरह से हम स्प्रिकलर सैट्म लगाकर थोडा बहुत खेती मे पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं तो स्प्रिंकलर सैट्स पर इस सरकार ने 8. 8 परसैन्ट सेल्ज टैक्स लगा रखा है। इससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। इस बारे में, मैंनै कई बार अनुरोध भी किया है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश व राजस्थान की सरकारों ने स्प्रिंकलर सैट्स को कर–मुक्त कर रखा है, उसी प्रकार इस सरकार को भी स्प्रिकलर सेटस को कर– मुक्त कर देना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिये। किसान विरोधी काम नहीं करना चाहिए। 8. 8 परसैन्ट जो सेल्ज टैक्स स्प्रिकलर सैट्स पर है, उनका कर–मुक्त कर देना चाहिए ताकि शराब आदमी की, गरीब किसानों को मदद की जा सके। इसके साथ–साथ मैं बिजली के बारे में भी थोडा सा कहना चाहूंगा। (घंटी) डिप्टी स्पीकर, इस तरह से आप बार–थार घंटी बजा रहै है, मैंने तो अभी स्तुत बोलना है। (शोर)

श्री बंसीलालः डिप्टी सरकार साहब, 1 बजकर 6 मिनट पर इन्होने बोलना शुरु किया था। बी ०ए०सी ० की मीटिंग में यह तय हुआ था कि दोनों तरफ में दो–दो मेन स्पीकर्ज आधा–आधा घण्टा बोलेंगे। और बाकी बोलने वाले 5– 6 मिनट में अपने हल्के की बात कह लेंगे। कल शाम में और आज में कोई फर्क षड़ु गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन तय यही हुआ था। 1.36

बजे तक तो आप इनको कुछ कहो मत, बोलने दें। जो इंटरफीरैन्स होती है, उसकी वजह से टाइम बढ़ाना होगा।

श्री ओम प्रकाश बेरी: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इररैलवैन्ट कभी नहीं बोलता जब मैं बोल लूंगा तो मैं खुद ही कह दूगा। तो मैं बिजली के बारे में कह रहा था। पानीपत और फरीदाबाद थर्मल प्लांट्स की जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी जो आज एं, वह 32 और 35 परसैन्ट है, इसमे ज्यादा बिजली वहां पैदा नहीं की जा सकती। मेरा एक सुझाव है कि अगर इन थर्मल प्लांट्स की सुचारू रूप से चलाने की क्षमता नही है तो इनको एन ०टी ०पी ० सी ० के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि यह क्षमता बढ़कर 70– 75 परसैंट हो जाए और प्रदेश को ज्यादा बिजली मिल सके।

इसके अलावा जो लाईन लामिज हैं, वे नैचुरल–वे में केवल 15 परसैटं ही होने चाहिए लेकिन आज 40 से 45 परसैट बल्कि 50 परसैंट तक लाईन लासिज है और बिजली की चोरी बड़े योजनाबद्ध तरीके से हो रही णै। बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार कोई प्रबन्ध करे ताकि लोगो की सारी समस्याएं दूर हो सके। इसके इलावा, मैं बताना चाहता हूं कि बिजली के बारे में, वर्ष 1995– 96 मे योजना के खर्चे पर 261 करोड़ 85 लाख रुपये दिखाये है। मैं वित्तमन्त्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि वे पिछले 10– 15 सालो के पूरे बजट उठा कर देख लें, हर साल

कमी डेढ़ सौ करोड़ रुपया, कभी 200 करोड़ रुपया योजना के खर्चे पर बिजली के बारे में खर्च करने की बात कही है। लेकिन कितना खर्चा योजनाओ पर किया गया इन 15 सालों के बीच मे, ये वह स्वय देख लें। क्या यह बात सही नही है कि योजनाओ के खर्चे को डाइवर्ट करके नान–प्लान एक्सपैन्डीचर में डाल दिया जाता है और किसी किस्म का कोई खर्च योजनाओं पर नही किया जाता ?

श्री उपाध्यक्षः बेरी साहब, आपका टाइम हो गया है।

श्री ओम प्रकाश बेरीः सर, यह तो बहुत लम्बा मामला है। मैं तो सरकार को अच्छे सुझाव दे रहा हूं।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह बात हुई थी कि आध–आध घटा दो मेन स्पीकरों को मिलेगा। मुख्य मन्त्री जो ने इस बात को ऐग्री किया था तो आप इनको आध घंटा तो बोलने दें।

बैठक का समय बढ़ाना

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, ये 24 मिनट बोल चुके हैं इसलिए आप 6 मिनट के लिए बैठक का समय और बढ़ा दे।

श्री उपाध्यक्षः यदि हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष: बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1995–96 के बजट पर सा मान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश बेरी: तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि जो योजना के लिए प्रावधान है, आप 15 साल का पुराना बजट उठा कर देख लें, उस पर कोई पैसा खर्च नही किया गया बल्कि उसको नान प्लान मे डाल देते है। इसी वजह से आज बिजली बोर्ड का घाटा साढ़े सोलह सौ करोड रूपया हो गया है। दिल्ली की सरकार ने 1976 में यमुना नगर के लिए एक सुपर थर्मल प्लांट लगाने की मन्जूरी दी थी और उसके लिए 600 एकड़ जमीन भी एक्वायर की गई थी लेकिन उस पर अमल नही किया गया। आज इन्होंने इजराइल की कम्पनी आइजनवर्ग से समझौता किया है। ये कहते हैं कि हम कंज्यूमर को 1.92 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देगे। पता नही थर्मल प्लांट लगने के बाद उसका कितना खर्चा बढ़ जाएगा? मेरे हिसाब मे कंज्यूमर को कम से कम साढ़े तीन रुपए या चार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। इसके लिए मैमोरैडम आफ अंडर स्टैडिंग है जिसको सदन में रखना चाहिए था ताकि मैम्बर्ज को पता चल जाता कि वह किस आधार व शर्तो पर हुआ है।

इसी प्रकार से मै अपनें इलाके के बारे मे भी कुछ कहना चाहता हूं। यह जो एक्स्प्लेनेटरी मैमोरैडम आन दि बजट पेश किया गया है, इसकी किताब के पेज 105 पर लिखा है कि जिन किसानों को ट्यूबवैल की बिजली के लिए राहत दी गई है, यानी जिन इलाकों को ट्यूबवैल के मामले मे बिजली के रेट्स की राहत दी गई है, इसमें वह इलाका दर्शाया गया है जिसको 44 रुपए प्रति बेसिक हार्स पावर की दर से ट्यूबवैल को बिजली दने का प्रावधान किया गया है। उसमें इलाके हैं तहसील दादरी, भिवानी, लोहारु तहसील और नाहडु। सब तहसील नाहडू, सब–तहसील के कुछ इलाके रिवाड़ी जिले में चले गए और कुछ मातनहेल सब–तहसील जो झज्जर मे पड़ती है, उसमें चरने गए। तो मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हू कि जो गांव पुरानी नाहडु तहसील के थे, उन सब को यह सस्ती बिजली की सुविधा दो। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के बाद उनके वाटर टेबल में कोई चेंज नही आई है।

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात हमारे सामने आई थी। बोर्ड उसको एग्जामिन कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम जरूर उनको रिलीफ देंगे।

श्री ओम प्रकाश बेरी: उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में ट्रांसफारमर प्रियारिटी के हिसाब से बदला जाता है लेकिन मैं अपने हल्के की बात कहता हू कि वहां पर 15 दिन से लेकर एक महीने तक इसको बदला जाता है। कम से कम इस किस्म की बात तो

इनको नही करनी चाहिए। बिजली के मामले मे इन्होने एक सैल्फ फाइनैंसिग स्कीम चलाई है। इसमे गरीब किसान 26–30 हजार रुपए कहां से देगा मैं चाहता हू कि इसको खत्म किया जाए और जो आपने 11 हजार ट्यूबैल्व को कनैक्शन देने का टारगैट बनाया बै, उनमे अधिकतर कनैक्शन रिवाड़ी, महेन्द्र– गढ़, भिवानी और झल्का– तहसील के लोगों को प्रयारिटी के हिसाब से दिए जाने चाहिएं। इसी तरह से मैं रोड्ज के बारे मे कहना चाहता हू। इनकी कागजों में तो बेशक रिपेयर हो गई होगी लेकिन प्रैक्टीकली नही हुई है। मैं आपको सड़को के नाम बताता है। एक तो झज्जर से कोसली है, झज्जर से गुडियानी, साम्पला, झज्जर, बेरी दुबलधन तथा बेरी से सांपला। इन सड्कों की हालत इतनी खराब है कि आप आख बन्द करके गाड़ी मैं बैठ जाएं। जब इनमें से किसी भी सड़क पर गाड़ी पहुंचेगी तो आपको पता लग जाएगा कि वह सड़क आ गई है। रोडज के बारे में हमारे इंजीनियर्ज काफी सक्षम है। हमारे इंजीनियर्ज से एक्सप्रैस हाई–वे बनवाने की बजाए, मलेशिया की एक फर्म को बनाने का ठेका दिया है। वह फर्म उसको बनाएगी। क्या मलेशिया के इंजीनियर्ज ज्यादा अच्छे है? क्या हमारे देश के इंजीनियर्ज पर सरकार को भरोसा नही है, इसलिए इस सरकार ने उसको बनाने के लिए मलेशिया की फर्म के साथ समझौता किया है? हमारे इंजीनियर्ज के साथ यइ बड़ी भारी ज्यादती है। डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा–सा कहना चाहूंगा। जो 50 किलोमीटर तक की लम्बाई के रूट परमिट प्राइवेट लोगों को दिए गए थे, उनके बारे में हमारा

बड़ा भारी बिटर एक्सपीरियंस हो गया है। जिन लोगों को जिन रूट्स के परमिट दिए गए थे, वे उन रूट्स पर बसें चलाने की बजाय हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर से मिल करके पुलिस वाली से मिल करके और सचिव आर०टी ०ए० से मिल करके जो वायबल रूट्स है, उन पर अपनी बसें चला रहे है। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पब्लिक के साथ बड़ी भारी ज्यादती हो गई है क्योकि जिन रूट्स के परमिट प्राइवेट आप्रेटर्ज को दिए गए थे, उन रूट्स से हरियाणा रोडवेज की बसें विदड्रा कर ली गई हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह दोहरी मार पड़ गई।

श्री उपाध्यक्षः बेरी साहब अब आप अपनी स्पीच समाप्त करे। आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री ओम प्रकाश बेरीः डिप्टी स्पीकर साहब, आप कम से कम हाउस का 15 मिनट टाईम बढ़ा दें। मुझे बातें तो कहनी ही हैं।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, बी ०ए०सी ० की मीटिग में यह बात आई थी कि अगर जरूरत पड़े तो हाउस का टाईम आधा घंटा बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आप इनको बोलने के लिए 15 मिनट का टाईम और दे दें।

चौधरी भजन लालः इसीलिए हमने सैशन दो दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इस समय हाउस का टाईम घंटा आधा घंटा बढ़ा ने के क्या मायने हैं? (शोर)

चौधरी बंसी लालः माननीय सदस्य यह कह रहे है कि इनको 15 मिनट और बोलना है। आपने इनके 5– 7 मिनट तो शोर करके ही खराब कर दिए। Let him remain on hes legs कल ये 15 मिनट और बोल लेंगे। कल ये जो 15 मिनट बोलेंगे वह मेरे टाईम में से आप काट लेना।

चौधरी भजन लालः नही, यह सवाल ही पैदा नही होता। वह आधा घंटा बोल चुके हैं।

चौधरी बंसी लालः बी ०ए०सी ० की मीटिंग में सारी बात हुई हैं। I am not speaking beyond the scope of the discussion, which took place in the Business Advisory Committee meeting.

श्री उपाध्यक्षः यदि हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 3 मिनट और दम दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है जी, 3 मिनट से ज्यादा न बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्षः बैठक का समय 3 मिनट और बढ़ाया जाता है। Please wind up within two minutes.

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री प्रकाश बेरी: डिप्टी स्पीकर साहब, दो मिनट में तो मेरी बाते। पूरी नही होगी। मैं ट्रासपोर्ट के बारे में कहू रहा था कि लोगो को सहुलियते देने के लिए प्राइवेट आप्रेटर्ज और हरियाणा रोडवेज की बसो के बीच में कम्पीटीशन चलाना चाहिए ताकि लोगो को सहुलियत मिल सके। हरियाणा रोडवेज की जो बसे है और जिन रूट्स पर प्राइवेट लोगों को परमिट दिए गए हैं, उन रूट्स पर चल रही है, उनको विदड्रा नही करना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहुलियत मिलतीं रहे। मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा और बेशक सरकार इस बारे मे इंक्वायरी कर ले कि जिन लोगों को जिस रूट के परमिट मिले है, वे लोग उन रूट्स पर अपनी बसें न चला करके, दूसरे रूट्स पर चला रहे है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊंगा कि शेरिया से बहादुरगढ़ का परमिट मिला हुआ है और बिरधा ना से बहादुरगढ़ का परमिट मिला हुआ है लेकिन वे बस चलाने हैं बेरी से बहादुरगढ। मैं एक बात और ट्रासपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहा रोहतक मै हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर पिछले 6 साल से बैठे है। वह जनरल मैनेजर किस तरह से लोगो के साथ जुल्म ढा रहे कुए, उसकी कहानी मैं आपको बताऊगा। वहां के एम्पलाइज ने आपस मे मिल कर उस जनरल मैनेजर के खिलाफ सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था कि उसकी इक्वायरी

होना चाहिए। कोई भी हरियाणा रोडवेज का जनरल मैनेजर कही पर भी 6 साल मे नही बैठा होगा लेकिन रोहतक में बैठा है।

Mr. Deputy Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 a.m., tomorrow.

13.38

(The Sabha then *adjourned till 9:30. a.m. on Wednesday, the 15th March, 1995.)